TOPPERS CLUB
IAS ACADEMY

₹ 49/-

Dec-25

Monthly CURRENT AFFAIRS

By - Toppers Club

Er Dev Pratap Singh
Director

Contact Us →
+91 6388671098
dpsctc@gmail.com
www.topperclubiasacademy.in

IAS | IPS | PCS | IFS | IRS & OTHER COMPETITIVE EXAMS

नीतीश कुमार
बिहार के CM 10वीं बार

निठारी कांड
सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रोक सका कोली की रिहाई

जस्टिस सूर्यकांत
भारत के 53वें
चीफ जस्टिस बने

ड्रग-सेफ्टी का बढ़ता संकट
भारत का ज़हरीला कफ सिरप हादसा

एंटी-पॉलीगैमी बिल 2025
असम कैबिनेट ने मंजूरी दी

क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी
यूनेस्को द्वारा घोषित – **लखनऊ**

केंद्रीय बीज विधेयक 2025
पुराने बीज कानूनों को बदलने के लिए

आईएमएफ ऋण
2025 में बढ़ता ऋण संकट: विस्तृत व्याख्या

तुवालु
बढ़ते जलवायु खतरों
के बीच आईयूसीएन का
90वाँ सदस्य बना

8TH
वेतन आयोग गठित
जानें इसके बारे में
महत्वपूर्ण बातें

Toppers Club IAS Acacdemy
All Copyright Reserved

Contact Info:
Phone No: +91 6388671098
Mail: dpsctc@gmail.com
Website: www.topperclubiasacademy.in

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT
ALL RIGHTS RESERVED

अस्वीकरण

यह पुस्तक विशेष रूप से शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। लेखक(ों) द्वारा यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है कि किसी भी मौजूदा कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन न हो। यदि किसी स्रोत का अनजाने में उल्लेख नहीं किया गया है या किसी प्रकार का अनचाहा उल्लंघन हुआ है, तो कृपया प्रकाशक को लिखित रूप में सूचित करें ताकि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जा सके।

हालाँकि सामग्री की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा की गई है, फिर भी अनजाने में कुछ त्रुटियाँ या चूक हो सकती हैं। किसी भी पाई गई विसंगति को आगामी संस्करणों में ठीक किया जाएगा। लेखक(ों), प्रकाशक और वितरक इस पुस्तक में दी गई जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कानूनी, तथ्यात्मक या महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोतों से परामर्श करें।

बाइंडिंग में दोष, प्रिंटिंग में त्रुटि या पृष्ठों की कमी जैसी समस्याओं के मामलों में प्रकाशक की ज़िम्मेदारी केवल उसी या समकक्ष संस्करण की दोषपूर्ण प्रति के प्रतिस्थापन तक ही सीमित है। प्रतिस्थापन के लिए अनुरोध खरीद की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इससे संबंधित सभी लागतें, जैसे कि शिपिंग, क्रेता द्वारा वहन की जाएंगी।

सर्वाधिकार सुरक्षित

इस प्रकाशन के किसी भी भाग को बिना प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी रूप में—चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोग्राफिक या अन्य कोई माध्यम हो—प्रतिलिपि, संग्रह या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। बिना अनुमति के उपयोग, पुनरुत्पादन या वितरण के परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

लेखक इस कृति की मूल सामग्री पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, सिवाय उन उद्धरणों के जहाँ उपयुक्त अनुमति के साथ स्रोत का उल्लेख किया गया है। यह प्रकाशन किसी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है, और इसमें कोई मानहानिकारक सामग्री सम्मिलित नहीं है।

प्रिय अभ्यर्थियों,

"देश का भविष्य वही गढ़ते हैं, जो परीक्षा से बहुत पहले अपने मन और प्रयासों में अनुशासन लाते हैं।"

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी एक परिवर्तनकारी यात्रा है—जिसमें अनुशासन, जिज्ञासा और दुनिया की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। तैयारी के सभी पहलुओं में, करंट अफेयर्स से लगातार जुड़े रहना सबसे प्रभावी साधन है। यह विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत करता है, अवधारणाओं को स्पष्ट बनाता है और उत्तर लेखन को अधिक परिपक्व दृष्टिकोण देता है, जिससे अभ्यर्थी भविष्य के प्रशासकों की तरह सोचना सीखते हैं। जैसा कहा गया है, "आज की आपकी निष्ठा ही उस भारत का निर्माण करती है जिसे आप कल नेतृत्व देंगे।" यह अंक आपकी उसी निष्ठा का साथी बनने के लिए तैयार है।

इस माह का संकलन भारत के प्रशासनिक परिवर्तनों, संवैधानिक बहसों, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक घटनाक्रमों को समेटता है। भारत में जहरीली कफ सिरप की लगातार होती घटनाएँ दवा नियमन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती हैं। निठारी कांड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह भी दिखाया कि कोर्ट कोली को जेल में बनाए रखने में क्यों असमर्थ रही—यह आपराधिक न्याय व्यवस्था और प्रक्रिया संबंधी न्याय पर महत्वपूर्ण विमर्श को जन्म देता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाएँ भी केंद्र में हैं। नीतीश कुमार का दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना राज्य राजनीति और गठबंधन रणनीतियों की जटिलताओं की ओर संकेत करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, न्यायमूर्ति सुर्या कांत की भारत के 53 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति न्यायपालिका की नेतृत्व संरचना में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहीं असम कैबिनेट द्वारा एंटी-बहुविवाह विधेयक 2025 को मंजूरी दिए जाने से व्यक्तिगत कानूनों और विधायी सुधारों पर नई चर्चाएँ खुलती हैं।

आर्थिक और नीति संबंधी मुद्दे भी इस संस्करण में प्रमुख हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ते आईएमएफ ऋण एक चिंताजनक अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट की ओर इशारा करते हैं। देश के भीतर, केंद्र द्वारा तैयार किया गया सीड्स बिल 2025 पुराने बीज कानूनों को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका प्रभाव किसानों, जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है, जिसके व्यापक वित्तीय और शासन संबंधी प्रभाव होंगे।

वैश्विक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ भी इस महीने की विशेषता हैं। तूवालु का आईयूसीएन का 90वाँ राज्य सदस्य बनना छोटे द्वीपीय देशों पर बढ़ते जलवायु संकट को रेखांकित करता है। वहीं भारत के लिए गर्व का क्षण तब आया जब लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया, जिसने इसकी समृद्ध पाक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है।

इन पृष्ठों को पढ़ते समय याद रखें कि जागरूकता ही सार्थक नेतृत्व का पहला कदम है। आप जो भी तथ्य सीखते हैं, जो भी मुद्दे समझते हैं, और जो भी दृष्टिकोण विकसित करते हैं, वे सब आपको उस प्रशासक के और करीब ले जाते हैं, जो आप बनने की आकांक्षा रखते हैं। आशा है, यह संस्करण आपके संकल्प को मजबूत करेगा, आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएगा और आपको राष्ट्र सेवा के अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा।

गहराई से सोचो. और मेहनत करो. राष्ट्र सेवा के लिए उठ खड़े हो।

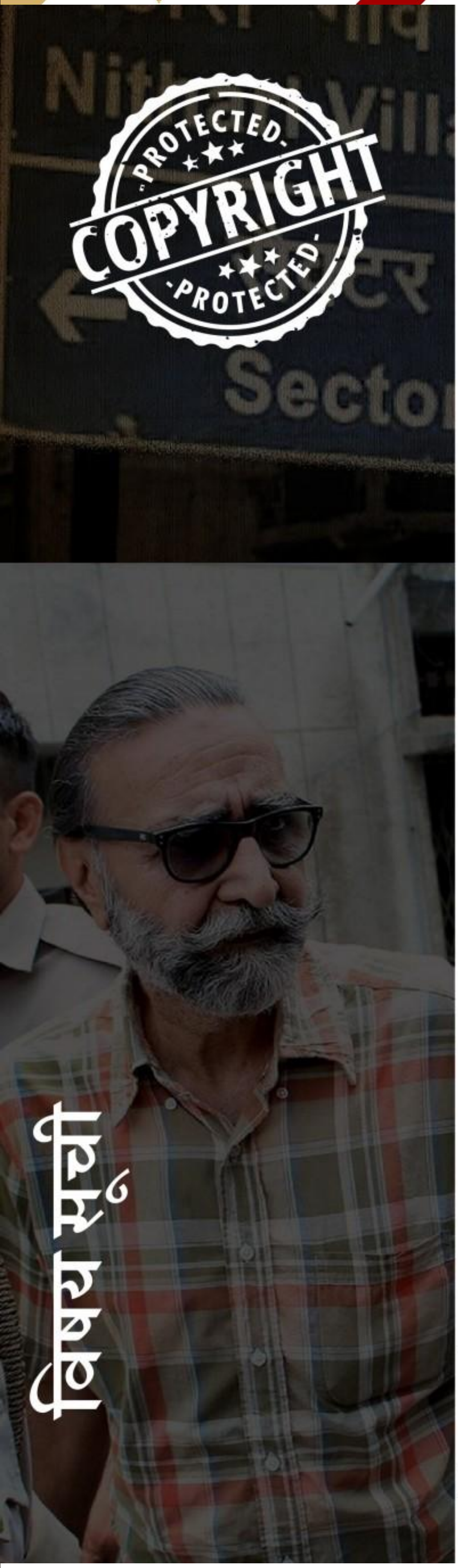

इस संस्करण में शामिल हैं

1.	नियुक्तियाँ	5
2.	राजतन्त्र एवं शासन	14
3.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ	18
4.	अर्थव्यवस्था एवं व्यापार	25
5.	रक्षा एवं सुरक्षा	34
6.	सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ	46
7.	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	49
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	53
9.	संस्कृति एवं इतिहास	61
10.	खेल-कूद	67
11.	निधन	73
12.	परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण दिन	77
13.	पुस्तकें एवं लेखक	78

बिजनेस न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमी न्यूज, पॉलिटिक्स न्यूज, इंडिया न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज एवं कई अन्य विषयों को कवर किया गया ......

समाचार साभार

बीबीसी, रॉयटर्स, अल जज़ीरा, पीआईबी, पीटीआई, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिज़नेस लाइन, इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल एवं अन्य सभी प्रमुख समाचार पत्र

नियुक्तियाँ

नीतीश कुमार ने 10वीं बार CM पद की शपथ ली

JD(U) प्रमुख नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

NDA नेता के तौर पर सर्वसम्मति से चयन

कुमार को JD(U) और NDA दोनों विधायक दलों का नेता सर्वसम्मति से चुना गया, जिससे नई सरकार का रास्ता साफ हो गया।

BJP ने लीडरशिप को अंतिम रूप दिया

BJP ने विधायकों के सर्वसम्मति से समर्थन से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना।

2025 का निर्णायक चुनावी जनादेश

NDA ने 243 में से 202 सीटें जीतीं, 2010 के बाद यह दूसरी बार है जब 200 सीटों का आंकड़ा पार किया; कुमार ने दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की।

NDA में सीटों का बंटवारा

BJP ने 89 सीटें जीतीं, JD(U) ने 85, LJP (RV) ने 19, HAM(S) ने 5, और RLM ने 4।

विपक्ष का प्रदर्शन

RJD ने 25 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 6, CPI(ML)L ने 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने 1, CPI(M) ने 1, AIMIM ने 5, और BSP ने 1।

1951 के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग

दो फेज़ के चुनाव में 67.13% वोटिंग हुई, जिसमें महिला वोटरों (71.6%) ने पुरुषों (62.8%) को पीछे छोड़ दिया।

बिहार

- राजधानी: पटना
- गवर्नर: आरिफ मोहम्मद खान
- पक्षी: हाउस स्पैरो
- ज़िले: 38

R&AW चीफ पराग जैन को सेक्रेटरी (सिक्योरिटी) का एडिशनल चार्ज दिया गया

केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के चीफ पराग जैन को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी (सिक्योरिटी) अपॉइंट किया है। यह ऑर्डर अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ़ द कैबिनेट (ACC) ने जारी किया है। जैन अपने मौजूदा रोल के अलावा इस पोस्ट पर तब तक रहेंगे जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता या आगे कोई ऑर्डर जारी नहीं हो जाता।

पराग जैन के बारे में

पराग जैन पंजाब कैडर के 1989 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) ऑफिसर हैं। वह अभी R&AW के हेड हैं, जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर काम करती है।

सेक्रेटरी (सिक्योरिटी) का रोल

सेक्रेटरी (सिक्योरिटी) स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज को देखता है — यह एलीट सिक्योरिटी एजेंसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है। यह पोस्ट VIP सुरक्षा के लिए अलग-अलग सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन पक्का करती है।

अपॉइंटमेंट का बैकग्राउंड

हरिनाथ मिश्रा (1990-बैच के IPS ऑफिसर) के रिटायरमेंट के बाद 31 जुलाई, 2025 से सेक्रेटरी (सिक्योरिटी) का पद खाली था। इससे पहले, सरकार ने 14 जून, 2025 को केरल कैडर के ऑफिसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्पेशल डायरेक्टर आरए चंद्रशेखर को इस रोल के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन बाद में ऑफिस संभालने से पहले उन्हें केरल DGP बना दिया गया था। तब से, सेक्रेटरी (कोऑर्डिनेशन) मनोज गोविल एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे।

मुख्य इंस्टीट्यूशन के बारे में

- R&AW (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग): 1968 में बनी, यह भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो विदेशी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है।
- SPG (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप): PM इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में बनी; यह भारत के प्राइम मिनिस्टर को करीबी सिक्योरिटी देती है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी (ACC): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यह सेक्रेटरी और डायरेक्टर सहित टॉप-लेवल के ब्यूरोक्रेट के अपॉइंटमेंट को मंज़ूरी देती है।

नोट: SPG एक्ट में 2019 में बदलाव किया गया था, जिससे SPG सुरक्षा सिर्फ़ मौजूदा प्रधानमंत्री तक ही सीमित हो गई।

अपराजिता सारंगी को ज़रूरी अमेंडमेंट बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया

BJP MP अपराजिता सारंगी को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह कमेटी तीन ज़रूरी बिलों —

संविधान (130वां अमेंडमेंट) बिल, 2025,

जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइज़ेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025, और

केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (अमेंडमेंट) बिल, 2025 — की जांच के लिए बनाई गई है।

कमेटी की बनावट

कमेटी में 31 सदस्य हैं:

1. BJP से 15,
2. NDA के सहयोगियों से 11,
3. विपक्ष से 4, और
4. 1 नॉमिनेटेड सदस्य।

BJP के जाने-माने सदस्यों में रविशंकर प्रसाद, पुरुषोत्तमभाई रूपाला, अनुराग ठाकुर और बृज लाल शामिल हैं। राज्यसभा की नॉमिनेटेड सदस्य सुधा मूर्ति भी इस कमेटी का हिस्सा हैं।

विपक्ष का प्रतिनिधित्व

कमेटी में विपक्ष के प्रतिनिधियों में सुप्रिया सुले (NCP), हरसिमरत कौर बादल (SAD), असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM), और निरंजन रेड्डी (YSRCP) शामिल हैं। हालांकि, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने यह कहते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया है कि प्रस्तावित बिल कानून के मूल सिद्धांत के खिलाफ हैं — कि किसी व्यक्ति को तब तक बेगुनाह माना जाता है जब तक वह दोषी साबित न हो जाए।

तीन संशोधन बिलों के बारे में

मॉनसून सेशन (20 अगस्त, 2025) के आखिरी दिन पेश किए गए इन तीन बिलों का मकसद सरकारी पदों पर बैठे लोगों के लिए ज़्यादा सख्त जवाबदेही लाना है। एक खास प्रावधान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन या उससे ज़्यादा समय तक हिरासत में रखने पर अपने आप हटाने का प्रस्ताव है। लोकसभा ने इन बिलों को पास होने से पहले डिटेल में जांच के लिए संसद की जॉइंट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पास किया।

जॉइंट कमेटी का मकसद

जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) उन मुश्किल कानूनी प्रस्तावों की जांच करने में अहम भूमिका निभाती है जिनके बड़े संवैधानिक या राजनीतिक मतलब होते हैं। यह कई पार्टियों का रिव्यू पक्का करता है, जिससे लागू करने से पहले गहरी जांच हो सके।

मुख्य तथ्य:

- अपराजिता सारंगी ओडिशा के भुवनेश्वर से लोकसभा MP हैं और 1994 बैच की पूर्व IAS ऑफिसर हैं।
- JPC मैकेनिज्म लोकसभा के प्रोसीजर रूल्स के रूल 193 के तहत बनाया गया है।
- संविधान (130वां अमेंडमेंट) बिल, 2025 ऊंचे संवैधानिक पदों के लिए अकाउंटेबिलिटी क्लॉज लाने की कोशिश करता है।
- जॉइंट कमेटियां आम तौर पर मुश्किल या कई डिपार्टमेंट वाले बिलों की जांच के लिए बनाई जाती हैं, जिनके लिए गहराई से एनालिसिस की ज़रूरत होती है।
- जॉइंट कमेटियों में सदस्यों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा के बीच आपसी सहमति से तय होती है।
- बोफोर्स स्कैंडल की जांच के लिए 1986 में पहली JPC बनाई गई थी।

शैलेश चंद्रा ग्लोबल ऑटो बॉडी OICA के हेड बनने वाले पहले भारतीय बने

भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर को एक बड़ी पहचान मिली है। सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के प्रेसिडेंट और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO शैलेश चंद्रा को 1 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले टर्म के लिए ऑर्गनाइज़ेशन इंटरनेशनेल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी'ऑटोमोबाइल्स (OICA) का प्रेसिडेंट चुना गया है। चंद्रा इस मशहूर ग्लोबल ऑटोमोटिव बॉडी को लीड करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने USA के अलायंस फॉर ऑटोमोटिव इनोवेशन के प्रेसिडेंट और CEO जॉन बोज़ेला की जगह ली है। OICA ने जर्मनी के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एसोसिएशन VDA की प्रेसिडेंट हिल्डेगार्ड मुलर को अपना वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया है। वह पहले जर्मन चांसलर की मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट और जर्मन एसोसिएशन ऑफ़ एनर्जी एंड वॉटर इंडस्ट्रीज़ (BDEW) की चेयरवुमन रह चुकी हैं। 1919 में शुरू हुआ OICA, नेशनल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एसोसिएशन के ग्लोबल फेडरेशन के तौर पर काम करता है, जो 36 सदस्य देशों को रिप्रेजेंट करता है। यह इंटरनेशनल ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड तय करने, ग्लोबल प्रोडक्शन और सेल्स डेटा

इकट्ठा करने और दुनिया भर में इंटरनेशनल मोटर शो को सपोर्ट करने के लिए UN के वर्ल्ड फोरम फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ व्हीकल रेगुलेशन (UNECE WP.29) के साथ मिलकर काम करता है। चंद्रा का चुनाव ग्लोबल ऑटो इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती लीडरशिप को दिखाता है, ऐसे समय में जब इंडस्ट्री नेट-ज़ीरो एमिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ओर बढ़ रही है।

सर्जियो गोर ने भारत में U.S. एम्बेसडर के तौर पर शपथ ली

यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर के भारत में अगले U.S. एम्बेसडर और साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए स्पेशल एन्वॉय के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें U.S.-इंडिया रिश्तों की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर ज़ोर दिया गया। यह अपॉइंटमेंट अगस्त 2025 में गोर के नॉमिनेशन के बाद हुआ है और यह U.S. एडमिनिस्ट्रेशन के भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर लगातार फोकस को दिखाता है, जिसे वह रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने में एक अहम साथी मानता है।

इंडिया-U.S. रिलेशन ओवरव्यू:
- डिप्लोमैटिक रिलेशन 1947 में बने।
- 2020 में "कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स" के तौर पर डेज़िग्नेटेड।
- रेगुलर बाइलेटरल डायलॉग में 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग, QUAD मीटिंग्स और ट्रेड पॉलिसी फोरम शामिल हैं।

सहयोग के मुख्य फोकस एरिया:
- डिफेंस: LEMOA (2016), COMCASA (2018), और BECA (2020) जैसे बुनियादी समझौते इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाते हैं।
- ट्रेड: FY 2023–24 में दोनों देशों का ट्रेड USD 191 बिलियन को पार कर गया, जिससे U.S. भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया।
- टेक्नोलॉजी और एनर्जी: सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में सहयोग।
- एजुकेशन: अभी लगभग 2 लाख भारतीय स्टूडेंट U.S. यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।

पटना में जन्मे डॉ. अंजनी सिन्हा सिंगापुर में नई U.S. एम्बेसडर बने

पटना (बिहार) की भारतीय मूल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अंजनी के. सिन्हा ने सिंगापुर में U.S. एम्बेसडर का पद ऑफिशियली संभाल लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एल्युम्नस, डॉ. सिन्हा की नियुक्ति ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारतीय मूल के प्रोफेशनल्स के बढ़ते रिप्रेजेंटेशन को दिखाती है।

डॉ. अंजनी के. सिन्हा का बैकग्राउंड
- जन्मस्थान: पटना, बिहार (इंडिया)।
- एजुकेशन: दिल्ली यूनिवर्सिटी की एल्युम्नस।

प्रोफेशन (डिप्लोमेसी से पहले):
- जाने-माने ऑर्थोपेडिक सर्जन।
- U.S. हेल्थकेयर सिस्टम में एंटरप्रेन्योर और मेडिकल लीडर।

U.S.-सिंगापुर रिलेशन:
डिप्लोमैटिक रिलेशन शुरू हुए: 1966 (लगभग छह दशक पहले)।

कोऑपरेशन के स्ट्रेटेजिक एरिया:
- डिफेंस और सिक्योरिटी: सिंगापुर की मिलिट्री फैसिलिटीज़ तक U.S. की एक्सेस।
- टेक्नोलॉजी और ट्रेड: सिंगापुर साउथ-ईस्ट एशिया में U.S. का एक बड़ा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है।
- एनर्जी कोऑपरेशन: क्लीन एनर्जी और इनोवेशन में जॉइंट प्रोजेक्ट्स।
- लॉ एनफोर्समेंट: साइबर सिक्योरिटी और एंटी-टेररिज्म इनिशिएटिव्स पर कोलेबोरेशन।

जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2026 तक NCLAT के चेयरपर्सन के तौर पर फिर से नियुक्त

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक भूषण को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का फिर से चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक प्रपोज़ल के बाद, 7 नवंबर, 2025 को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमिटी (ACC) ने इस फ़ैसले को मंज़ूरी दी। जस्टिस भूषण 4 जुलाई, 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे, जब उनकी उम्र 70 साल हो जाएगी।

NCLAT (नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल) के बारे में
- स्थापित: 1 जून, 2016
- पैरेंट मिनिस्ट्री: मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स
- हेडक्वार्टर: नई दिल्ली

कार्य:
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (IBBI), और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) के ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील सुनता है। कंपनीज़ एक्ट, 2013 और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 के तहत मामलों के फैसले में अहम भूमिका निभाता है।
- अभी की बनावट: चेयरपर्सन + ज्यूडिशियल और टेक्निकल मेंबर
- अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ़ द कैबिनेट (ACC):
- भारत के प्रधानमंत्री इसके हेड हैं।
- टॉप-लेवल ब्यूरोक्रेटिक और ट्रिब्यूनल पदों पर अपॉइंटमेंट को मंज़ूरी देता है।
- रीजनल मामलों को संभालने के लिए NCLAT की बेंच चेन्नई और हैदराबाद में भी काम करती हैं।
- जस्टिस भूषण पहले रावी ब्यास रिवर ट्रिब्यूनल के हेड थे, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच इंटर-स्टेट नदी पानी के झगड़ों को देखता है।
- उनके खास सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आधार, लैंड एक्विजिशन और अयोध्या टाइटल विवाद के मामले शामिल हैं।
- NCLAT चेयरपर्सन का कार्यकाल या रिटायरमेंट की उम्र ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के तहत तय होती है — ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की लिमिट 70 साल है। NCLAT के फैसलों के खिलाफ कंपनी एक्ट, 2013 के सेक्शन 423 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

विजय दहिया DDCA की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन बने

पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय दहिया को दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। तीन सदस्यों वाली कमेटी में रॉबिन सिंह (जूनियर) और अंजलि शर्मा भी शामिल हैं। इस अपॉइंटमेंट की घोषणा 6 नवंबर 2025 को की गई थी।

बदलाव का कारण और कमेटी की भूमिका:
CAC का पुनर्गठन पूर्व चेयरमैन सुरिंदर खन्ना को हटाने के बाद किया गया है, जिन पर जम्मू और कश्मीर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) से जुड़े मिसमैनेजमेंट और बकाया पेमेंट न करने के आरोप लगे थे।

CAC इन कामों के लिए ज़िम्मेदार है:
- दिल्ली की सभी क्रिकेट टीमों के लिए सिलेक्टर, कोच, मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ की सिफारिश करना।
- क्रिकेट ऑपरेशन की नियुक्तियों और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करना।

अतिरिक्त प्रमुख तथ्य::
- DDCA (दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन): 1883 में बना, 1928 से BCCI से जुड़ा हुआ है।
- CAC (क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी) DDCA के अंदर एक कानूनी बॉडी है जो कोचिंग और क्रिकेट से जुड़े अपॉइंटमेंट के सिलेक्शन और देखरेख के लिए ज़िम्मेदार है।
- स्टेट क्रिकेट बॉडीज़ में हाल के रिफॉर्म्स BCCI के गवर्नेंस रिफॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट-ऑफ-इंटरेस्ट रूल्स और ट्रांसपेरेंसी पर ज़ोर दिया गया है।
- विजय दहिया लगातार यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेशनल कंडक्ट के सपोर्टर रहे हैं।

रक्षित हर्गेव ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ और कार्यकारी निदेशक नियुक्त

रक्षित हर्गेव को 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी, पाँच साल के कार्यकाल के लिए, शेयरधारकों की मंज़ूरी के अधीन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल शेयरधारकों की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा।

पृष्ठभूमि और पूर्व भूमिका
हर्गेव इससे पहले बिड़ला ओपस के सीईओ थे, जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज का पेंट व्यवसाय और आदित्य बिड़ला समूह का हिस्सा है। वह 5 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से बिड़ला ओपस छोड़ देंगे।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज
- पूर्व में: ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड
- उद्योग: खाद्य प्रसंस्करण
- स्थापना: 1892; 1918 से ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड के रूप में
- मुख्यालय: कोलकाता, भारत
- अध्यक्ष: नुस्ली वाडिया

तंजानिया: चुनाव विवाद के बीच सामिया सुलुहू हसन ने प्रेसिडेंट के तौर पर दूसरे टर्म के लिए शपथ ली

तंजानिया की प्रेसिडेंट सामिया सुलुहू हसन ने हिंसा और विपक्ष के नकारे जाने वाले बहुत विवादित चुनाव के बाद अपने दूसरे टर्म के लिए शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी डोडोमा के एक मिलिट्री परेड ग्राउंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। चामा चा मापिंडुज़ी (CCM) पार्टी की सदस्य सामिया सुलुहू हसन, अपने पहले के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली की मौत के बाद 2021 में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं। उनके नेतृत्व ने पूर्वी अफ्रीका में आर्थिक सुधारों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्षेत्रीय कूटनीति पर ध्यान दिया है।

तंजानिया:

- राजधानी: डोडोमा
- करेंसी: तंजानिया शिलिंग
- सामिया सुलुहू हसन: तंजानिया की छठी राष्ट्रपति; यह पद संभालने वाली पहली महिला।
- कार्यकाल: 5 साल (तंजानिया के संविधान के अनुसार)।

संजय गर्ग ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए

सीनियर IAS ऑफिसर संजय गर्ग (1994 बैच, केरल कैडर) ने 1 अक्टूबर, 2025 से ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के डायरेक्टर जनरल (DG) का पद ऑफिशियली संभाल लिया है। यह अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने की। अपनी नई नियुक्ति से पहले, गर्ग इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) के सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन (DARE) में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। उनका अनुभव गवर्नेंस, रूरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जैसे खास सेक्टर्स में फैला हुआ है। BIS के DG के तौर पर, गर्ग इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) में भारत की नेशनल कमिटी के प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम करेंगे — यह ग्लोबल बॉडी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय करने के लिए ज़िम्मेदार है।

ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS):

- स्थापित: 1986 (BIS एक्ट, 1986 के तहत; 2016 में बदला गया)
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- काम करता है: मिनिस्ट्री ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
- अभी के मिनिस्टर: प्रल्हाद जोशी
- BIS भारत की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, जो स्टैंडर्डाइज़ेशन, सर्टिफ़िकेशन, हॉलमार्किंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ज़िम्मेदार है।

BIS सर्टिफ़िकेशन स्कीम:

- ISI मार्क: इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जो क्वालिटी और सेफ़्टी पक्का करते हैं।
- हॉलमार्किंग: सोने और चांदी की ज्वेलरी के लिए।
- कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम (CRS): इलेक्ट्रॉनिक और IT प्रोडक्ट्स के लिए।
- ECO मार्क: एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए।

वाइस एडमिरल बी. शिवकुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मैटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

वाइस एडमिरल बी. शिवकुमार ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना के 40वें मैटेरियल प्रमुख (COM) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वे वाइस एडमिरल किरण देशमुख (AVSM, VSM) का स्थान लेंगे। नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में बैटन परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया, जो नौसेना की शीर्ष कार्यात्मक शाखाओं में से एक में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है।

भारतीय नौसेना की तीन प्रमुख कार्यात्मक शाखाएँ हैं:

- संचालन - युद्ध और तैनाती
- कार्मिक - जनशक्ति और प्रशिक्षण
- सामग्री - उपकरण, रसद और रखरखाव

सामग्री प्रमुख सीधे नौसेनाध्यक्ष (सीएनएस) को रिपोर्ट करते हैं और नौसेना बोर्ड का हिस्सा होते हैं, जो दीर्घकालिक रणनीतिक और आधुनिकीकरण नीतियाँ तैयार करता है। यह नियुक्ति नौसेना के सतत बुनियादी ढाँचे और पुर्जों व प्रणालियों के स्वदेशी

उत्पादन पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने और विदेशी निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है।

मेजर जनरल भरत मेहतानी को एनसीसी निदेशालय (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़) का नया अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया

मेजर जनरल भरत मेहतानी को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को कवर करने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) निदेशालय का नया अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नियुक्त किया गया है। वे मेजर जनरल जगदीप सिंह चीमा का स्थान लेंगे, जो 37 वर्षों की विशिष्ट सैन्य सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। इस औपचारिक बैटन एक्सचेंज ने दोनों अधिकारियों के बीच नेतृत्व के सुचारु परिवर्तन को चिह्नित किया। एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) की स्थापना 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के तहत हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय (MoD) के अधीन कार्य करता है। एनसीसी का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और निस्वार्थ सेवा का विकास करना है। कैडेट गणतंत्र दिवस परेड, आपदा राहत, स्वच्छ भारत अभियान और साहसिक अभियानों में भाग लेते हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, का न्यायिक जीवन उल्लेखनीय रहा है। मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (2018-2019) और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (2001 से) के रूप में कार्य किया। उन्हें संवैधानिक कानून, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अपने प्रगतिशील निर्णयों के लिए जाना जाता है। 10 फ़रवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक से कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1984 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त हुए - उसी वर्ष उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

भारत के आगामी मुख्य न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरणों की सिफ़ारिश करने वाली कॉलेजियम प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल न्यायिक पारदर्शिता को मज़बूत करने, केस प्रबंधन प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने और न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग का विस्तार करने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर वरिष्ठता-आधारित पदोन्नति की परंपरा को जारी रखती है, जो दूसरे न्यायाधीशों के मामले (1993) के बाद से चली आ रही है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- संविधान का अनुच्छेद 124(2) राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं।
- भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुंदस कानिया (1950-1951) थे।
- अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था और यह नई दिल्ली में स्थित है।
- मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायिक अकादमी और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के पदेन प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं।
- नियुक्ति प्रक्रिया प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) का पालन करती है, जहाँ निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर अगले न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं।

कैमरून के 92 वर्षीय राष्ट्रपति पॉल बिया ने विवादास्पद आठवाँ कार्यकाल जीता

कैमरून के 92 वर्षीय लंबे समय से राष्ट्रपति पद पर आसीन नेता पॉल बिया ने 12 अक्टूबर, 2025 को हुए चुनाव में 53.7% वोट हासिल कर विवादास्पद आठवाँ राष्ट्रपति कार्यकाल हासिल कर लिया है। यह जानकारी संवैधानिक परिषद ने दी है। उनके मुख्य

प्रतिद्वंद्वी, इस्सा चिरोमा बाकरी को 35.2% वोट मिले। इस परिणाम के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, चुनावी धोखाधड़ी के आरोप और सुरक्षा बलों व विपक्षी समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई। पॉल बिया 1982 से सत्ता में हैं, जिससे वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले और सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्षों में से एक बन गए हैं।

कैमरून:

- राजधानी: याउंडे
- राष्ट्रपति: पॉल बिया
- प्रधानमंत्री: जोसेफ न्गुटे
- मुद्रा: सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक
- आधिकारिक भाषाएँ: फ्रेंच, अंग्रेज़ी

RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में सी. एस. राजन की पुनर्नियुक्ति को मंज़ूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में सी. एस. राजन की पुनर्नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है। उनका नया कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 21 अक्टूबर, 2027 को समाप्त होगा। बैंक की नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है।

मुख्य विवरण

- वर्तमान भूमिका: राजन जनवरी 2024 से अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और अक्टूबर 2022 में अपनी नियुक्ति के बाद से स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
- अतिरिक्त भूमिका: वे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड सदस्य भी हैं।

पृष्ठभूमि और करियर की मुख्य विशेषताएँ

- सिविल सेवा करियर: राजन 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनके पास 40 से अधिक वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है।
- पूर्व भूमिका: उन्होंने राजस्थान के मुख्य सचिव (2016) के रूप में कार्य किया और ऊर्जा, उद्योग, राजमार्ग और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काम किया।

सेवानिवृत्ति के बाद की भूमिकाएँ:

- उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद, राजस्थान (2016)।
- प्रबंध निदेशक, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) (भारत सरकार द्वारा 2018 में नियुक्त) - जहाँ उन्होंने कॉर्पोरेट पुनर्गठन और शासन सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में:

उदय कोटक द्वारा 2003 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से बैंक में परिवर्तित होने के लिए RBI की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद स्थापित।

- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
- टैगलाइन: "चलो पैसे को सरल बनाएँ। "
- सीईओ और एमडी: अशोक वासवानी

अंशकालिक और पूर्णकालिक अध्यक्षों के बीच अंतर:

- एक अंशकालिक अध्यक्ष मुख्य रूप से बोर्ड प्रशासन और नीति निरीक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि दैनिक कार्यों पर।
- एक पूर्णकालिक अध्यक्ष कार्यकारी और प्रबंधकीय जिम्मेदारियों में शामिल होता है।

कैथरीन कोनोली भारी जीत के बाद आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गईं

एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में, स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कोनोली अपनी प्रतिद्वंद्वी हीथर हम्फ्रीज़ पर भारी जीत हासिल करते हुए आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। यह चुनाव आयरिश राजनीति में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है, जहाँ एक स्वतंत्र उम्मीदवार को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ है।

मुख्य अंश

- पूर्व पद: आयरिश संसद (डैल इरेन) के उपाध्यक्ष
- राष्ट्रपति की भूमिका: मुख्यतः औपचारिक, आयरिश लोगों की एकता का प्रतिनिधित्व करती है।

आयरिश राष्ट्रपति पद के बारे में

भूमिका की प्रकृति: आयरलैंड के राष्ट्रपति (उआचटारन ना हिरेन) राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है, जबकि कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री (ताओसीच) द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

- कार्यकाल: सात वर्ष, एक बार नवीनीकृत।
- आधिकारिक निवास: आरास एन उआचटारैन, डबलिन।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- पूर्ववर्ती: माइकल डी. हिगिंस, जिन्होंने दो कार्यकाल (2011-2025) तक सेवा की।
- आयरलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति: मैरी रॉबिन्सन (1990-1997)।
- आयरलैंड की संसद: ओइरेचटास के नाम से जानी जाती है, जिसमें डैल एरेन (निचला सदन) और सीनाद एरेन (उच्च सदन) शामिल हैं।

- राजनीतिक व्यवस्था: संसदीय लोकतंत्र, जिसमें राष्ट्रपति राज्य प्रमुख और ताओसीच सरकार प्रमुख होते हैं।
- राजधानी: डबलिन
- मुद्रा: यूरो (€)
- सदस्यता: यूरोपीय संघ (ईयू), 1973 से

डेल टेक्नोलॉजीज ने अनुराग अरोड़ा को इंडिया कंज्यूमर बिजनेस के लिए सीनियर डायरेक्टर और GM नियुक्त किया

डेल टेक्नोलॉजीज ने अनुराग अरोड़ा को इंडिया में कंज्यूमर सेल्स का सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया। अरोड़ा 2020 में डेल में शामिल हुए थे और अब उन्हें इंडिया में कंज्यूमर सेगमेंट के लिए बिजनेस ग्रोथ, सेल्स और स्ट्रैटेजी को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास सेल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, रिटेल और ई-कॉमर्स में 28 साल का एक्सपीरियंस है। अरोड़ा ने डेल की कंज्यूमर स्ट्रैटेजी में काफी योगदान दिया है, जिसमें Dell.com को मजबूत करना और रिटेल चैनल्स को बढ़ाना शामिल है। उनके नए रोल में पूरे इंडियन मार्केट में कंज्यूमर बिजनेस को बढ़ाना शामिल है।

अमित अग्रवाल नए टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाए गए; नीरज मित्तल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भेजे गए

कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमिटी (ACC) ने एक बड़े ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल को मंज़ूरी दे दी है। अमित अग्रवाल (IAS, 1993 बैच, छत्तीसगढ़ कैडर) नए टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाए गए।

पहले का पद: सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्युटिकल्स (दिसंबर 2024 से)।

डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) और डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमीशन (DCC) को हेड करेंगे। नीरज मित्तल टेलीकॉम सेक्रेटरी से हटाकर मिनिस्ट्री ऑफ़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस (MoPNG) के नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। पंकज जैन की जगह लेंगे, जिन्हें 8वें सेंट्रल पे कमीशन का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है।

ACC द्वारा मंज़ूर दूसरे बड़े अपॉइंटमेंट्स

- मनोज जोशी (सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ लैंड रिसोर्सेज़) → सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल्स (अमित अग्रवाल की जगह)।
- सुनील पालीवाल (चेयरपर्सन, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट) → चेयरमैन, इनलैंड वाटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (सेक्रेटरी रैंक)।
- आतिश चंद्रा (स्पेशल सेक्रेटरी, PMO) → ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD), डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर।
- वी विद्यावती (टूरिज्म सेक्रेटरी) → सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्पावरमेंट ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़।
- एस कृष्णा (कर्नाटक कैडर IAS) → टूरिज्म सेक्रेटरी (विद्यावती की जगह)।

सरकार ने केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और PNB में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए

केंद्र सरकार ने पांच बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त करने को मंज़ूरी दे दी है, जो टॉप-लेवल बैंकिंग लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव है।

नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उनके पिछले रोल

केनरा बैंक

- अपॉइंटेड: सुनील कुमार चुघ
- पिछला रोल: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में चीफ जनरल मैनेजर (CGM)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

- अपॉइंटेड: अमरेश प्रसाद
- पिछला रोल: PNB चीफ जनरल मैनेजर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

- अपॉइंटेड: प्रभात किरण
- पिछला रोल: चीफ जनरल मैनेजर, केनरा बैंक

इंडियन बैंक

- अपॉइंटेड: मिनी टी. एम.
- पिछला रोल: बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ जनरल मैनेजर

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

- अपॉइंटेड: अमित कुमार श्रीवास्तव
- पिछला रोल: ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर, PNB

टेन्योर और इफेक्टिव शुरुआत

सभी पांच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 24 नवंबर 2025 से शुरू होकर तीन साल के टर्म के लिए काम करेंगे। उनकी अपॉइंटमेंट सरकारी लेवल पर अप्रूव्ड स्टैंडर्ड सीनियर लीडरशिप रोटेशन का हिस्सा हैं।

अपॉइंटमेंट के पीछे का मकसद

इन लीडरशिप बदलावों का मकसद इन चीज़ों को मज़बूत करना है:

- एग्जीक्यूटिव लेवल पर फैसले लेना
- इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस
- मुख्य सरकारी बैंकों में ऑपरेशनल एफिशिएंसी
- फाइनेंशियल सेक्टर की बदलती चुनौतियों के बीच सेक्टर में स्थिरता

वॉलमार्ट के सीईओ मैकमिलन एक दशक बाद सेवानिवृत्त होंगे, अंदरूनी सूत्र फ़र्नर उनके उत्तराधिकारी होंगे

वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन सेवानिवृत्त होंगे

वॉलमार्ट ने घोषणा की है कि लंबे समय से सीईओ रहे डग मैकमिलन एक दशक से ज़्यादा समय तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद 31 जनवरी, 2026 को सेवानिवृत्त होंगे।

अंदरूनी सूत्र के उत्तराधिकारी: जॉन फ़र्नर नए सीईओ नियुक्त

मैकमिलन के उत्तराधिकारी जॉन फ़र्नर होंगे, जो वर्तमान में वॉलमार्ट यू.एस. के सीईओ हैं और कंपनी में लगभग 30 साल बिता चुके हैं।

करियर का सफ़र और फ़िटनेस

मैकमिलन और फ़र्नर दोनों ने वॉलमार्ट में अपने करियर की शुरुआत प्रति घंटा सहयोगी के रूप में की थी - फ़र्नर ने 1993 में - जिससे वे वॉलमार्ट की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक मज़बूत सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त बन गए।

परिवर्तन योजना

मैकमिलन जून 2026 तक वॉलमार्ट के निदेशक मंडल में बने रहेंगे और वित्तीय वर्ष 2027 तक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे ताकि नेतृत्व का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके।

वॉलमार्ट

- मालिक: वाल्टन परिवार
- मुख्यालय: बेंटनविले, अर्कांसस, संयुक्त राज्य अमेरिका
- संस्थापक: सैम वाल्टन, बड वाल्टन
- अध्यक्ष एवं सीईओ: डग मैकमिलन

राजतन्त्र एवं शासन

केंद्र ने सीड्स एक्ट 1966 और सीड्स (कंट्रोल) ऑर्डर 1983 की जगह सीड्स बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत के बीज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाने के लिए ड्राफ्ट सीड्स बिल, 2025 तैयार किया है। इसका मकसद सीड्स एक्ट, 1966 और सीड्स (कंट्रोल) ऑर्डर, 1983 की जगह लेना है, और इस सेक्टर को आज की खेती, टेक्नोलॉजी और मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से बनाना है। यह बिल किसानों के अधिकारों की रक्षा करने, अच्छी क्वालिटी के बीजों तक सस्ती पहुँच पक्का करने और बीज सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मज़बूत करने पर फोकस करता है। यह नकली या खराब क्वालिटी के बीजों की बिक्री को रोकने की भी कोशिश करता है, जिससे किसानों का नुकसान कम हो। मंत्रालय ने अगले महीने की 11 तारीख तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए ड्राफ्ट बिल पर आम लोगों और स्टेकहोल्डर्स से कमेंट्स मंगाए हैं।

नया सीड्स बिल 2025 क्यों ज़रूरी है

भारत का सीड सेक्टर नई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ा है:

- हाइब्रिड सीड्स,
- GM रिसर्च,
- प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी,
- क्लाइमेट-रेज़िलिएंट वैरायटी।
- इसलिए, पुराना फ्रेमवर्क (1966 और 1983) पुराना हो गया।

सीड्स एक्ट 1966 अभी क्या करता है

बीजों की क्वालिटी, लेबलिंग, सर्टिफ़िकेशन और इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। स्टेट सीड सर्टिफ़िकेशन एजेंसियों और सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी के ज़रिए स्टैंडर्ड लागू करता है।

सीड्स (कंट्रोल) ऑर्डर 1983

बीज डीलरों के लिए लाइसेंसिंग ज़रूरी करता है। अक्सर ठीक से लागू न होने और पुरानी परिभाषाओं के लिए इसकी आलोचना होती है।

- सीड्स बिल 2025 के उम्मीद के मुताबिक मुख्य प्रोविज़न (शायद पहले के ड्राफ़्ट पर आधारित)
- बिक्री से पहले बीज वैरायटी का ज़रूरी रजिस्ट्रेशन।
- लेबलिंग के नियम: जर्मिनेशन %, प्योरिटी %, जेनेटिक प्योरिटी, वगैरह।
- अगर सही बुआई के हालात के बावजूद बीज खराब हो जाते हैं, तो सीड कंपनियों को किसानों को मुआवज़ा देना पड़ सकता है। नकली बीजों को कम करने के लिए बीज ट्रेसेबिलिटी का फ्रेमवर्क।
- बीज सर्टिफिकेशन और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को बढ़ावा देना।
- बीज डेवलपमेंट में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना।

PPV&FR एक्ट 2001 – किसान अधिकार (रिलवेंट लिंकेज)

किसान बीज बचा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं (ब्रांडेड बीज की बिक्री को छोड़कर)। अगर रजिस्टर्ड वैरायटी फेल हो जाती हैं तो किसानों को मुआवजा मिलता है। प्लांट ब्रीडर के अधिकार देता है।

बीज रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है

- फसल प्रोडक्टिविटी में 20–30% की बढ़ोतरी बीज की क्वालिटी की वजह से होती है।
- नकली बीज कपास, दालों और सब्जी सेक्टर में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए फूड सिक्योरिटी पक्का करता है और इनकम बढ़ाता है।

असम कैबिनेट ने एंटी-पॉलीगैमी बिल 2025 को मंज़ूरी दी: 7 साल तक की जेल, महिलाओं के लिए मुआवज़ा

असम कैबिनेट ने असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल, 2025 को मंज़ूरी दे दी है, जिसका मकसद राज्य में पॉलीगैमी (एक से ज़्यादा पति-पत्नी से शादी करना) की प्रथा पर रोक लगाना है। यह बिल 25 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले आने वाले सेशन में असम लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाएगा।

बिल के मुख्य नियम

बिल में एक से ज़्यादा शादी करने का दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल का प्रस्ताव है। यह अपराध कॉग्निज़ेबल होगा, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है, और तुरंत ज़मानत नहीं दी जाएगी। पॉलीगैमी की शिकार महिलाओं की मदद के लिए राज्य सरकार एक स्पेशल मुआवज़ा फंड बनाएगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस फंड का मकसद महिलाओं को – चाहे वे अनजान दूसरी पत्नियाँ हों या छोड़ी हुई पहली पत्नियाँ हों – पैसे और समाज की कमज़ोरी से बचाना है।

बिल के तहत छूट

यह बिल कल्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की वजह से कुछ कम्युनिटी और इलाकों पर लागू नहीं होगा:

असम में शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) कम्युनिटी।

भारतीय संविधान के छठे शेड्यूल के तहत आने वाले इलाके, जिनमें शामिल हैं:

- बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC)
- दीमा हसाओ ज़िला
- कार्बी आंगलोंग ज़िला
- इसके अलावा, 2005 से पहले छठे शेड्यूल वाले इलाकों में रहने वाले माइनॉरिटी मुसलमानों को भी छूट दी जाएगी।

बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट

2023 में, असम सरकार ने पहली बार एंटी-पॉलीगैमी कानून लाने के प्लान का अनाउंसमेंट किया था। रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट जज जस्टिस रूमी फुकन की हेडिंग में एक कमेटी बनाई गई थी ताकि यह जांचा जा सके कि ऐसा कानून बनाने के लिए राज्य लेजिस्लेचर की काबिलियत क्या है। 2024 में उत्तराखंड के

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पास करने के बाद इस प्रपोज़ल को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि असम का मकसद अपने कानून को UCC फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करना था।

8वें वेतन आयोग का गठन

केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संरचना में संशोधन हेतु 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8वीं सीपीसी) के गठन को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से देश भर के लगभग 50 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पैनल की संरचना और कार्यकाल

- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त), सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश।
- सदस्य: एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव।
- समय-सीमा: आयोग को गठन की तिथि से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यह अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, 1 जनवरी, 2026 से अंतिम कार्यान्वयन होने की संभावना है।

अपेक्षित वेतन संरचना और बजट आवंटन

8वें वेतन आयोग ने अभी तक आधिकारिक वेतन मैट्रिक्स प्रकाशित नहीं किए हैं, लेकिन प्रारंभिक अनुमान बताते हैं:

- फिटमेंट फैक्टर: राजकोषीय आवंटन के आधार पर 2.86-3.0 के बीच अपेक्षित।
- आयोग द्वारा 2026 के अंत तक सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जिसका चरणबद्ध कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2026-27 तक जारी रहेगा।

फिटमेंट फैक्टर: वेतन और पेंशन संशोधन का प्रमुख निर्धारक

फिटमेंट फैक्टर, संशोधन के दौरान मूल वेतन और पेंशन पर लागू होने वाला गुणन अनुपात है। 7वें वेतन आयोग (2016) ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी, जिससे कुल वेतन में 157% की वृद्धि हुई।

- न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया
- न्यूनतम पेंशन ₹3,500 से बढ़कर ₹9,000 हो गई
- यदि 2026 में भी यही कारक (2.57) लागू किया जाए:
- न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर ₹46,260/माह हो सकता है
- न्यूनतम पेंशन बढ़कर ₹23,130/माह हो सकती है
- हालांकि, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग 1.92 के अधिक रूढ़िवादी फिटमेंट कारक का अनुमान लगाते हैं, जिससे 92% की वृद्धि होगी और न्यूनतम मूल वेतन ₹34,560/माह हो जाएगा।

पृष्ठभूमि: वेतन आयोगों का विकास

- पहला वेतन आयोग 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के तहत गठित किया गया था।
- प्रत्येक वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में वेतन और पेंशन में संशोधन करता है।
- न्यायमूर्ति ए. के. माथुर की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुई।

अतिरिक्त:

- उद्देश्य: वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढाँचों की समीक्षा करता है और उन्हें मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के अनुरूप बनाने के लिए उनमें बदलावों की सिफ़ारिश करता है।
- कार्यान्वयन प्राधिकरण: वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)।
- प्रभाव: संशोधन राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढाँचों को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि कई राज्य सीपीसी की सिफ़ारिशों को आंशिक या पूर्ण रूप से अपनाते हैं।

आर्थिक निहितार्थ:

- उच्च वेतन बिलों के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है।
- घरेलू खपत और माँग को बढ़ावा देता है, जिससे अल्पावधि में अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।
- यूडीसी और एलडीसी वेतन संशोधन: लिपिक संवर्ग और कनिष्ठ कर्मचारियों को अक्सर निम्न वेतन स्तरों पर अधिक प्रतिशत वृद्धि के कारण आनुपातिक रूप से सबसे अधिक लाभ होता है।

केंद्र ने चार नए लेबर कोड नोटिफाई किए

नए लेबर कोड लागू हुए

भारत ने 21 नवंबर 2025 से चार बड़े लेबर कोड लागू किए हैं, जो दशकों में लेबर कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव है। ये नए कोड 29 पुराने और बिखरे हुए लेबर कानूनों की जगह लेंगे।

चार लेबर कोड

सुधारों में शामिल हैं:

1. मजदूरी पर कोड
2. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड
3. सोशल सिक्योरिटी पर कोड
4. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस (OSHWC) कोड

सुधार का मकसद

नए सिस्टम का मकसद कम्प्लायंस को आसान बनाना, लेबर गवर्नेंस को मॉडर्न बनाना और पूरे देश में साफ, एक जैसे नियम देना है। इसका मकसद वर्कर की सुरक्षा में सुधार करते हुए इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाना है।

वर्कर्स के लिए खास बदलाव

- एक जैसा मिनिमम पे पक्का करने के लिए एक नेशनल फ्लोर वेज।
- सोशल सिक्योरिटी कवरेज को गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक बढ़ाया गया।

➢ बेहतर सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस, जिसमें काम के घंटों और नाइट शिफ्ट में महिलाओं के काम पर अपडेटेड नियम शामिल हैं।
➢ सभी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी अपॉइंटमेंट लेटर।

एम्प्लॉयर्स पर असर

नए कोड सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंसिंग और रिटर्न फाइल करने में आसानी के साथ एक आसान सिस्टम लाते हैं। लेबर इंस्पेक्टर कम्प्लायंस को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेंगे।

चिंताएं और चुनौतियां

यूनियन और लेबर ग्रुप वर्कर के अधिकारों के कमज़ोर होने की चेतावनी देते हैं, खासकर स्ट्राइक नियमों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए सुरक्षा के मामले में। राज्यों में उनके नियमों की तैयारी के आधार पर लागू करना अलग-अलग हो सकता है।

कुल मिलाकर नज़रिया

चार लेबर कोड के लागू होने से भारत के लेबर लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव आया है। हालांकि उम्मीद है कि इससे रेगुलेशन आसान होंगे और एफिशिएंसी में सुधार होगा, लेकिन उनका असर काफी हद तक प्रैक्टिकल लागू करने और राज्य-स्तर की तैयारी पर निर्भर करेगा।

लघु लेख

सरकार ने ऑर्गन और टिशू ट्रांसप्लांटेशन रूल्स, 2025 में बदलावों को नोटिफाई किया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने THOTA एक्ट, 1994 के तहत ह्यूमन ऑर्गन और टिशू ट्रांसप्लांटेशन (अमेंडमेंट) रूल्स, 2025 पेश किए हैं, जिसका मकसद पूरे भारत में ऑर्गन और टिशू ट्रांसप्लांटेशन तक पहुंच को बेहतर बनाना है। यह बदलाव खास तौर पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से जुड़े प्रोसेस को आसान बनाता है, जिससे देश भर में ज़्यादा समावेशी आई-केयर सर्विस सुनिश्चित होती हैं।

2025 के अमेंडमेंट रूल्स के मुख्य तथ्य

यह बदलाव कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने वाले सेंटर्स के लिए क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप की ज़रूरी ज़रूरत को हटा देता है। ये माइक्रोस्कोप, हालांकि कॉर्नियल सेल हेल्थ का पता लगाने के लिए ज़रूरी थे, लेकिन छोटे और ग्रामीण आई-केयर सेंटर्स के लिए महंगे और खरीदना मुश्किल थे। इस रुकावट को हटाने के साथ, सरकार का लक्ष्य कॉर्नियल ट्रांसप्लांट क्षमताओं को आई हॉस्पिटल्स के बड़े नेटवर्क तक बढ़ाना है, खासकर उन इलाकों में जहां सुविधाएं कम हैं।

हेल्थकेयर का महत्व

यह नियम बदलाव पूरे भारत में ऑर्गन, टिशू और आई डोनेशन सेवाओं तक सभी की पहुँच को बेहतर बनाकर नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम (NOTP) के लक्ष्यों को सपोर्ट करता है। यह ज़्यादा मेडिकल संस्थानों को कॉर्नियल डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे डोनर टिशू की उपलब्धता बढ़ती है। इस सुधार से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से निपटने में भी काफी मदद मिलने की उम्मीद है, जो भारत की बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौतियों में से एक है।

कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बीमारी या आँख की पारदर्शी बाहरी सतह को नुकसान के कारण होता है, जो अक्सर इन्फेक्शन, चोट, कुपोषण या जेनेटिक्स से जुड़ा होता है। इंडियन जर्नल ऑफ़ ऑप्थल्मोलॉजी के अनुसार, यह भारत में मोतियाबिंद के बाद अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जिससे लगभग 1.2 मिलियन लोग प्रभावित हैं, और हर साल 25,000-30,000 नए मामले सामने आते हैं।

लीगल फ्रेमवर्क: ह्यूमन ऑर्गन्स और टिशूज़ का ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, 1994

1994 से पहले, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कानून राज्यों में बिखरे हुए थे, जिससे नैतिक चिंताएं पैदा हुईं और गैर-कानूनी ऑर्गन ट्रेड, खासकर किडनी में, बढ़ गया। इसे ठीक करने के लिए, डॉ. एल. एम. सिंघवी (1991) की हेड वाली एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर THOTA एक्ट, 1994 लागू किया गया था। यह एक्ट सिर्फ इलाज के मकसद से ह्यूमन ऑर्गन्स और टिशूज़ को निकालने, स्टोर करने और ट्रांसप्लांट करने के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा देता है, साथ ही ऑर्गन्स के कमर्शियल ट्रेड को रोकता है।

यह एक्ट ऑर्गन्स, खासकर ब्रेन-डेड डोनर्स से, नैतिक रूप से वापस पाने को पक्का करता है, और ट्रांसप्लांटेशन के तरीकों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को ज़रूरी बनाता है। मुख्य प्रोविज़न में डोनर-रिसीपिएंट रिश्तों की डेफिनिशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ज़रूरतें, और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑथराइज़ेशन कमेटियों की स्थापना शामिल हैं।

अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंटेशन

2011 के अमेंडमेंट के ज़रिए एक बड़ा अपडेट आया, जिसने एक्ट के कवरेज को बढ़ाकर ऑर्गन्स और टिशूज़ की एक बड़ी रेंज को शामिल किया। इन नियमों को लागू करने के लिए THOTA रूल्स, 2014 लाए गए थे। क्योंकि हेल्थ राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को इसे लागू करने के लिए फॉर्मल तौर पर एक्ट अपनाना होगा। अभी, यह एक्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जो अपने खास कानूनों को मानते हैं।

निठारी कांड का बड़ा मोड़: सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रोक सका कोली की रिहाई

पृष्ठभूमि: निठारी हत्याकांड

2005-2006 में, निठारी गाँव (नोएडा, उत्तर प्रदेश) में कई बच्चे और महिलाएँ लापता हो गईं। कंकाल और शरीर के अंग एक घर के पीछे पाए गए जहाँ कोली मोनिंदर सिंह पंढेर के यहाँ घरेलू नौकर के रूप में काम करता था।

दिसंबर 2006 में, अवशेष मिले; कोली और पंढेर को 29 दिसंबर 2006 को हिरासत में लिया गया। बाद में मामला केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया।

अभियोजन पक्ष का मामला और प्रारंभिक दोषसिद्धि

शुरुआती मुकदमों में से एक में अभियोजन पक्ष का मामला दो मुख्य स्तंभों पर टिका था:

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष कोली द्वारा स्वीकारोक्ति।
- कथित तौर पर उसकी निशानदेही पर खोपड़ियों, हड्डियों और अन्य वस्तुओं की बरामदगी।
- 2009 में, निचली अदालत ने कोली और पंढेर दोनों को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में उच्च न्यायालय ने कोली की दोषसिद्धि (उस मामले में) बरकरार रखी, लेकिन सबूतों के अभाव में पंढेर को उसी मुकदमे में बरी कर दिया।
- 2011 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कोली की अपील खारिज कर दी और उसे "सीरियल किलर" करार दिया और मामले को "दुर्लभतम" बताया।

संबंधित मामलों में बाद में बरी

2010 और 2021 के बीच, कोली पर उसी तथ्य-मैट्रिक्स (अर्थात, निठारी हत्याकांड) से उत्पन्न 12 अन्य मामलों में मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। पंढेर को भी उनमें से दो में दोषी ठहराया गया था।

हालांकि, अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोली को उन सभी 12 मामलों में बरी कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक या विश्वसनीय नहीं थी (कोली 60 दिनों तक बिना किसी वकील के हिरासत में रहा) और अवशेषों की बरामदगी अस्वीकार्य थी क्योंकि कोली को घटनास्थल पर लाए जाने से पहले ही खुदाई शुरू हो गई थी, और अन्य खामियाँ भी थीं।

जुलाई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन बरी किए गए मामलों में राज्य की अपीलों को खारिज कर दिया और उन्हें अंतिम बना दिया।

विसंगती: केवल एक दोषसिद्धि

कानूनी विरोधाभास यह था कि जहाँ 12 मामलों (एक ही साक्ष्य पर आधारित) में बरी कर दिया गया था, वहीं कोली पर एक दोषसिद्धि अभी भी कायम थी, जबकि उन पर एक ही साक्ष्य के आधार पर मुकदमा चलाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखना जबकि अन्य को समान रिकॉर्ड के आधार पर बरी कर दिया गया, "न्याय का स्पष्ट हनन" होगा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और तर्क

न्यायालय ने अपने उपचारात्मक क्षेत्राधिकार - अंतिम उपलब्ध कानूनी उपाय - का आह्वान करते हुए कहा कि जब गंभीर अन्याय हो तो उसे हस्तक्षेप करना चाहिए।

न्यायालय ने इस्तेमाल किए गए सबूतों में "संरचनात्मक कमियों" का उल्लेख किया: स्वीकारोक्ति स्वैच्छिकता के मानक पर खरी नहीं उतरी थी और प्रक्रियागत खामियों (जैसे, घटनास्थल का अभियुक्त के पूर्ण नियंत्रण में न होना, पुलिस को अवशेषों की पूर्व जानकारी, अपर्याप्त फोरेंसिक पुष्टिकरण) के कारण बरामदगी स्वीकार्य नहीं थी।

न्यायालय ने कहा कि यदि समान साक्ष्यों पर आधारित दो परिणामों (कुछ मामलों में बरी और अन्य में दोषसिद्धि) को एक साथ रहने दिया गया, तो यह अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार - निष्पक्ष प्रक्रिया) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कोली की शेष दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

निहितार्थ और प्रमुख सबक

न्याय की एकरूपता: जब साक्ष्य समान हों, तो परिणाम समान होने चाहिए; अन्यथा समानता भंग होती है।

साक्ष्य की स्वीकार्यता मायने रखती है: स्वीकारोक्ति, बरामदगी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को पूरा करने वाली और विश्वसनीय रूप से पुष्ट होने वाली होनी चाहिए।

उपचारात्मक क्षेत्राधिकार की भूमिका: यह दर्शाता है कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय घटना के दशकों बाद भी गंभीर अन्याय को ठीक करने के लिए कदम उठा सकता है।

हाई-प्रोफाइल मामला, उच्च मानक: अत्यंत गंभीर अपराधों में भी, "उचित संदेह से परे" के मानक से समझौता नहीं किया जा सकता।

परीक्षा प्रासंगिकता: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यह मामला अनुच्छेद 14 और 21, दंड प्रक्रिया (धारा 164 सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम), और अपीलीय/उपचारात्मक न्यायशास्त्र का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण है।

सरल शब्दों में:

कोली इसलिए बरी हो गया क्योंकि उसके खिलाफ एकमात्र सबूत (स्वीकारोक्ति + बरामदगी) दोषपूर्ण घोषित कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसे 12 मामलों में बरी नहीं कर सकते, लेकिन एक मामले में उसे दोषी ठहरा सकते हैं, जबकि सभी मामले एक ही दोषपूर्ण सबूत पर आधारित थे।

मुख्य कारण का विश्लेषण:

धारा 164 सीआरपीसी के तहत स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं थी

वह 60 से अधिक दिनों तक हिरासत में रहा।

वकील तक पहुँच नहीं थी।

अदालत ने कहा कि इस तरह के स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

हड्डियों और अवशेषों की बरामदगी अवैध/अविश्वसनीय थी

कोली को घटनास्थल पर लाए जाने से पहले ही खुदाई शुरू हो गई थी।

पुलिस को पहले से ही पता था कि अवशेष कहाँ मिले थे।

साक्ष्यों की श्रृंखला टूटी हुई थी।

फोरेंसिक संपर्क कमज़ोर थे।

12 समान मामले पहले ही बरी हो चुके हैं

1. सभी मामलों में साक्ष्य एक जैसे थे।
2. 2025 में अपील समाप्त होने के बाद, सभी बरी होने के फैसले अंतिम हो गए।
3. केवल एक ही दोषसिद्धि को बरकरार रखना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
4. यह अनुच्छेद 14 - कानून के समक्ष समानता - का उल्लंघन करता है।
5. यह अनुच्छेद 21 - निष्पक्ष प्रक्रिया - का उल्लंघन करता है।
6. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी असंगति "न्याय की स्पष्ट विफलता" है।
7. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उपचारात्मक शक्ति का प्रयोग किया।
8. यह गंभीर अन्याय को ठीक करने का अंतिम और दुर्लभतम उपाय है।
9. इसने कोली की एकमात्र बची हुई दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ

भारत एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स कार्यकारी समिति में पुनः निर्वाचित

रोम में आयोजित 48वें कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (CAC48) सत्र के दौरान, भारत को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स कार्यकारी समिति में पुनः निर्वाचित किया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रजित पुन्हानी ने किया।

CAC48 में भारत के प्रमुख फोकस क्षेत्र

भारत ने निम्नलिखित से संबंधित वैज्ञानिक डेटाबेस को अद्यतन और विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला:

- खाद्य योजक
- कीटनाशक अवशेष
- पशु चिकित्सा दवा अवशेष
- विश्लेषणात्मक विधियाँ
- खाद्य संदूषक

प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के लिए समर्थन

भारत ने कोडेक्स संचालन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एकीकृत करने की वकालत की, जिसमें तेज़ और अधिक सटीक दस्तावेज़ अनुवाद शामिल है।

विस्तारित नेतृत्व भूमिका

भारत का पुनर्निर्वाचन 2027 में CAC50 के पूरा होने तक कोडेक्स गतिविधियों में उसके निरंतर नेतृत्व और सहयोग को सुनिश्चित करता है।

कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (CAC) क्या है?

कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग एक वैश्विक मंच है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक, दिशानिर्देश और कार्यप्रणाली संहिताएँ विकसित करता है:

- खाद्य सुरक्षा
- उपभोक्ता संरक्षण
- खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार
- इसके मानकों का दुनिया भर में उपयोग किया जाता है और ये राष्ट्रीय खाद्य कानूनों, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा नियमों को प्रभावित करते हैं।

GCC ने वन-स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंज़ूरी दी

गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) ने एक वन-स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंज़ूरी दी है, जो एक ही जगह पर इमिग्रेशन, कस्टम और सिक्योरिटी चेक की इजाज़त देकर गल्फ देशों के बीच यात्रा को आसान बनाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 में UAE और बहरीन के बीच शुरू होगा। पूरी तरह से लागू होने के बाद, यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा चेक के सीधे एयरपोर्ट पर उतर और बाहर निकल सकेंगे, जिससे इस इलाके में यात्रा की सुविधा बेहतर होगी।

डिजिटल डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म

यह सिस्टम एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्लेटफॉर्म पर चलेगा, जिससे GCC देशों के बीच सिक्योरिटी, बैगेज की जानकारी और यात्रा नियमों का रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। इसका मकसद बॉर्डर प्रोसेस में एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और स्पीड बढ़ाना है।

बड़ी रीजनल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा

यह पहल एक और बड़े सुधार — GCC ग्रैंड टूर्स वीज़ा को सपोर्ट करती है, जो यूरोप के शेंगेन वीज़ा जैसा है। यूनिफाइड टूरिस्ट वीज़ा के 2025 के आखिर तक पायलट ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है, और 2026 में पूरी तरह से रोलआउट होने की संभावना है। इन उपायों का मकसद मिलकर रीजनल टूरिज्म और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देना है।

गल्फ रेलवे प्रोजेक्ट से लिंक

GCC सभी छह सदस्य देशों को 2,177 km रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए गल्फ रेलवे प्रोजेक्ट भी डेवलप कर रहा है। इसे पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर 2030 है, जिससे आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव और मज़बूत होगा।

मुख्य तथ्य:

- GCC सदस्य: सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान
- शुरुआत: 1981, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग पर फोकस
- वन-स्टॉप सिस्टम: UAE-बहरीन के बीच पहला फेज़ 2025 में
- यूनिफाइड वीज़ा: GCC ग्रैंड टूर्स वीज़ा — 2026 में पूरी तरह से शुरू करने का टारगेट
- आर्थिक फ़ायदा: यात्रा का समय कम, टूरिज्म और व्यापार में बढ़ोतरी
- सुरक्षा पहलू: मज़बूत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बॉर्डर डेटा शेयर किया जाएगा

ओमान 2025-29 के लिए UNESCO की मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) काउंसिल का सदस्य बना

ओमान को 2025–2029 के टर्म के लिए UNESCO मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) प्रोग्राम की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल में काम करने के लिए चुना गया है। यह चुनाव उज़्बेकिस्तान के समरकंद में UNESCO जनरल कॉन्फ्रेंस के 43वें सेशन के दौरान हुआ। अपनी एनवायरनमेंट अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, ओमान का चुनाव ग्लोबल एनवायरनमेंटल गवर्नेंस और बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन में उसकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है। काउंसिल में शामिल होकर, ओमान MAB के मकसदों में एक्टिवली हिस्सा लेगा: प्रोटेक्टेड एरिया को बढ़ाना, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना, बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन को

आगे बढ़ाना, और सस्टेनेबल तरीकों को बढ़ावा देना। ओमान के पास पहले से ही UNESCO द्वारा डेज़िग्नेटेड दो बायोस्फीयर रिज़र्व हैं: अल-सरीन नेचर रिज़र्व और अल जबल अल अख़दर लैंडस्केप रिज़र्व, जो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए उसके कमिटमेंट को दिखाते हैं।

UNESCO मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) प्रोग्राम के बारे में

- शुरू हुआ: 1971
- मकसद: समाज और बायोस्फीयर के बीच की दूरी को कम करना; लोकल कम्युनिटी की कोशिशों और अच्छे साइंस के आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सॉल्यूशन को बढ़ावा देना।

मुख्य हिस्से:

- बायोस्फीयर रिज़र्व (कोर, बफर और ट्रांज़िशन ज़ोन)
- इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी और इंसानों के बीच बातचीत पर रिसर्च
- सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस

इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल (ICC) एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें चुने हुए सदस्य देश शामिल हैं; यह पॉलिसी तय करती है और नए बायोस्फीयर रिज़र्व को मंज़ूरी देती है।

पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर साइन किए

पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर साइन किए हैं, जिसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने पास कर दिया था, जिससे यह ऑफिशियली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया है। यह अमेंडमेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलिट्री की सभी ब्रांच पर बहुत ज़्यादा नए अधिकार देता है, जबकि ज्यूडिशियरी की आज़ादी को काफी कमज़ोर करता है। यह अमेंडमेंट आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट दोनों के लिए लाइफटाइम लीगल इम्युनिटी भी पक्का करता है, जिससे भविष्य में कोई भी केस नहीं चलेगा। इस कानून का कड़ा विरोध हुआ है, लीगल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि यह तानाशाही की ओर एक बदलाव दिखाता है और डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कमज़ोर करता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और दूसरे पॉलिटिकल अलायंस समेत विपक्षी पार्टियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें सरकार पर ज्यूडिशियल पावर को दबाने और ज़्यादा मिलिट्री कंट्रोल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।

27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट (पाकिस्तान) के बारे में

यह आर्मी चीफ को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देता है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास में एक बहुत कम देखा गया कदम है।

यह ज्यूडिशियरी की भूमिका को कमज़ोर करता है, खासकर चीफ जस्टिस की शक्तियों को।

यह इन्हें ज़िंदगी भर की इम्यूनिटी देता है:

- आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर
- राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी

यह अमेंडमेंट क्यों विवादित है

कानूनी जानकारों का कहना है कि:

- यह मिलिट्री लीडरशिप में पावर को एक जगह जमा करता है
- शक्तियों के बंटवारे को कमज़ोर करता है
- न्यायिक आज़ादी को कम करता है
- लोकतांत्रिक शासन के लिए खतरा है
- विपक्षी पार्टियों ने बिल को "असंवैधानिक" और "अथॉरिटेरियन" बताया।

कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा: भारत–नेपाल ट्रांज़िट प्रोटोकॉल को मिला रणनीतिक अपग्रेड

इंडिया और नेपाल ने ट्रांज़िट ट्रीटी के प्रोटोकॉल में बदलाव के लिए एक लेटर ऑफ़ एक्सचेंज (LoE) पर साइन किए हैं, जिससे जोगबनी-विराटनगर रेल लिंक के ज़रिए सीधी रेल कनेक्टिविटी हो सकेगी। इस बदलाव से कोलकाता और विशाखापत्तनम पोर्ट से सीधे नेपाल कस्टम्स यार्ड कार्गो स्टेशन तक कंटेनर वाला और बल्क कार्गो आ-जा सकेगा। यह पहल मल्टीमॉडल ट्रेड कनेक्टिविटी को मज़बूत करती है, तीसरे देशों के साथ नेपाल के व्यापार को आसान बनाती है, और आर्थिक और कमर्शियल रिश्तों को गहरा करती है। यह रेल लिंक—जो भारत की ग्रांट मदद से बना है—का उद्घाटन दोनों देशों के PM ने 1 जून 2023 को मिलकर किया था। इस मीटिंग में क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया गया, जिसमें इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICPs) और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

स्टैटिक और बैकग्राउंड फैक्ट्स

इंडिया-नेपाल ट्रांज़िट ट्रीटी: 1960 में साइन की गई; यह नेपाल को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन पोर्ट्स तक पहुँचने की इजाज़त देती है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, जो समुद्री रास्तों पर ट्रांज़िट के लिए पूरी तरह से इंडिया पर निर्भर है। जोगबनी बिहार में है; विराटनगर नेपाल का बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है।

ट्रेड और कनेक्टिविटी फैक्ट्स

- भारत और नेपाल के बीच 1,850 km से ज़्यादा का खुला बॉर्डर है।
- मुख्य बॉर्डर पॉइंट्स: रक्सौल-बीरगंज, जोगबनी-विराटनगर, सुनौली-भैरहवा, काकरभिट्टा-नक्सलबाड़ी, बनबसा-महेंद्रनगर।
- भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर और सबसे बड़ा FDI सोर्स है।

ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स

- इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स (ICPs): बिना रुकावट ट्रेड के लिए मॉडर्न बॉर्डर फैसिलिटीज़।
- भारत-नेपाल के बीच फंक्शनल ICPs: रक्सौल-बीरगंज, जोगबनी-विराटनगर, सुनौली-भैरहवा।

भारत इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए नेपाल को सपोर्ट करता है:

- जयनगर–कुर्था रेलवे
- रक्सौल–काठमांडू रेलवे (प्रस्तावित)

- अरुण III हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट
- अपर करनाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट

सीरिया ने ISIS के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया

नए समझौते पर हस्ताक्षर

सीरिया ने ISIS को हराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक गठबंधन के साथ एक राजनीतिक सहयोग घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड द लेवेंट (ISIL) के विरुद्ध लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने की उसकी मंशा का संकेत मिलता है। घोषणापत्र में वर्तमान में राजनीतिक और गैर-सैन्य पहलुओं को शामिल किया गया है, जबकि प्रत्यक्ष सैन्य एकीकरण पर अभी विस्तार से चर्चा होनी बाकी है।

रणनीतिक महत्व

सीरिया का यह कदम एक बड़े कूटनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो दमिश्क को वाशिंगटन और ISIL के विरुद्ध व्यापक गठबंधन प्रयासों के और करीब लाता है। यह समझौता सीरिया के पुनर्निर्माण समर्थन, प्रतिबंधों में राहत और वैश्विक भागीदारी को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

अगले कदम और अनिश्चितताएँ

प्रभावी सैन्य सहयोग, संयुक्त अभियान और कार्यान्वयन समय-सीमा अभी भी अस्पष्ट हैं और आगे की बातचीत के अधीन हैं। पूर्ण एकीकरण स्पष्ट होने से पहले दोनों पक्षों को परिचालन ढाँचों और सुरक्षा गारंटियों को औपचारिक रूप देना होगा।

इसका क्या अर्थ है?

सीरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के साथ सहयोग करने के लिए औपचारिक रूप से सहमति व्यक्त की है, जो आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड द लेवेंट (ISIL) के विरुद्ध लड़ता है।

- यह सहयोग मुख्यतः राजनीतिक, सुरक्षा और ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने के पहलुओं पर केंद्रित है, हालाँकि प्रत्यक्ष सैन्य समन्वय की अभी पुष्टि नहीं हुई है।
- यह कदम एक बड़े कूटनीतिक बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि सीरिया – जो लंबे समय से पश्चिम द्वारा अलग-थलग पड़ा हुआ है – अब एक साझा लक्ष्य: ISIL के खात्मे के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा दिखा रहा है।
- यह पुनर्निर्माण, प्रतिबंधों में ढील और अन्य देशों के साथ सीरिया के संबंधों के पुनर्निर्माण पर भविष्य की बातचीत के द्वार भी खोल सकता है।

सरल शब्दों में, सीरिया के इस गठबंधन में शामिल होने का अर्थ है कि वह अब ISIL से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन का हिस्सा है, और वर्षों में पहली बार – कम से कम आंशिक रूप से – पश्चिमी शक्तियों के साथ जुड़ रहा है।

सीरिया

- राजधानी: दमिश्क
- राष्ट्रपति: अहमद अल-शरा
- आधिकारिक भाषा: अरबी
- महाद्वीप: एशिया

सीमा पर बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ शांति समझौते को स्थगित किया

सीमा पर घटना

थाई-कंबोडिया सीमा के पास सिसाकेत प्रांत में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में थाई सैनिक घायल हो गए, जिनमें से एक का पैर कट गया। थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाया, जिसका कंबोडिया ने खंडन करते हुए दावा किया कि विस्फोट पुरानी बारूदी सुरंगों से हुआ था।

युद्धविराम समझौते का निलंबन

थाईलैंड ने घोषणा की कि वह अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाले शांति समझौते के कार्यान्वयन को तब तक स्थगित कर रहा है जब तक कंबोडिया अनिर्दिष्ट मांगों को पूरा नहीं कर देता। हाल ही में मलेशिया में हस्ताक्षरित इस समझौते में भारी हथियारों को हटाना और कंबोडियाई युद्धबंदियों की रिहाई शामिल थी।

रणनीतिक और कूटनीतिक निहितार्थ

इस निलंबन से 2025 के सीमा संघर्ष को कम करने के हालिया प्रयास ख़तरे में पड़ गए हैं, जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और दर्जनों मौतें हुईं। कंबोडिया ने गहरी चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि इस कदम से महीनों की कूटनीतिक प्रगति पर पानी फिर सकता है।

अगले कदम

कंबोडिया की कार्रवाई के स्पष्टीकरण तक थाईलैंड ने कैदियों की रिहाई और हथियार वापसी पर रोक लगा दी है। दोनों पक्षों पर विश्वास बहाल करने और आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए शांति समझौते की प्रतिबद्धताओं को फिर से शुरू करने का दबाव है।

विवाद की पृष्ठभूमि:

मूल थाईलैंड-कंबोडिया विवाद 1900 के दशक के शुरुआती वर्षों का है और सीमा पर स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर, प्रीह विहियर मंदिर के स्वामित्व को लेकर केंद्रित है। 1904-1908 में, फ्रांसीसी औपनिवेशिक मानचित्रों (जब कंबोडिया फ्रांसीसी शासन के अधीन था) में मंदिर को कंबोडियाई क्षेत्र के अंदर दिखाया गया था, लेकिन बाद में थाईलैंड ने इसका विरोध किया और दावा किया कि ये मानचित्र गलत थे। 1962 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने फैसला सुनाया कि प्रीह विहियर मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड ने आसपास के 4.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विवाद किया, यह तर्क देते हुए कि यह फैसला केवल मंदिर पर ही लागू होता है। इस सीमा अस्पष्टता के कारण तब से दोनों देशों के बीच कभी-कभी सैन्य झड़पें और राजनयिक तनाव उत्पन्न हुए हैं।

बढ़ते जलवायु खतरों के बीच तुवालु IUCN का 90वाँ सदस्य बना

एक प्रमुख पर्यावरणीय घटनाक्रम में, दुनिया के सबसे छोटे और जलवायु के प्रति सबसे संवेदनशील द्वीप राष्ट्रों में से एक, तुवालु,

आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) का 90वाँ सदस्य बन गया है। इस सदस्यता का उद्देश्य तुवालु के पर्यावरणीय शासन को मज़बूत करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों में इसकी वैश्विक भागीदारी को गहरा करना है।

तुवालु के बारे में

- स्थान: प्रशांत महासागर, हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच
- भूगोल: नौ एटोल और निचले द्वीप समूह
- कुल भूमि क्षेत्र: लगभग 26 वर्ग किलोमीटर
- अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ): लगभग 900,000 वर्ग किलोमीटर, प्रवाल भित्तियों, मत्स्य पालन और प्रवासी समुद्री पक्षियों से समृद्ध
- राजधानी: फुनाफुटी
- तुवालु का IUCN में शामिल होना जैव विविधता संरक्षण, सतत संसाधन प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन पहलों के लिए वैश्विक समर्थन प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

IUCN (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) के बारे में

- स्थापना: 1948
- मुख्यालय: ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड
- वर्तमान सदस्य देश: 90 (तुवालु के शामिल होने के साथ)
- उद्देश्य: प्रकृति संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और जैव विविधता पर सरकारों के लिए नीतिगत मार्गदर्शन को बढ़ावा देना।
- प्रमुख रिपोर्ट: संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची - जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची।

जापान ने दुनिया का पहला येन-आधारित स्थिर सिक्का "JPYC" लॉन्च किया

एक ऐतिहासिक वित्तीय घटनाक्रम में, जापान ने दुनिया का पहला येन-आधारित स्थिर सिक्का लॉन्च किया है, जो पारंपरिक रूप से नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था में ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल भुगतानों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। JPYC नामक इस स्थिर सिक्के को जापानी फिनटेक स्टार्टअप JPYC Inc. ने लॉन्च किया है। यह डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से घरेलू बचत और जापानी सरकारी बॉन्ड (JGB) द्वारा समर्थित है और जापानी येन के साथ 1:1 अनुपात में परिवर्तनीय है।

JPYC स्थिर सिक्के के बारे में

JPYC Inc. का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 10 ट्रिलियन येन (लगभग 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के JPYC टोकन जारी करना है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों डिजिटल लेनदेन में इसके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसे शीघ्र अपनाने के लिए, शुरुआत में कोई लेनदेन शुल्क नहीं लिया जाएगा; इसके बजाय, कंपनी अपनी JGB होल्डिंग्स पर ब्याज से रिटर्न अर्जित करने की योजना बना रही है। जेपीवाईसी के सीईओ नोरिटाका ओकाबे के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य लेनदेन और निपटान लागत को कम करना है, जिससे स्टार्टअप्स और व्यवसायों को तेज़ और सस्ते डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके। कंपनी सीमा पार अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए वैश्विक साझेदारियों के लिए भी तैयार है।

कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में तिमोर-लेस्ते आसियान का 11वाँ सदस्य बना

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान, तिमोर-लेस्ते आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया। 1999 में कंबोडिया के प्रवेश के बाद से, यह दो दशकों से भी अधिक समय में इस क्षेत्रीय समूह का पहला विस्तार है।

मुख्य अंश

- विषय: "समावेशीपन और स्थिरता"
- नया सदस्य: तिमोर-लेस्ते (पूर्वी तिमोर)
- प्रधानमंत्री उपस्थित: ज़ानाना गुस्माओ, जिन्होंने आसियान नेताओं के साथ विलय दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए।
- महत्व: 26 वर्षों में पहला आसियान विस्तार, जो क्षेत्रीय एकता और सहयोग का प्रतीक है।

आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) के बारे में

- स्थापना: 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणापत्र (बैंकॉक घोषणापत्र) के माध्यम से।
- संस्थापक सदस्य: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।

बाद के सदस्य:

- ब्रुनेई दारुस्सलाम - 1984
- वियतनाम - 1995
- लाओस और म्यांमार - 1997
- कंबोडिया - 1999
- तिमोर-लेस्ते - 2025 (11वाँ सदस्य)
- मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।
- प्राथमिक लक्ष्य: सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, राजनीतिक सहयोग और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।

तिमोर-लेस्ते के बारे में

- राजधानी: दिली
- स्वतंत्रता: 2002 में (इंडोनेशिया से अलग होने के बाद) प्राप्त हुई।
- अर्थव्यवस्था: तेल, गैस और कृषि पर अत्यधिक निर्भर।
- सामरिक महत्व: एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, विशेष रूप से समुद्री और ऊर्जा सहयोग में, आसियान की पहुँच को मज़बूत करता है।

अतिरिक्त:

- आसियान अध्यक्ष (2025): मलेशिया
- आसियान का उद्देश्य: "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय"

श्रीलंका को आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के लिए एडीबी से 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता मिली

श्रीलंका को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता मिली है। यह राशि 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की तीन किस्तों में जारी की जाएगी। यह धनराशि आर्थिक स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, व्यापक आर्थिक लचीलापन और पर्यटन विकास पर केंद्रित है।

यह धनराशि निम्नलिखित क्षेत्रों में पर्यटन क्षमता विकसित करने में मदद करेगी:

- त्रिंकोमाली (पूर्वी बंदरगाह जिला)
- मध्य प्रांत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सिगिरिया के आसपास के क्षेत्र।

आर्थिक पृष्ठभूमि:

श्रीलंका 2022 के वित्तीय संकट से उबर रहा है, जिसकी विशेषताएँ हैं:

- विदेशी मुद्रा भंडार में कमी
- उच्च मुद्रास्फीति
- ऋण चूक
- ईंधन, खाद्यान्न और दवाओं की कमी
- देश आईएमएफ समर्थित कार्यक्रम के तहत सुधारों को लागू कर रहा है।
- यह स्थिरता बहाल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए एडीबी और विश्व बैंक जैसी एजेंसियों से भी सहायता मांग रहा है।

US ने ताइवान को $700m का NASAMS मिसाइल सिस्टम बेचा

बड़ी मिसाइल सेल: U.S. ने ताइवान को NASAMS मीडियम-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम बेचने के लिए लगभग $700 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है, जो ताइपे के लिए वाशिंगटन के सपोर्ट को दिखाता है।

NASAMS क्या है? NASAMS (नेशनल एडवांस्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम) RTX ने बनाया है और यूक्रेन में इसका बैटल-टेस्ट किया गया है; यह ताइवान के एयर डिफेंस को काफी मजबूत करता है।

डील की डिटेल्स और टाइमलाइन: पेंटागन ने एक "पक्की फिक्स्ड-प्राइस" डील कन्फर्म की है, जिसका काम फरवरी 2031 तक पूरा होने वाला है।

स्ट्रेटेजिक मतलब: यह ताइवान की लेयर्ड एयर-डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, खासकर आइलैंड के पास अक्सर चीनी मिलिट्री एक्टिविटी को देखते हुए।

U.S.–ताइवान मैसेज: U.S. अधिकारियों ने जोर दिया कि यह सेल ताइवान के डिफेंस के लिए "पत्थर की तरह मजबूत" अमेरिकी कमिटमेंट का एक साफ सिग्नल है।

चीन के साथ बढ़ता तनाव: बीजिंग इस डील का कड़ा विरोध कर रहा है, वह ऐसे हथियारों की बिक्री को ताइवान पर अपने दावों का उल्लंघन और इलाके में अस्थिरता पैदा करने वाला कदम मानता है।

UAE 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय डोनर बनेगा

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 2025 में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (EU) के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय डोनर बन गया है। ग्लोबल मानवीय फंडिंग डेटा के अनुसार, UAE ने USD 1.46 बिलियन का योगदान दिया, जो कुल ग्लोबल मानवीय सहायता का 7.2% है, जो USD 20.28 बिलियन था। खास बात यह है कि UAE अब सबसे बड़ा इंडिविजुअल डोनर देश है, क्योंकि USA और EU को सिंगल देशों के बजाय डोनर ग्रुप माना जाता है। UAE का मानवीय मॉडल न्यूट्रैलिटी, इनक्लूसिविटी और बिना किसी भेदभाव के मदद देने पर आधारित है, जो राष्ट्रीयता, धर्म या एथनिसिटी की परवाह किए बिना मदद देता है। देश तेज़ी से आपदा रिस्पॉन्स और लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटिव, दोनों पर फोकस करता है। ग्लोबल मानवीय जुड़ाव के हिस्से के तौर पर, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुख्य सेक्टर को सपोर्ट किया गया है।

UAE मानवीय मदद पाने वाले टॉप देश (2025)

1 फ़िलिस्तीन (गाज़ा) – सबसे बड़ा हिस्सा

2 सूडान

दूसरे बड़े देश: सीरिया, यूक्रेन, अफ़गानिस्तान

1. UAE अपनी ग्लोबल मदद की भूमिका क्यों बढ़ा रहा है

- सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ाता है
- एक ग्लोबल मानवीय केंद्र के तौर पर अपनी इमेज को मज़बूत करता है
- मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और उससे आगे अपनी स्ट्रेटेजिक विदेश नीति को सपोर्ट करता है
- UAE के संस्थापक शेख ज़ायद के विज़न को बनाए रखता है, जिन्होंने मानवीय मूल्यों पर ज़ोर दिया

2. ग्लोबल मानवीय मदद में UAE की रैंकिंग

- कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा डोनर
- अलग-अलग देशों में पहला
- पिछले सालों में लगातार दुनिया भर के टॉप 5 डोनर में शामिल

3. ग्लोबल मानवीय मदद (GHA) के बारे में

- इन संगठनों द्वारा मॉनिटर किया जाता है:
- UNOCHA (मानवीय मामलों के कोऑर्डिनेशन के लिए UN ऑफ़िस)
- GHA रिपोर्ट / डेवलपमेंट इनिशिएटिव (DI)

फ़ंडिंग में शामिल हैं:

- खाने की मदद
- इमरजेंसी हेल्थ सर्विस
- रिफ्यूजी सपोर्ट
- संघर्ष के बाद फिर से बनाना

4. UAE द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले संकटों के प्रकार

- संघर्ष वाले इलाके (फ़िलिस्तीन, सूडान, सीरिया)

- आपदा प्रभावित इलाके
- रिफ्यूजी और IDP (इंटरनल डिसप्लेस्ड पर्सन्स) सपोर्ट
- मेडिकल इवैक्युएशन और फील्ड हॉस्पिटल
- इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन

लघु लेख

भारत ने ताजिकिस्तान के आयनी एयरबेस पर ऑपरेशन खत्म किया

भारत ने ताजिकिस्तान के आयनी एयरबेस से अपनी मिलिट्री मौजूदगी ऑफिशियली वापस ले ली है, जिससे विदेश में उसकी अकेली मिलिट्री ऑपरेशनल तैनाती खत्म हो गई है। यह वापसी सेंट्रल एशिया में जुड़ाव और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए भारत के नज़रिए में एक बड़ा बदलाव दिखाती है।

एयरबेस का बैकग्राउंड और डेवलपमेंट

आयनी एयरबेस, जिसे गिसार मिलिट्री एयरोड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास है। असल में यह सोवियत-काल का बेस था, इसे 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के साथ अपग्रेड किया गया था, जिसमें रनवे मॉडर्नाइज़ेशन, हैंगर कंस्ट्रक्शन, और नेविगेशन और एयर-ट्रैफिक सिस्टम लगाना शामिल था। एयरबेस ने भारत की रीजनल आउटरीच और सिक्योरिटी प्लानिंग में एक स्ट्रेटेजिक भूमिका निभाई।

भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व

आयनी की लोकेशन ने भारत को एक यूनिक जियोपॉलिटिकल फायदा दिया, क्योंकि यह अफ़गानिस्तान के करीब था और वखान कॉरिडोर के पास था, जो अफ़गानिस्तान को चीन से जोड़ने वाली एक पतली पट्टी है। इस बेस के ज़रिए, भारत अपने काउंटर-टेररिज़्म सहयोग को मज़बूत कर पाया, मानवीय मिशन चला पाया, और चीन और रूस के असर वाले इलाके में अपनी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी बनाए रख पाया। इस फ़ैसिलिटी का इस्तेमाल अफ़गानिस्तान की अस्थिरता से जुड़े इवैक्युएशन और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन के दौरान भी किया गया था।

भारत क्यों पीछे हटा?

कहा जाता है कि भारत के बाहर निकलने के बाद ताजिकिस्तान ने बाइलेटरल ऑपरेशनल एग्रीमेंट को खत्म होने के बाद रिन्यू नहीं किया। बदलते रीजनल पावर बैलेंस, रूस और चीन का बढ़ता असर, और अफ़गानिस्तान से US के हटने के बाद ऑपरेशनल रुकावटों ने मिलिट्री की अहमियत कम कर दी। भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक फ़ोकस तेज़ी से इंडो-पैसिफिक रीजन और अपनी बॉर्डर डिफ़ेंस क्षमताओं के मॉडर्नाइज़ेशन पर शिफ्ट किया है।

भारत की विदेश और सुरक्षा पॉलिसी पर असर

यह वापसी सेंट्रल एशिया में भारत की स्ट्रेटेजिक गहराई पर असर डालती है और टकराव वाले इलाकों के पास इसकी सीधी एयरपावर प्रोजेक्शन क्षमताओं को कम करती है। एनालिस्ट का मानना है कि इसके लिए भारत को इस इलाके के साथ डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी इनिशिएटिव को मज़बूत करना होगा, जैसे रीजनल फ़ोरम, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर और डिफ़ेंस पार्टनरशिप में हिस्सा लेना। यह कदम डिसएंगेजमेंट के बजाय पॉलिसी को फिर से बनाने का संकेत देता है।

सूडान का पतन: सत्ता, युद्ध और वैश्विक उपेक्षा की कीमत

सूडान अप्रैल 2023 से एक विनाशकारी गृहयुद्ध में घिरा हुआ है, जब जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुरहान के नेतृत्व वाली सूडानी सशस्त्र सेना (एसएएफ) और जनरल मोहम्मद हमदान डागालो (जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है) की कमान वाली रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच भीषण सत्ता संघर्ष छिड़ गया था। एक राजनीतिक विवाद के रूप में शुरू हुआ यह संघर्ष अब दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक बन गया है, जिसमें अकाल, बड़े पैमाने पर विस्थापन और नरसंहार के आरोप शामिल हैं।

संघर्ष की उत्पत्ति

इस युद्ध की जड़ें 2019 में लंबे समय से सत्ता पर काबिज उमर अल-बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बाद के अशांत परिणामों में निहित हैं, जिन्होंने 1989 में सत्ता हथिया ली थी। बड़े पैमाने पर सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण उनके पद से हटने से कुछ समय के लिए लोकतंत्र की उम्मीदें जगी थीं। हालाँकि, जल्द ही नागरिक और सैन्य गुटों के बीच तनाव बढ़ गया।

सेना और नागरिकों के बीच एक नाजुक सत्ता-साझाकरण समझौता स्थापित हुआ था, लेकिन अक्टूबर 2021 में बुरहान और हेमेदती के नेतृत्व में एक और तख्तापलट ने इसे ध्वस्त कर दिया। 1,00,000 सैनिकों वाले आरएसएफ को राष्ट्रीय सेना में एकीकृत करने की योजना और एकीकृत बल की कमान किसके हाथ में होगी, इस पर मतभेदों के कारण उनका गठबंधन टूट गया। दोनों जनरल अपनी व्यक्तिगत शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने पर आमादा दिखाई दिए।

यह गतिरोध 15 अप्रैल 2023 को खुले युद्ध में बदल गया, जब राजधानी खार्तूम में झड़पें शुरू हुईं और तेज़ी से पूरे देश में फैल गईं। आरएसएफ ने शुरुआत में शहर के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन महीनों की भीषण लड़ाई के बाद, सेना ने मार्च 2025 में फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया, और बमबारी और आग से तबाह शहर को पीछे छोड़ दिया।

आरएसएफ कौन हैं?

रैपिड सपोर्ट फोर्सेज की उत्पत्ति जंजावीद मिलिशिया से हुई थी, जो 2000 के दशक की शुरुआत में दारफुर संघर्ष के दौरान अत्याचारों के लिए कुख्यात थी, जब उन पर गैर-अरब समुदायों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया गया था। हेमेदती के नेतृत्व में, आरएसएफ एक दुर्जेय अर्धसैनिक बल के रूप में विकसित हुआ, जिसने यमन और लीबिया में संघर्षों में भाग लिया और सूडान की सोने की खदानों पर नियंत्रण के माध्यम से खुद को वित्तपोषित किया।

सूडानी सेना ने संयुक्त अरब अमीरात और लीबिया के सरदार जनरल खलीफा हफ्तार पर आरएसएफ को हथियार और धन मुहैया कराने का आरोप लगाया है—दोनों ही आरोपों से इनकार

करते हैं। जून 2025 में, आरएसएफ ने लीबिया और मिस्र के साथ सूडान की सीमाओं पर कब्ज़ा कर लिया और बाद में दारफुर में सेना के अंतिम प्रमुख गढ़ अल-फशर पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण मिल गया।

सेना नियंत्रण और चल रही लड़ाइयाँ

जबकि आरएसएफ पश्चिमी सूडान पर हावी है, सेना उत्तर और पूर्व के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखती है, जिसका मुख्य समर्थन मिस्र करता है, जो नील नदी के माध्यम से सीमा और महत्वपूर्ण जल संसाधनों को साझा करता है।

जनरल बुरहान अब लाल सागर पर स्थित पोर्ट सूडान से शासन करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार का घर है, हालाँकि यह शहर अभी भी खतरे में है - मार्च 2025 में आरएसएफ के एक बड़े ड्रोन हमले का शिकार हो सकता है।

2025 में सेना द्वारा खार्तूम और गीज़ीरा राज्य पर पुनः कब्ज़ा करना अस्थायी जीत थी, लेकिन अल-फ़शर का पतन एक गंभीर झटका था, जिससे लाखों लोग घेराबंदी में फँस गए, भुखमरी का सामना कर रहे थे, और मानवीय सहायता से वंचित हो गए।

दारफुर में नरसंहार और अत्याचार

दारफुर में व्यापक अत्याचारों की खबरों ने इस क्षेत्र के काले अतीत की यादें ताज़ा कर दी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और सहायता एजेंसियों का कहना है कि आरएसएफ और उसके सहयोगी अरब मिलिशिया मसालित और अन्य गैर-अरब समूहों के खिलाफ जातीय सफाया अभियान चला रहे हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) के अनुसार, अल-गेनीना में हज़ारों लोग मारे गए और बचे लोगों ने सुनियोजित हत्याओं और यौन हिंसा की गवाही दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से घोषणा की कि आरएसएफ बलों ने नरसंहार किया है, जिसमें पुरुषों और लड़कों की सामूहिक हत्याओं, लक्षित बलात्कारों और नागरिकों पर जानबूझकर किए गए हमलों के सबूत दिए गए हैं।

सूडान की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में एक मामला दायर किया जिसमें यूएई पर आरएसएफ को वित्त पोषण में मिलीभगत का आरोप लगाया गया, लेकिन आईसीजे ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में इसे खारिज कर दिया। आरएसएफ नरसंहार करने से इनकार करता है और दावा करता है कि हिंसा आदिवासी विवादों से उपजी है।

इस बीच, अल-फ़शर से हुई नई नरसंहार की घटनाओं ने शहर में फंसे लगभग 2,50,000 नागरिकों के लिए चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

विफल शांति प्रयास और वैश्विक प्रतिक्रिया

सऊदी अरब और बहरीन में कई दौर की शांति वार्ताएँ युद्धविराम तक पहुँचने में विफल रही हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि दोनों पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवीय समूहों ने वैश्विक ध्यान की कमी की निंदा की है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने सुझाव दिया है कि नस्लवाद आंशिक रूप से अफ्रीकी संघर्षों के प्रति दुनिया की उदासीनता की व्याख्या करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह ने वैश्विक कूटनीति को "सुस्त" बताया, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रतिक्रिया को "बेहद अपर्याप्त" बताया। मानवीय गतिविधियाँ चरमरा रही हैं—80% आपातकालीन रसोई बंद हो गई हैं, और 2.4 करोड़ से ज़्यादा लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और सहायता कार्यकर्ता चेतावनी देते हैं कि सूडान का युद्ध अब दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय आपदा है, जो गाजा और यूक्रेन के संकटों से भी बड़े पैमाने पर है।

संकट के कगार पर एक राष्ट्र

अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश, सूडान, जिसकी आबादी 4.6 करोड़ है, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम हैं और अरबी और अंग्रेज़ी बोलते हैं। अपनी विशाल प्राकृतिक संपदा, खासकर सोने के बावजूद, यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। गृहयुद्ध ने इसकी नाज़ुक अर्थव्यवस्था के बचे-खुचे हिस्से को तहस-नहस कर दिया है—सरकारी राजस्व में 80% की गिरावट आई है, और लाखों लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

आरएसएफ के क्षेत्रीय प्रभुत्व और पूर्व में सेना की मज़बूत पकड़ के साथ, सूडान एक और विभाजन के खतरे में है, जो 2011 में दक्षिण सूडान के अलगाव की याद दिलाता है। जब तक तत्काल अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई नहीं की जाती, यह संघर्ष देश को स्थायी रूप से खंडित करने और इसके प्रभाव में फंसे लाखों लोगों की पीड़ा को और गहरा करने का खतरा पैदा करता है।

IMPORTANCE
To commemorates the enactment of the Indian Legal Services Authorities Act 1987, which came into force on 9th November 1995.

MOTTO
To spread awareness for ensuring reasonable fair and justice procedure for all citizens.

NALSA
Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987. To provide free Legal Services to the weaker sections of the society. Chief Justice of India serves as the Patron-in-Chief NALSA

NOTE
On this day, Lok Adalats are organized across the country to make safe the legal system operations and encourages righteousness of people on the equality basis.

Inception: 1955 **By:** Supreme Court of India

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

अमित शाह ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किए, हर शहर में एक UCB का टारगेट

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दो नई डिजिटल पहल — सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन — लॉन्च कीं, जिनका मकसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (UCBs) के बीच डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देना और भारत के तेज़ी से बदलते फाइनेंशियल इकोसिस्टम में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पक्का करना है। उन्होंने नई दिल्ली में अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर पर दो दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इन ऐप का उद्घाटन किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि कैशलेस इकॉनमी में कोऑपरेटिव बैंकों के बने रहने और बढ़ने के लिए डिजिटलाइज़ेशन ज़रूरी है।

खास घोषणाएँ

दो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किए गए:

- सहकार डिजी पे: डिजिटल पेमेंट के लिए
- सहकार डिजी लोन: ऑनलाइन क्रेडिट सर्विस के लिए
- टारगेट: दो साल के अंदर 1,500 UCBs को इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाना।
- लक्ष्य: पाँच साल के अंदर दो लाख से ज़्यादा आबादी वाले हर शहर में कम से कम एक नया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (UCB) बनाना।
- निर्देश: सफल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में बदलना।

सेक्टर के सुधार और परफॉर्मेंस

पिछले दो सालों में UCB सेक्टर में NPA 2.8% से घटकर 0.6% हो गया है — जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काफी सुधार दिखा है। शाह ने कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने और मॉडर्न बनाने में अपनी भूमिका के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तारीफ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि UCB को युवाओं और छोटे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, और फाइनेंशियल इनक्लूजन और रोजगार बनाने पर फोकस करना चाहिए।

ऐप्स के बारे में

- सहकार डिजी पे: कोऑपरेटिव बैंक कस्टमर्स के लिए सुरक्षित डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को मुमकिन बनाता है, जिससे कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा मिलता है।
- सहकार डिजी लोन: कोऑपरेटिव बैंकिंग में बिज़नेस करने में आसानी के लिए डिजिटल लोन प्रोसेसिंग और तेज़ मंज़ूरी देता है।
- ये प्लेटफ़ॉर्म UPI, आधार-इनेबल्ड सर्विसेज़ और RBI-रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होंगे।

अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (UCB) के बारे में

UCB कोऑपरेटिव सिद्धांतों पर काम करते हैं और इन्हें रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) और रजिस्ट्रार ऑफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिलकर रेगुलेट करते हैं। वे छोटे बिज़नेस, कम इनकम वाले ग्रुप और सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों को सस्ता क्रेडिट देने में अहम भूमिका निभाते हैं। 2025 तक, भारत में शहरी और सेमी-अर्बन इलाकों में 1,500 से ज़्यादा UCB हैं।

सरकार ने NPS और UPS के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LC75 और BLC निवेश विकल्पों का विस्तार किया

भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) दोनों के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LC75 (जीवन चक्र निधि 75) और BLC (संतुलित जीवन चक्र) निवेश विकल्पों के विस्तार को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य सेवानिवृत्ति बचत के प्रबंधन में अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करना है और यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की गैर-सरकारी अंशदाताओं के साथ समानता की लंबे समय से चली आ रही माँग के अनुरूप है, जिनके पास पहले से ही इन विकल्पों तक पहुँच थी। नए प्रावधान के तहत, कर्मचारियों के पास अब निवेश विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच होगी, जिनमें शामिल हैं:

डिफ़ॉल्ट विकल्प (स्वचालित परिसंपत्ति आवंटन)

LC75 (आक्रामक जीवन चक्र निधि) - उच्च जोखिम उठाने की क्षमता वाले लोगों के लिए उपयुक्त, जो 75% तक इक्विटी में निवेश करते हैं।

BLC (संतुलित जीवन चक्र निधि) - मध्यम जोखिम के साथ इक्विटी और ऋण जोखिम को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

इस निर्णय से कर्मचारियों को अपने पेंशन पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने, सूचित वित्तीय नियोजन को बढ़ावा देने और विविध निवेशों के माध्यम से दीर्घकालिक कोष वृद्धि सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

नए विकल्प प्रस्तुत किए गए:

- LC75 (जीवन चक्र निधि 75) - उच्च इक्विटी निवेश (75% तक), जिसमें उम्र बढ़ने के साथ क्रमिक कमी आती है।
- BLC (संतुलित जीवन चक्र) - मध्यम रिटर्न और कम जोखिम के लिए संतुलित इक्विटी-ऋण निवेश।
- उद्देश्य: लचीलापन बढ़ाना और कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति निवेशों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएँ:

- ग्लाइड पाथ मैकेनिज्म (उम्र के साथ स्वचालित जोखिम में कमी)
- विस्तृत स्वचालित विकल्प
- सूचित और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना के लिए समर्थन
- महत्व: सरकारी और गैर-सरकारी NPS ग्राहकों के बीच समानता सुनिश्चित करता है।

- कार्यान्वयन प्राधिकरण: पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

2026 में नई GDP सीरीज़ जारी होगी: MoSPI ने तरीकों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया

मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया है जिसमें GDP बेस ईयर को 2022–23 में बदलने से पहले भारत के नेशनल अकाउंट्स में बड़े तरीकों में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। बदली हुई GDP सीरीज़ ऑफिशियली 27 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। इस बदलाव की देखरेख एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स (ACNAS) कर रही है, जिसके चेयरमैन इकोनॉमिस्ट बी.एन. गोल्डर हैं, और इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़, स्टेट गवर्नमेंट्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन्स और रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन्स के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। कमिटी का काम डेटा सोर्स को अपडेट करना और GDP कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाले एस्टिमेशन मेथड्स को बेहतर बनाना है।

मुख्य प्रस्तावित बदलाव:

1. अपडेटेड बेस ईयर: 2022–23

- नई सीरीज़ GDP बेस ईयर को 2011–12 से 2022–23 में बदल देगी।
- इकॉनमी में स्ट्रक्चरल बदलावों को दिखाने के लिए बेस-ईयर में समय-समय पर बदलाव किया जाता है।

2. प्रोडक्शन और इनकम अप्रोच पर फोकस (डिस्कशन पेपर–1)

- सेक्टरल आउटपुट के लिए इस्तेमाल होने वाले डेटासेट को अपडेट करना।
- अलग-अलग सेक्टर में इनकम फ्लो का बेहतर मेज़रमेंट।
- मौजूदा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए नॉमिनल और रियल GDP कैलकुलेशन में बदलाव।
- पिछले दशक के टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बदलावों को शामिल करना।

3. दूसरा डिस्कशन पेपर (आने वाला)

एक्सपेंडिचर अप्रोच (प्राइवेट कंजम्पशन, सरकारी खर्च, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट) में बदलावों पर फोकस करेगा।

4. मकसद: ट्रांसपेरेंसी और डेटा एक्यूरेसी में सुधार करना

- MoSPI मेथड को फाइनल करने से पहले पब्लिक, एक्सपर्ट और इंस्टीट्यूशनल फीडबैक मांग रहा है।
- भारत के नेशनल अकाउंट्स को UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स (UN-SNA 2008) स्टैंडर्ड्स के करीब लाने की कोशिश।

GDP बेस ईयर में बदलाव क्यों ज़रूरी हैं

- स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक बदलावों (डिजिटल इकोनॉमी, सर्विसेज़ एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स) को दिखाएं।
- इन्फ्लेशन-एडजस्टेड (रियल) GDP की एक्यूरेसी में सुधार करें।
- पक्का करें कि पॉलिसी प्लानिंग में अप-टू-डेट इकोनॉमिक बेंचमार्क का इस्तेमाल हो।

RBI ने भारत-EU क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए UPI–TIPS इंटरलिंकेज की घोषणा की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को मज़बूत करने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) के TARGET इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट (TIPS) सिस्टम के साथ भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को इंटरलिंक करने की घोषणा की है। यह कदम क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को बढ़ाने के G20 रोडमैप के साथ है, जो इंटरनेशनल रेमिटेंस को सस्ता, तेज़, ट्रांसपेरेंट और सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने पर फोकस करता है। RBI और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ लगातार बातचीत की है, जिसके बाद दोनों पक्ष UPI–TIPS कनेक्टिविटी के लिए रियलाइज़ेशन फ़ेज़ शुरू करने पर सहमत हुए हैं। एक बार चालू हो जाने पर, यह लिंक भारत और EU सदस्य देशों में यूज़र्स के लिए रियल-टाइम, सुरक्षित डिजिटल पेमेंट चैनल का इस्तेमाल करके आसान, कम लागत वाले रेमिटेंस को मुमकिन बनाएगा। आने वाले फेज़ में RBI, NIPL और ECB के बीच टेक्निकल इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और सेटलमेंट मैकेनिज्म शामिल होंगे।

UPI के बारे में

- लॉन्च किया: NPCI ने 2016 में
- फीचर्स: तुरंत ट्रांसफर, 24×7 अवेलेबिलिटी, QR-बेस्ड पेमेंट
- दुनिया भर में मंज़ूर: UAE, सिंगापुर, फ्रांस (एफिल टावर), श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, भूटान, वगैरह।
- भारत के फाइनेंशियल इनक्लूजन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का हिस्सा।

TIPS (TARGET इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट) के बारे में

- ऑपरेट करता है: यूरोसिस्टम (ECB + यूरोज़ोन नेशनल सेंट्रल बैंक)
- लॉन्च हुआ: नवंबर 2018
- मकसद: यूरोज़ोन में पेमेंट का इंस्टेंट सेटलमेंट
- करेंसी सपोर्टेड: यूरो

UPI–TIPS इंटरलिंकेज का महत्व

पहला बड़ा इंडिया-EU डिजिटल पेमेंट लिंक

इसमें मदद करता है:

1. सस्ता रेमिटेंस
2. इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट
3. सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर

इसके लिए उपयोगी:

- यूरोप में इंडियन डायस्पोरा
- भारत आने वाले EU टूरिस्ट
- भारतीय स्टूडेंट, बिज़नेस और एक्सपोर्टर

भारत और बहरीन ने एनपीसीआई-बेनिफिट साझेदारी के माध्यम से वास्तविक समय में सीमा पार भुगतान को सक्षम बनाया

नया फिनटेक सहयोग

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की वैश्विक शाखा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने भारत और बहरीन के बीच वास्तविक समय में सीमा पार धन प्रेषण को सक्षम करने के लिए बहरीन की अग्रणी फिनटेक फर्म, बेनिफिट के साथ साझेदारी की है।

यूपीआई-ईएफटीएस एकीकरण

यह साझेदारी भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को फावरी+ सेवा के माध्यम से बहरीन के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम (ईएफटीएस) से जोड़ती है, जिससे दोनों देशों के उपयोगकर्ता तुरंत और सुरक्षित रूप से धन भेज और प्राप्त कर सकते हैं।

नियामक समर्थन

यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन (सीबीबी) के मार्गदर्शन में विकसित की गई थी, जो डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मजबूत संस्थागत सहयोग को दर्शाती है।

फिनटेक संबंधों को मजबूत करना

यह साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहरीन यात्रा के दौरान 2019 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन पर आधारित है। दिसंबर 2024 में आयोजित चौथी भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक में इसे और मज़बूत किया गया, जिसमें फिनटेक सहयोग पर ज़ोर दिया गया।

राजनयिक जुड़ाव

2025 में, भारतीय राजदूत विनोद के. जैकब ने फिनटेक और सीमा पार डिजिटल भुगतान संबंधों को बढ़ाने के लिए बहरीन के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ चर्चा की।

आर्थिक प्रभाव

इस पहल से वित्तीय संपर्क, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें दो-तरफ़ा निवेश 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा।

मुख्य परिणाम

यह UPI-Fawri+ लिंकेज डिजिटल सहयोग में एक बड़ा कदम है, जो वैश्विक फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में बहरीन की स्थिति को मज़बूत करता है।

बहरीन

- राजधानी: मनामा
- मुद्रा: बहरीनी दीनार
- राजा: हमद बिन ईसा अल खलीफा
- क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री: सलमान बिन हमद अल खलीफा

भारत और इक्वाडोर ने राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत की विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा और इक्वाडोर की विदेश एवं मानव गतिशीलता मामलों की मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड की यात्रा के दौरान, भारत और इक्वाडोर ने अपने राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमओयू का केंद्र बिंदु और दायरा

यह समझौता प्रशिक्षण कार्यक्रमों, राजनयिक संकायों के आदान-प्रदान और राजनयिक एवं विदेश सेवा प्रशिक्षण में संस्थागत संबंधों को मजबूत करने सहित संयुक्त क्षमता निर्माण प्रयासों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना भी है।

राजनयिक पहुँच और रणनीतिक संदर्भ

लैटिन अमेरिका के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव के बीच, मंत्री मार्गेरिटा ने इक्वाडोर के क्विटो में भारतीय दूतावास का उद्घाटन करके भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यह कदम वैश्विक दक्षिण में दक्षिण-दक्षिण सहयोग और राजनयिक पहुँच पर भारत के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।

भारत-इक्वाडोर प्रमुख सहयोग: व्यापार, रक्षा, संस्कृति, शिक्षा और कूटनीति

व्यापार-ढांचे का पहला प्रमुख कदम 2015 जेटको प्रोटोकॉल था। एक अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) पर 2019 से बातचीत चल रही है। रक्षा संबंध समझौतों से आगे जाते हैं: वास्तविक उपकरण आपूर्ति (एएलएच हेलीकॉप्टर, 2008) इसकी गहराई को उजागर करती है। इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र सुधारों (जैसे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है - जो राजनयिक संरेखण का संकेत देता है। संस्कृति, शिक्षा, आईटी प्रशिक्षण बहु-क्षेत्रीय सहयोग का हिस्सा हैं।

इक्वाडोर

- राजधानी: क्विटो
- राष्ट्रपति: डैनियल नोबोआ
- मुद्रा: अमेरिकी डॉलर
- आधिकारिक भाषा: स्पेनिश

महाराष्ट्र ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

महाराष्ट्र सरकार ने अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन एवं राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के तटीय बुनियादी ढाँचे में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम और ब्लू इकोनॉमी विजन के अनुरूप बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, समुद्री रसद में वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

अबू धाबी बंदरगाह समूह:
- स्थापना: 2006
- मुख्यालय: अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
- कार्य: वैश्विक स्तर पर बंदरगाहों, रसद केंद्रों और समुद्री सेवाओं का प्रबंधन।

राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखण

सागरमाला कार्यक्रम (2015 में प्रारंभ):
भारत के तटरेखा के साथ बंदरगाह-आधारित विकास, रसद दक्षता और औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है।

मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030:
कार्गो क्षमता बढ़ाने, वैश्विक बंदरगाह रैंकिंग और हरित शिपिंग प्रथाओं का रोडमैप।

ब्लू इकोनॉमी नीति ढाँचा:
आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित।

महाराष्ट्र:
- राजधानी: मुंबई
- उपमुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाह:
- मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी/न्हावा शेवा)
- दिघी पोर्ट
- केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री (2025 तक): सर्बानंद सोनोवाल
- भारत का समुद्री नीति केंद्र: सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)

नोट: भारत-यूएई सीईपीए पर हस्ताक्षर: फरवरी 2022

IFFI ने UNICEF के साथ पार्टनरशिप की, ताकि बचपन की खूबसूरती और मुश्किलों को दिखाने वाली फिल्में दिखाई जा सकें

IFFI-UNICEF पार्टनरशिप बच्चों के सिनेमा को दिखाएगी: इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) ने UNICEF के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि ऐसी फिल्में दिखाई जा सकें जो बचपन की खुशियों और मुश्किलों को दिखाती हैं।

बच्चों की ज़िंदगी पर फोकस करने वाली पांच फिल्में: UNICEF इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव सिंथिया मैककैफ्रे ने कहा कि भारत, कोसोवो, मिस्र और दक्षिण कोरिया की पांच फिल्में दिखाई जा रही हैं, जो अलग-अलग कल्चर में बच्चों की दिक्कतों, चुनौतियों और मौकों को दिखाएंगी।

कहानी कहने के एक नए जॉनर को बढ़ाना: IFFI बच्चों पर फोकस करने वाले सिनेमा के एक अनोखे जॉनर को खोलने में मदद कर रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी फिल्मों की डिमांड बढ़ सकती है।

शिक्षा में भारत की कामयाबी: मैककैफ्रे ने प्राइमरी शिक्षा लेवल पर जेंडर पैरिटी के UNICEF के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने के लिए भारत को बधाई दी।

76 साल की पार्टनरशिप: उन्होंने कहा कि भारत के साथ UNICEF की लंबी पार्टनरशिप दोनों को बेहतर बनाने वाली रही है, और भारत से मिली सीख से दुनिया भर में बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिली है।

IFFI
- जगह: पणजी, गोवा, भारत
- शुरूआत: 24 जनवरी 1952
- होस्ट: गोवा सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ़ फ़िल्म फ़ेस्टिवल्स

UNICEF
- फ़ाउंडर: लुडविक राजचमन
- टाइप: फ़ंड
- हेडक्वार्टर: न्यूयॉर्क सिटी, U.S.
- एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर: कैथरीन एम. रसेल
- पेरेंट ऑर्गनाइज़ेशन: यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली

ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप

इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (ACITI) पार्टनरशिप शुरू की है। यह एक तीन-तरफ़ा सहयोग है जिसका मकसद ज़रूरी और नई टेक्नोलॉजी पर सहयोग को मज़बूत करना है। इस फ्रेमवर्क की घोषणा जोहान्सबर्ग में हुए G20 समिट के दौरान की गई।

ACITI के मुख्य उद्देश्य
ज़रूरी और नई टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाना, जैसे:
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
- क्वांटम टेक्नोलॉजी
- ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी
- ज़रूरी मिनरल प्रोसेसिंग
- ग्लोबल सप्लाई चेन की मज़बूती को मज़बूत करना, खासकर ज़रूरी मिनरल के लिए।
- क्लाइमेट-फ्रेंडली इनोवेशन को बढ़ावा देकर नेट-ज़ीरो एमिशन की ओर ग्लोबल बदलाव में मदद करना।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।

रणनीतिक महत्व
- ACITI पार्टनरशिप मौजूदा इंडिया-ऑस्ट्रेलिया, इंडिया-कनाडा और ऑस्ट्रेलिया-कनाडा के द्विपक्षीय टेक पहलों को पूरा करती है। ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पर फोकस भारत के 2070 तक नेट-ज़ीरो हासिल करने के लक्ष्य से मेल खाता है।
- AI डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर अपनाने पर सहयोग का मकसद तीनों देशों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी और डिजिटल गवर्नेंस को बेहतर बनाना है।
- इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजिक नेटवर्क को मजबूत करता है, सप्लाई चेन की कमजोरियों और सिंगल-कंट्री सोर्सिंग पर निर्भरता का मुकाबला करता है।

लागू करने की टाइमलाइन

भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अधिकारी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने और खास प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करने के लिए 2026 की पहली तिमाही में मिलेंगे।

भारत के टेक लक्ष्य:

- भारत का लक्ष्य 2025-26 तक $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है।
- भारत कृषि, हेल्थकेयर और डिजिटल पेमेंट जैसे सेक्टर में AI अपनाने वाले टॉप देशों में से एक है।

ज़रूरी मिनरल्स का महत्व:

- लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे मिनरल्स EV बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं।
- ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े लिथियम प्रोड्यूसर्स में से एक है; कनाडा में निकल और कोबाल्ट भरपूर मात्रा में है।

G20 जोहान्सबर्ग 2025 थीम:

ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल एनर्जी और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को मजबूत करने पर फोकस।

साउथ कोरिया-US ने $350 बिलियन के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट MoU पर साइन किए

साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने U.S. के अंदर कई प्रायोरिटी सेक्टर्स में $350 बिलियन के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को मुमकिन बनाने के लिए एक बड़े मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए हैं। यह अनाउंसमेंट साउथ कोरिया के इंडस्ट्री मिनिस्टर किम जंग-क्वान ने की। दोनों देशों का टारगेट जनवरी 2029 तक खास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनल और सिलेक्ट करना है। इन इन्वेस्टमेंट्स के इन पर ज़्यादा फोकस होने की उम्मीद है:

- सेमीकंडक्टर
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और बैटरी
- क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन
- एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सिक्योरिटी
- स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस

यह एग्रीमेंट इकोनॉमिक रिश्तों को मज़बूत करता है और इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सपोर्ट करता है।

यह इन्वेस्टमेंट चीन पर सप्लाई चेन डिपेंडेंस को कम करने के U.S. के गोल्स के साथ अलाइन है।

साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और EV बैटरी में एक मेन ग्लोबल प्लेयर बना हुआ है। और बातें:

- U.S. में इन्वेस्ट करने वाली बड़ी साउथ कोरियन कंपनियाँ: सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, SK हाइनिक्स, हुंडई मोटर्स, LG एनर्जी सॉल्यूशन
- U.S. घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए CHIPS & साइंस एक्ट जैसी पहलों के तहत ऐसे इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है।
- साउथ कोरिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है (IMF का अनुमान)।
- दोनों देशों के बीच संबंधों का फ्रेमवर्क: साउथ कोरिया-US अलायंस (1953)
- मुख्य डिफेंस सहयोग पहल: वाशिंगटन डिक्लेरेशन 2023

भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ₹10,000 करोड़ के योगदान की घोषणा की

भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना को सपोर्ट करने के लिए ₹10,000 करोड़ की फाइनेंशियल मदद की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत डिप्लोमैटिक और डेवलपमेंटल पार्टनरशिप और मजबूत होगी। यह घोषणा एक इवेंट के दौरान की गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक शामिल हुए।

भारत के प्रति भूटान का आभार

राजा जिग्मे खेसर वांगचुक ने भारत के प्रति गहरा आभार जताते हुए कहा कि "भारत हमेशा भूटान के साथ खड़ा रहा है, और इसलिए भूटान भी भारत के साथ खड़ा है। " उन्होंने भूटान की डेवलपमेंट जर्नी में भारत के लगातार सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और दोनों हिमालयी पड़ोसियों के बीच शेयर्ड वैल्यूज़ और दोस्ती को दोहराया।

होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस: ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (GNH)

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भूटान के राजा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि किसी देश का डेवलपमेंट सिर्फ़ GDP से नहीं, बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (GNH) से मापा जाना चाहिए — यह एक अनोखा कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरनमेंट और सोशल वेल-बीइंग के साथ जोड़ता है। यह भूटान के सस्टेनेबल और इनक्लूसिव ग्रोथ के विज़न से मेल खाता है।

वाराणसी में भूटानी मंदिर के लिए ज़मीन का आवंटन

कल्चरल कोऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर, भारत सरकार वाराणसी में एक रॉयल भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस बनाने के लिए ज़मीन देगी, जो दोनों देशों के बीच शेयर्ड स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक है।

भूटान:

- भूटान के राजा: जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक
- भूटान के प्रधानमंत्री: शेरिंग तोबगे
- भूटान की राजधानी: थिम्पू
- करेंसी: न्गुलट्रम (BTN) — भारतीय रुपये से जुड़ी
- ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स (GNH): भूटान ने सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट को मापने के लिए शुरू किया

भारत-भूटान संबंध:

भारत 1949 में भूटान की आज़ादी को मान्यता देने वाला पहला देश था। दोस्ती और सहयोग की संधि (1949) द्विपक्षीय संबंधों को कंट्रोल करती है। भारत भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड और डेवलपमेंट पार्टनर बना हुआ है।

HDFC बैंक 2025 के लिए भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स में टॉप पर, TCS को पीछे छोड़ा

HDFC बैंक, जिसकी ब्रांड वैल्यू $44.9 बिलियन है, ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) को पीछे छोड़कर 2025 की कंटार ब्रांडज़ रैंकिंग में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। 2014 से बैंक की ब्रांड वैल्यू 377% बढ़ी है।

HDFC बैंक टॉप पर क्यों पहुँचा

HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद, बैंक ने ब्रांड-लेड इनोवेशन को मज़बूत किया, जिसमें "विजिल आंटी" सेफ्टी मैस्कॉट और 30-मिनट की डिजिटल ऑटो लोन सुविधा जैसे जाने-पहचाने एसेट्स पेश किए गए।

2025 में भारत का ब्रांड लैंडस्केप

टॉप 100 भारतीय ब्रांड्स की कुल वैल्यू $523.5 बिलियन है—जो भारत की GDP का लगभग 13% है—और कुल ब्रांड वैल्यू साल-दर-साल 6% बढ़ी है। इनमें से 34 ब्रांड्स में ग्रोथ हुई, और 18 नए आए हैं।

खास नए और तेज़ी से आगे बढ़ने वाले ब्रांड

- अल्ट्राटेक सीमेंट $14.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ नंबर 7 पर शुरू हुआ, जिसे मज़बूत कस्टमर भरोसे और घर बनाने के तरीकों से बढ़ावा मिला।
- वेस्टसाइड ($3.3 बिलियन) और ज़ूडियो ($2.5 बिलियन) नंबर 38 और नंबर 52 पर आए।
- ज़ोमैटो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड बना रहा, जिसकी वैल्यू लगभग दोगुनी होकर $6 बिलियन हो गई और यह नंबर 21 पर पहुँच गया।

Kantar BrandZ टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025

रैंक	ब्रांड	कैटेगरी	ब्रांड वैल्यू 2025 (US$M)
1	HDFC बैंक	फाइनेंशियल सर्विसेज़	44,988
2	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़	बिज़नेस टेक्नोलॉजी और सर्विसेज़ प्लेटफॉर्म्स	44,233
3	एयरटेल	टेलीकॉम प्रोवाइडर्स	41,069
4	इंफोसिस	बिज़नेस टेक्नोलॉजी और सर्विसेज़ प्लेटफॉर्म्स	25,540
5	ICICI बैंक	फाइनेंशियल सर्विसेज़	20,633
6	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	फाइनेंशियल सर्विसेज़	18,808
7	अल्ट्राटेक सीमेंट	मटीरियल्स	14,524
8	जियो	टेलीकॉम प्रोवाइडर्स	14,055
9	HCL टेक	बिज़नेस टेक्नोलॉजी और सर्विसेज़ प्लेटफॉर्म्स	12,826
10	LIC	फाइनेंशियल सर्विसेज़	10,347

मुंबई और दिल्ली दुनिया के टॉप 10 अरबपति शहरों में शामिल — हुरुन ग्लोबल रिच रिपोर्ट 2025

हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट (2025) के मुताबिक, मुंबई और नई दिल्ली दुनिया के टॉप दस अरबपति शहरों में शामिल हैं, जो भारत की बढ़ती आर्थिक और एंटरप्रेन्योरियल ताकत को दिखाता है। मुंबई — भारत की फाइनेंशियल कैपिटल — ने 92 अरबपतियों के साथ दुनिया भर में तीसरा स्थान हासिल किया है, और बीजिंग (91) और शंघाई (87) जैसे बड़े एशियाई हब को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली पहली बार टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुई, इंडस्ट्रियल, टेक और रियल एस्टेट ग्रोथ की वजह से 57 अरबपतियों के साथ 9वें स्थान पर रही। न्यूयॉर्क शहर 119 अरबपतियों के साथ ग्लोबल लिस्ट में टॉप पर रहा, उसके बाद लंदन (97) रहा, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर उनके दबदबे की पुष्टि हुई।

वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें भारत सबसे तेजी से बढ़ते वेल्थ हब में से एक बनकर उभरा है।

अरबपति शहरों की ग्लोबल रैंकिंग (2025)

रैंक	शहर	अरबपतियों की संख्या
1	न्यूयॉर्क	119
2	लंदन	97
3	मुंबई	92
4	बीजिंग	91
5	शंघाई	87
6	शेन्ज़ेन	84
7	हांगकांग	65
8	मॉस्को	59
9	नई दिल्ली	57
10	सैन फ्रांसिस्को	52

अतिरिक्त प्रमुख तथ्य:

रिपोर्ट पब्लिश करने वाला: हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट — जो हर साल हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट बनाने के लिए जाना जाता है।

प्लेटफ़ॉर्म जिस पर शेयर किया गया: वर्ल्ड ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स (X के ज़रिए, पहले ट्विटर)।

भारत के अरबपति शहर:

मुंबई (तीसरा) — मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज़) और गौतम अडानी (अडानी ग्रुप) समेत कई भारतीय उद्योगपतियों का घर।

नई दिल्ली (9वां) — रियल एस्टेट, टेलीकॉम और टेक सेक्टर में बिज़नेस टाइकून के लिए उभरता हुआ हब।

- अरबपतियों की गिनती में भारत की जगह (देश के हिसाब से): चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है।
- ट्रेंड इनसाइट: पिछले दस सालों में भारत में अरबपतियों की संख्या तीन गुना से ज़्यादा बढ़ी है, जो तेज़ी से आर्थिक बढ़ोतरी और टेक-सेक्टर में तेज़ी को दिखाता है।

मुंबई 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर: टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स

मुंबई को टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर बताया गया है, जिसने बीजिंग, शंघाई, चियांग माई और हनोई जैसे बड़े एशियाई शहरों को पीछे छोड़ दिया है।

सर्वे में लोगों से उनके शहर को कल्चर, नाइटलाइफ़, खाने, जीवन की क्वालिटी और पूरी खुशी के आधार पर रेट करने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 94% मुंबईकरों ने कहा कि उनका शहर उन्हें खुश रखता है — जो एशिया में सबसे ज़्यादा है।

मुंबई को सबसे खुशहाल शहर क्या बनाता है

मुंबई की एनर्जेटिक लाइफस्टाइल, अलग-अलग तरह का कल्चर और अच्छे मौकों ने इसे टॉप पर लाने में मदद की है। सर्वे के खास आंकड़ों में शामिल हैं:

- 94% लोगों ने कहा कि यह शहर उन्हें खुश रखता है।
- 89% लोग मुंबई में कहीं और से ज़्यादा खुश महसूस करते हैं।
- 88% का मानना है कि शहर के लोग पॉजिटिव हैं।
- 87% का कहना है कि हाल ही में मुंबई में खुशी बढ़ी है। शहर का वाइब्रेंट एंटरटेनमेंट सीन, चहल-पहल वाली सोशल लाइफ, करियर के मौके और मशहूर स्ट्रीट फूड कल्चर को खुशी बढ़ाने वाले बड़े कारण माना गया है।

साउथ ईस्ट एशिया के टॉप परफॉर्मर

- थाईलैंड के चियांग माई और वियतनाम के हनोई ने चौथा और पाँचवाँ स्थान हासिल किया।
- दोनों शहरों की तारीफ इन वजहों से हुई:
- हरी-भरी जगहें
- आरामदायक लाइफस्टाइल
- कम्युनिटी की मज़बूत भावना
- शांति और बैलेंस्ड लाइफ चाहने वाले लोग इन्हें पसंद करते हैं।

कुछ बड़े शहरों की रैंक नीचे क्यों है

सियोल, सिंगापुर और टोक्यो जैसे शहर खुशी के पैमाने पर नीचे रैंक पर हैं। टोक्यो में, सिर्फ़ 70% लोगों ने कहा कि वे अपने शहर में खुश महसूस करते हैं — इसकी वजह काम के लंबे घंटे और तेज़ शहरी ज़िंदगी है। यह मॉडर्न शहरों में मेंटल हेल्थ, पब्लिक पार्क और शहरी आराम की जगहों की बढ़ती अहमियत को दिखाता है।

एशिया के टॉप 10 सबसे खुश शहर (2025)

1. मुंबई, इंडिया
2. बीजिंग, चीन
3. शंघाई, चीन
4. चियांग माई, थाईलैंड
5. हनोई, वियतनाम
6. जकार्ता, इंडोनेशिया
7. हांगकांग
8. बैंकॉक, थाईलैंड
9. सिंगापुर
10. सियोल, साउथ कोरिया

दुनिया के टॉप 10 सबसे खुश शहर (2025)

1. अबू धाबी, UAE
2. मेडेलिन, कोलंबिया
3. केप टाउन, साउथ अफ्रीका
4. मेक्सिको सिटी, मैक्सिको
5. मुंबई, इंडिया
6. बीजिंग, चीन
7. शंघाई, चीन
8. शिकागो, USA
9. सेविले, स्पेन
10. मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया

टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में

पब्लिश किया है: टाइम आउट, एक ग्लोबल लाइफस्टाइल और ट्रैवल मैगज़ीन ने। मकसद: यह पता लगाना कि लोग अपने शहरों को कल्चर, खाने, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और खुशी के मामले में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं।

सर्वे बेस: 50+ बड़े ग्लोबल शहरों के हज़ारों शहरी लोग।

IFFCO और अमूल ICA ग्लोबल रैंकिंग 2025 में दुनिया की टॉप कोऑपरेटिव में शामिल

भारत के बड़े कोऑपरेटिव संगठन — इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF-अमूल) — को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (ICA) वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में दुनिया की टॉप कोऑपरेटिव में शामिल किया गया है।

यह रैंकिंग कतर के दोहा में हुए ICA CM50 कॉन्फ्रेंस के दौरान अनाउंस की गई, जहाँ IFFCO और अमूल दोनों को प्रति व्यक्ति GDP और ग्लोबल कोऑपरेटिव एक्सीलेंस में उनके शानदार योगदान के लिए पहचाना गया।

IFFCO का योगदान:

IFFCO ने सस्टेनेबल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देकर लाखों भारतीय किसानों को मज़बूत बनाया है। यह ऑर्गनाइज़ेशन मुनाफ़े को कम्युनिटी वेलफेयर, ग्रीन इनिशिएटिव और टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए रीइन्वेस्ट करता रहता है, जिससे यह कोऑपरेटिव सफलता में एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गया है।

अमूल का योगदान:

अमूल ने अपनी "व्हाइट रेवोल्यूशन" विरासत के ज़रिए, भारत के डेयरी सेक्टर को दुनिया के सबसे बड़े कोऑपरेटिव डेयरी नेटवर्क में से एक बना दिया है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सामूहिक मालिकाना हक के सिद्धांतों पर बना, अमूल पूरे भारत में लाखों डेयरी किसानों के लिए सही इनकम और आर्थिक मज़बूती पक्का करता है।

सरकार के विज़न के साथ तालमेल:

यह उपलब्धि भारत सरकार की "सहकार से समृद्धि" (सहयोग के ज़रिए खुशहाली) पहल के साथ तालमेल बिठाती है, जिसका मकसद कोऑपरेटिव सेक्टर को भारत की आर्थिक तरक्की और ग्रामीण मज़बूती के एक अहम पिलर के तौर पर मज़बूत करना है।

और भी ज़रूरी बातें:

- IFFCO हेडक्वार्टर: नई दिल्ली
- अमूल (GCMMF) हेडक्वार्टर: आनंद, गुजरात
- IFFCO की स्थापना: 1967
- अमूल की स्थापना: 1946
- ICA हेडक्वार्टर: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
- IFFCO चेयरमैन: दिलीप संघानी
- अमूल मैनेजिंग डायरेक्टर: जयेन मेहता (2025 तक)

लघु लेख

आईएमएफ का कर्ज़ बढ़ता जा रहा है: अर्जेंटीना, यूक्रेन और मिस्र वैश्विक कर्ज़दारों में सबसे आगे

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) - दुनिया का "अंतिम ऋणदाता" - अब रिकॉर्ड स्तर के बकाया कर्ज़ का सामना कर रहा है क्योंकि कम से कम 86 देशों पर सामूहिक रूप से 162 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज़ है। अर्जेंटीना और यूक्रेन से लेकर मिस्र तक, आर्थिक संकटों, वैश्विक व्यापार व्यवधानों और मुद्रास्फीति के झटकों के बीच, इन देशों ने आईएमएफ सहायता पर तेज़ी से निर्भरता बढ़ाई है।

अक्टूबर 2025 तक के आँकड़े, अस्थिर वैश्विक वित्तीय माहौल में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते दबाव को रेखांकित करते हैं।

आईएमएफ की भूमिका और संरचना

1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित आईएमएफ की स्थापना युद्धोत्तर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और वित्तीय संकटों को रोकने के लिए की गई थी। आज, वाशिंगटन, डीसी में मुख्यालय वाला यह आईएमएफ 191 सदस्य देशों के साथ काम करता है और नीतिगत सलाह, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

इसकी ऋण देने की क्षमता लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर है, जो सदस्य देशों के योगदान ("कोटा") से वित्त पोषित है। प्रत्येक देश के कोटे का आकार उसके वित्तीय योगदान, उधार सीमा और मतदान शक्ति को निर्धारित करता है। धनी देश, जो अक्सर ऋणदाता होते हैं, आईएमएफ ऋणों के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं और बदले में अपने योगदान पर ब्याज अर्जित करते हैं।

2024 में, लगभग 50 ऋणदाता देशों ने आईएमएफ से प्राप्त धन से सामूहिक रूप से 5 अरब डॉलर का ब्याज अर्जित किया।

रिकॉर्ड स्तर पर वैश्विक उधारी

आईएमएफ विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में ऋणों का आकलन करता है - एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति जो पाँच मुद्राओं के समूह से जुड़ी होती है: अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, चीनी रेनमिनबी और जापानी येन। अक्टूबर 2025 के मध्य तक, एक एसडीआर लगभग 1.36 डॉलर के बराबर था।

कुल मिलाकर, आईएमएफ पर 118.9 अरब एसडीआर (लगभग 162 अरब डॉलर) बकाया है। शीर्ष तीन उधारकर्ता - अर्जेंटीना, यूक्रेन और मिस्र - इस कुल राशि का लगभग आधा हिस्सा हैं, जबकि शीर्ष दस देशों का हिस्सा 73% है।

1. अर्जेंटीना: आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार

अर्जेंटीना आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार बना हुआ है, जिस पर 41.8 बिलियन एसडीआर (लगभग 57 बिलियन डॉलर) का कर्ज है - जो अगले सात देशों के कुल कर्ज से भी अधिक है।

दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र का आईएमएफ से ऋण लेने का एक लंबा और परेशानी भरा इतिहास रहा है, और इसमें शामिल होने के बाद से इसे 23 आईएमएफ कार्यक्रम प्राप्त हुए हैं। इसका सबसे हालिया बेलआउट, अप्रैल 2025 में स्वीकृत 20 बिलियन डॉलर का पैकेज, बढ़ती मुद्रास्फीति और गिरते पेसो के बीच आया था।

2018 में, अर्जेंटीना को तत्कालीन राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री के कार्यकाल में इतिहास का सबसे बड़ा आईएमएफ ऋण - 57 बिलियन डॉलर - भी मिला था, जिसका उद्देश्य मुद्रा संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करना था।

एक नए घटनाक्रम में, अक्टूबर 2025 में ट्रम्प प्रशासन ने 20 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की, जिसमें अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बीच मुद्रा विनिमय भी शामिल है, जिसका उद्देश्य मध्यावधि चुनावों से पहले अर्जेंटीना के डॉलर भंडार को मजबूत करना है।

2. यूक्रेन: युद्ध और आर्थिक पतन के कारण उधारी बढ़ रही है

यूक्रेन, IMF का दूसरा सबसे बड़ा उधारकर्ता है, जिस पर 10.4 बिलियन SDR (लगभग 14 बिलियन डॉलर) बकाया है। 2022 में रूस के आक्रमण के बाद, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, और 2025 की शुरुआत तक कुल ऋण दोगुना से भी ज़्यादा बढ़कर 152 बिलियन डॉलर हो गया। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए, IMF ने मार्च 2023 में 15.5 बिलियन डॉलर की चार-वर्षीय विस्तारित निधि सुविधा (EFF) को

मंज़ूरी दी - जो सहयोगियों के साथ समन्वित 115 बिलियन डॉलर के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहायता पैकेज का एक हिस्सा है। 2025 के अंत तक, इस कार्यक्रम के तहत यूक्रेन को 10.6 बिलियन डॉलर वितरित किए जा चुके थे, जिससे भारी रक्षा खर्च के बीच सरकारी संचालन और सामाजिक सेवाओं को बनाए रखने में मदद मिली।

3. मिस्र: मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे से जूझना

आईएमएफ का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार, मिस्र, 6.9 बिलियन एसडीआर (लगभग 9 बिलियन डॉलर) का कर्जदार है। इसका कर्ज बार-बार होने वाले राजकोषीय संकटों, विदेशी मुद्रा की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण है।

आईएमएफ ने पहली बार 2016 में हस्तक्षेप किया था, जब उसने मिस्र के पाउंड को स्थिर करने, सब्सिडी पर अंकुश लगाने और राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 11.9 बिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ये नीतियाँ, व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक होने के बावजूद, उच्च जीवन-यापन लागत के कारण घरेलू असंतोष को भी जन्म दे रही हैं।

मार्च 2025 में, आईएमएफ ने मिस्र के चल रहे 8 बिलियन डॉलर के ईएफएफ की समीक्षा पूरी की और 1.2 बिलियन डॉलर जारी करने को मंजूरी दी। राजकोषीय सुधारों और आईएमएफ समर्थित मौद्रिक नीतियों की बदौलत तब से मुद्रास्फीति लगभग आधी हो गई है।

सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आईएमएफ ऋण: दबाव में छोटी अर्थव्यवस्थाएँ

अर्जेंटीना और यूक्रेन जैसे देशों पर सबसे अधिक ऋण बकाया है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आईएमएफ का ऋण भार एक अलग तस्वीर पेश करता है।

छोटी और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ असमान रूप से ऋणी हैं:

- सूरीनाम: सकल घरेलू उत्पाद का 13%
- मध्य अफ़्रीकी गणराज्य: 9.4%
- अर्जेंटीना: 8.3%
- बारबाडोस: 7.4%
- गाम्बिया: 6.95%

इन देशों के लिए, आईएमएफ द्वारा किए गए पुनर्भुगतान राष्ट्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, जिससे कल्याण, बुनियादी ढाँचे और विकास पर खर्च सीमित हो जाता है।

आईएमएफ ऋणों की दोधारी तलवार

आईएमएफ उन देशों के लिए आवश्यक बना हुआ है जो ऋण-चूक के कगार पर हैं। हालाँकि, इसकी ऋण शर्तें - जिनमें अक्सर मितव्ययिता, सब्सिडी में कटौती और मुद्रा अवमूल्यन शामिल हैं - असमानता को बढ़ा सकती हैं और सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती हैं। आलोचकों का तर्क है कि ऐसी शर्तें, आर्थिक रूप से तर्कसंगत होते हुए भी, अक्सर भ्रष्ट अभिजात वर्ग के बजाय आम नागरिकों को दंडित करती हैं।

फिर भी, आईएमएफ इस बात पर ज़ोर देता है कि राजकोषीय अनुशासन और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं, खासकर ऐसे दौर में जब व्यापार युद्ध, बढ़ती ब्याज दरें और वैश्विक मुद्रास्फीति व्याप्त है।

परिप्रेक्ष्य: बढ़ता ऋण और नाज़ुक सुधार

2025 तक, आईएमएफ का कुल बकाया ऋण चार दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर होगा, जो गहरी वैश्विक आर्थिक नाज़ुकता को दर्शाता है। संरक्षणवादी व्यापार नीतियों और भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण बाज़ारों पर दबाव जारी रहने के कारण, और अधिक देश आपातकालीन सहायता के लिए आईएमएफ की ओर रुख कर सकते हैं।

लेकिन जैसे-जैसे उधार बढ़ता है, निर्भरता भी बढ़ती है - जिससे कई विकासशील देश ऋण, सुधार और नए संकट के चक्र में फँस जाते हैं, जो एक अधिक न्यायसंगत, अधिक टिकाऊ वैश्विक वित्तीय प्रणाली की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

05 NOV

World Tsunami Day

IMPORTANCE

To mark the adoption of the Sendai Framework by UN in 2015 after the Hyogo Framework, which emphasises the reduction of risk a key factor if the world is to achieve substantial reductions in disaster mortality.

MOTTO

To raise tsunami awareness and share innovative approaches to risk reduction.

WHAT IS TSUNAMI?

- The term 'Tsunami' is a Japanese term which means "harbour wave".
- A tsunami is a series of giant waves caused by earthquakes or undersea volcanic eruptions and underwater landslides.

NOTE

World Tsunami Awareness Day was the brain child of Japan. The date for the annual celebration was chosen in honour of the Japanese story of "Inamu-ra-no-hi", meaning the "burning of the rice sheaves".

Inception: 2015 **Edition:** 11th

रक्षा एवं सुरक्षा

दुबई एयरशो में HAL और जर्मन फर्म ने डिफेंस टेक डील की

HAL और जर्मन सेंसर फर्म HENSOLDT ने इंडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर के लिए LiDAR-बेस्ड ऑब्सटेकल अवॉइडेंस सिस्टम (OAS) को को-डेवलप करने के लिए एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया।

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सॉवरेन कैपेबिलिटी

इस डील में HAL को डिजाइन राइट्स, IPR और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ट्रांसफर शामिल है, जिससे सिस्टम का डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन हो सकेगा।

एडवांस्ड हेलीकॉप्टर सेफ्टी

HENSOLDT का SferiSense LiDAR सेंसर और DVE (डिग्रेडेड विज़ुअल एनवायरनमेंट) कंप्यूटर पायलटों को खराब विजिबिलिटी में भी पावर लाइन जैसी रुकावटों का पता लगाने में मदद करेगा, जिससे क्रैश का खतरा कम होगा।

इंडियन फ्लीट में इंटीग्रेशन

यह सिस्टम पहले HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) पर और बाद में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा।

एक्सपोर्ट और लंबे समय का सहयोग

HAL के पास OAS टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने का अधिकार होगा, जिससे भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट क्षमता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ेगी।

LiDAR क्या है?

LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) एक रिमोट-सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो बहुत सटीकता से दूरी मापने के लिए लेज़र बीम का इस्तेमाल करती है।

यह कैसे काम करता है:

LiDAR सेंसर किसी चीज़ या सतह की ओर तेज़ी से लेज़र पल्स भेजते हैं। लाइट को वापस आने में लगने वाला समय मापा जाता है, जिससे दूरी कैलकुलेट करने में मदद मिलती है। लगातार स्कैन करके, LiDAR आस-पास का एक डिटेल्ड 3D मैप बनाता है।

HAL

- इंडस्ट्री: एयरोस्पेस और डिफेंस
- स्थापना: 22 दिसंबर 1940 (हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट) और 1964 (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स)
- फाउंडर: वालचंद हीराचंद
- हेडक्वार्टर: बेंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया
- चेयरमैन और MD: डी.के. सुनील

इंडियन नेवी ने मुंबई में देश का पहला स्वदेशी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर वेसल 'INS माहे' कमीशन किया

इंडियन नेवी ने INS माहे को कमीशन किया

इंडियन नेवी ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में INS माहे को कमीशन किया है, जो माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट का पहला वेसल है।

स्वदेशी शिपबिल्डिंग माइलस्टोन

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, INS माहे आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की बढ़ती शिपबिल्डिंग ताकत को दिखाता है। 80% से ज़्यादा स्वदेशी कंटेंट के साथ, यह वॉरशिप डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और सिस्टम इंटीग्रेशन में हुई तरक्की को दिखाता है।

भूमिका और क्षमता

INS माहे को उथले पानी में एंटी-सबमरीन ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह पश्चिमी समुद्र तट पर एक साइलेंट हंटर के रूप में काम करेगा, जिससे भारत की तटीय सुरक्षा और ASW क्षमताएँ बढ़ेंगी।

माहे का अर्थ:

माहे (जिसे माहे भी कहते हैं) मालाबार कोस्ट पर एक छोटा सा तटीय इलाका है, जो पहले एक फ्रेंच बस्ती थी, और अब पुडुचेरी (UT) का हिस्सा है। नेवी अक्सर जहाजों का नाम भारतीय तटीय शहरों या इलाकों के नाम पर रखती है, इसलिए माहे-क्लास जहाजों का नाम इसी जगह के नाम पर रखा गया है।

भारत ने नेवल माइन वॉरफेयर के लिए नेक्स्ट-जेन ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल बनाए

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRdo) ने मैन-पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (MP-AUVs) को सफलतापूर्वक डेवलप किया है, जिन्हें माइन काउंटरमेजर (MCM) मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि पानी के अंदर की माइन का पता लगाया जा सके और उन्हें बेअसर किया जा सके। इस एडवांस्ड सिस्टम को नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL), विशाखापत्तनम ने डेवलप किया है, जिसमें रियल-टाइम सर्विलांस के लिए साइड-स्कैन सोनार और अंडरवाटर कैमरे जैसे पेलोड हैं। डीप-लर्निंग-बेस्ड टारगेट रिकग्निशन और अंडरवाटर अकूस्टिक कम्युनिकेशन से लैस, ये कॉम्पैक्ट AUVs नेवी के लिए ऑपरेशनल रिस्क को कम करेंगे और अंडरवाटर मिशन के दौरान माइन का तेज़ और ज़्यादा सटीक पता लगाना पक्का करेंगे। इस्तेमाल की गई खास टेक्नोलॉजी:

- रियल-टाइम माइन डिटेक्शन के लिए साइड स्कैन सोनार और अंडरवाटर कैमरे
- ऑटोमैटिक माइन क्लासिफिकेशन के लिए डीप लर्निंग-बेस्ड AI एल्गोरिदम
- कोऑर्डिनेटेड मल्टी-AUV ऑपरेशन के लिए अंडरवाटर अकूस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम

MP-AUV के फायदे

- पोर्टेबल → मैन-पोर्टेबल और लाइटवेट
- फास्ट डिप्लॉयमेंट → रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी
- नेवी डाइवर्स और माइनस्वीपर्स के लिए कम रिस्क
- नेटवर्क-इनेबल्ड ऑपरेशन (मल्टीपल AUV कोलेबोरेशन)
- कम मिशन टाइम और लॉजिस्टिक एफर्ट

स्टेटस

NSTL हार्बर पर सफल फील्ड ट्रायल किए गए
कई इंडियन इंडस्ट्रीज़ शामिल → प्रोडक्शन जल्द शुरू होगा

भारतीय नौसेना 80% स्वदेशी सर्वेक्षण पोत 'इक्षक' को नौसेना में शामिल करेगी

भारतीय नौसेना 6 नवंबर 2025 को कोच्चि नौसेना अड्डे पर सर्वेक्षण पोत एसवीएल इक्षक को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल करेगी, जो समुद्री आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों में एक बड़ा कदम होगा। सर्वेक्षण पोत (बड़े) वर्ग में तीसरा यह पोत, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है।

उन्नत जल सर्वेक्षण भूमिका

इक्षक को बंदरगाहों, बंदरगाहों, नौवहन चैनलों और भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के गहरे पानी और तटीय जल सर्वेक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मल्टी-बीम इको साउंडर, ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (एयूवी), रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (आरओवी), और सर्वे मोटर बोट (एसएमबी) से लैस, इस पोत में एक हेलीकॉप्टर डेक भी है - जो इसकी परिचालन बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाता है।

सामरिक एवं आत्मनिर्भरता का महत्व

उच्च क्षमता वाले सर्वेक्षण पोत का स्वदेशी निर्माण करके, भारतीय नौसेना रक्षा निर्माण में "आत्मनिर्भर भारत" के एजेंडे को मज़बूत कर रही है। इक्क्षक, दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र जागरूकता, सुरक्षित नौवहन और समुद्री संचालन के लिए बेड़े की तैयारी को बढ़ाता है।

प्रतियोगी परीक्षा के मुख्य बिंदु

- नाम: एसवीएल इक्क्षक - संस्कृत में "मार्गदर्शक"
- वर्ग: सर्वेक्षण पोत (बड़ा) - श्रृंखला का तीसरा पोत
- निर्माता: जीआरएसई (कोलकाता)
- स्वदेशी सामग्री: 80% से अधिक
- कमीशनिंग तिथि और स्थान: 6 नवंबर 2025, नौसेना बेस कोच्चि
- प्राथमिक भूमिका: बंदरगाहों, तटीय और गहरे पानी का जल सर्वेक्षण
- मुख्य उपकरण: मल्टी-बीम इको साउंडर, एयूवी, आरओवी, एसएमबी, हेलीकॉप्टर डेक
- रणनीतिक महत्व: समुद्री आत्मनिर्भरता, सुरक्षित नौवहन, उन्नत निगरानी

रूस ने पोसाइडन ड्रोन ले जाने में सक्षम नई परमाणु पनडुब्बी 'खाबरोवस्क' का प्रक्षेपण किया

रूस ने सेवेरोडविंस्क स्थित सेवमाश शिपयार्ड में अपनी नवीनतम परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी "खाबरोवस्क" का प्रक्षेपण किया है, जो उसके रणनीतिक नौसैनिक बेड़े में एक बड़ा योगदान है। यह पनडुब्बी पोसाइडन परमाणु ऊर्जा चालित अंडरवाटर ड्रोन, जिसे "प्रलयकारी हथियार" भी कहा जाता है, को ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो अंतरमहाद्वीपीय दूरी और विनाशकारी शक्ति में सक्षम है। खाबरोवस्क-श्रेणी की पनडुब्बी (जिसे प्रोजेक्ट 09851 के नाम से भी जाना जाता है) बेलगोरोड-श्रेणी के बाद विकासाधीन परमाणु पनडुब्बियों की दूसरी पीढ़ी है और यह रूस के पोसाइडन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका अनावरण राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में किया था।

पोसाइडन परमाणु ड्रोन के बारे में

- पोसाइडन एक मानवरहित पानी के नीचे का वाहन (UUV) है जो एक लघु परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित होता है।
- यह 1,000 मीटर की गहराई पर 10,000 किलोमीटर से अधिक की स्वायत्त यात्रा कर सकता है, जिससे इसका पता लगाना या अवरोधन करना लगभग असंभव है।
- यह ड्रोन कई मेगाटन का परमाणु हथियार ले जा सकता है, जो विशाल सुनामी उत्पन्न करने और तटीय शहरों को तबाह करने में सक्षम है।
- यह रूस के "रणनीतिक निवारक त्रय" का हिस्सा है, जिसमें भूमि-आधारित ICBM, वायु-प्रक्षेपित हथियार और समुद्र-आधारित प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

सेवमाश शिपयार्ड रूस का एकमात्र शिपयार्ड है जो परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करता है; यह आर्कान्जेस्क ओब्लास्ट के सेवेरोडविंस्क में स्थित है। रूसी नौसेना दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। रूस का सामरिक पनडुब्बी बेड़ा मुख्य रूप से उसके उत्तरी और प्रशांत बेड़े के अंतर्गत संचालित होता है। बेलगोरोड (K-329) पोसाइडन ड्रोन ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई पहली पनडुब्बी थी (2022 में कमीशन की गई)। भारत वर्तमान में अरिहंत श्रेणी के एसएसबीएन कार्यक्रम के तहत अपनी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी, आईएनएस अरिहंत का संचालन करता है। आईएनएस अरिहंत भारत के परमाणु त्रिकोण का हिस्सा है, जो विश्वसनीय द्वितीय-आक्रमण क्षमता सुनिश्चित करता है।

भारत ने श्रीहरिकोटा से सबसे भारी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) से LVM3-M5 रॉकेट के ज़रिए भारत के सबसे भारी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

यह लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3) की पांचवीं ऑपरेशनल फ़्लाइट है — जिसे GSLV Mk-III के नाम से भी जाना जाता है,

यह भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह मिशन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और स्पेस डिफ़ेंस में भारत की बढ़ती क्षमताओं को फिर से साबित करता है।

CMS-03 सैटेलाइट की खास बातें

- टाइप: मिलिट्री-सिविलियन डुअल-यूज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट
- वज़न: लगभग 4,400 किलोग्राम, जो इसे अब तक लॉन्च किया गया भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाता है।
- ऑर्बिट: जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट (GTO)
- मकसद: पूरे भारत और आस-पास के समुद्री इलाकों में सुरक्षित, मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सर्विस देना।

एप्लीकेशन:

- स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कम्युनिकेशन को मज़बूत करना।
- डिफ़ेंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए सुरक्षित डेटा, वॉइस और वीडियो लिंक को इनेबल करना।
- डिजिटल कनेक्टिविटी, टेलीमेडिसिन और टेली-एजुकेशन को सपोर्ट करना।
- सरकारी ऑपरेशन के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाना।

LVM3 लॉन्च व्हीकल के बारे में

- फुल फॉर्म: लॉन्च व्हीकल मार्क-3
- इसे GSLV Mk-III (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) के नाम से भी जाना जाता है
- टाइप: थ्री-स्टेज हेवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल
- पहला स्टेज: सॉलिड बूस्टर (S200)
- दूसरा स्टेज: लिक्विड कोर (L110)
- तीसरा स्टेज: क्रायोजेनिक अपर स्टेज (C25)

पेलोड कैपेसिटी:

- लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 8,000 kg तक
- जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में 4,000–4,500 kg तक
- पिछले मिशन: चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, और वनवेब सैटेलाइट मिशन।

ISRO (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन) के बारे में

- स्थापना: 1969
- हेडक्वार्टर: बेंगलुरु, कर्नाटक
- चेयरमैन: डॉ. वी. नारायणन (2025 से)
- पेरेंट डिपार्टमेंट: डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस, भारत सरकार

खास मिशन:

- चंद्रयान-3 (2023): भारत चांद के साउथ पोल के पास लैंड करने वाला पहला देश बना।
- आदित्य-L1 (2023): भारत का पहला सोलर मिशन, जो अभी ऑपरेशनल है।
- गगनयान मिशन (2025–26): भारत का पहला ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन (आने वाला है)।

रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले 'पोसाइडन' अंडरवाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया

रूस ने अपने परमाणु रिएक्टर पर पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाले और परमाणु क्षमता से लैस अंडरवाटर ड्रोन पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस परीक्षण को "बड़ी सफलता" बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा रक्षा प्रणालियाँ पोसाइडन को रोक नहीं पाएँगी।

पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन के बारे में

प्रकार: स्वायत्त, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंडरवाटर ड्रोन (टॉरपीडो श्रेणी)।

क्षमताएँ:

- भारी विनाशकारी शक्ति वाला परमाणु हथियार ले जा सकता है।
- तटीय शहरों और बंदरगाहों को नष्ट करने में सक्षम रेडियोधर्मी सुनामी पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- अभूतपूर्व गहराई और गति पर संचालित होता है, जो अवरोधन क्षमता से परे है।
- सीमा: इसकी सीमा असीमित होने का अनुमान है, क्योंकि यह एक लघु परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित है।
- उद्देश्य: रणनीतिक निवारण - मिसाइल-रोधी प्रणालियों को दरकिनार करने और द्वितीय-आक्रमण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएँ

- परमाणु रिएक्टर: पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टरों से 100 गुना छोटा।
- वारहेड क्षमता: कथित तौर पर रूस के सरमत आईसीबीएम से कहीं ज़्यादा।
- वाहक प्लेटफ़ॉर्म: पोसाइडन को बेलगोरोड पनडुब्बी (प्रोजेक्ट 09852) से तैनात किया गया है, जो दुनिया की सबसे लंबी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है जिसे विशेष रूप से ऐसे ड्रोन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रूस के "नई पीढ़ी" के परमाणु हथियारों में शामिल हैं:

- सरमत आईसीबीएम - कई वारहेड वाली भारी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम)।
- बुरेवेस्टनिक - असीमित दूरी तक मार करने वाली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज़ मिसाइल।
- किंजल - हवा से प्रक्षेपित हाइपरसोनिक मिसाइल।
- अवनगार्ड - परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन।
- पोसीडॉन - परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंडरवाटर ड्रोन (टॉरपीडो)।
- इन प्रणालियों का अनावरण राष्ट्रपति पुतिन ने 2018 में रूस के आधुनिकीकरण अभियान के तहत किया था।

रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 'बुरेवेस्टनिक' क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण किया: पुतिन ने तैनाती योजनाओं की घोषणा की

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 'बुरेवेस्टनिक' क्रूज़ मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की और इसे असीमित रेंज और उन्नत रणनीतिक क्षमता वाला हथियार बताया। यह घोषणा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ एक टेलीविज़न बैठक के दौरान की गई।

मुख्य अंश

- परीक्षणित मिसाइल: बुरेवेस्टनिक (नाटो वर्गीकरण में SSC-X-9 "स्काईफॉल" के रूप में भी जाना जाता है)
- प्रकार: परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज़ मिसाइल
- रेंज: व्यावहारिक रूप से असीमित - 15 घंटे के उड़ान परीक्षण के दौरान 14,000 किमी की दूरी सफलतापूर्वक तय की गई
- उद्देश्य: रूस की लंबी दूरी की परमाणु निवारक क्षमता को मज़बूत करना
- तैनाती: राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सशस्त्र बलों को मिसाइल तैनाती के लिए बुनियादी ढाँचा तैयार करने का निर्देश दिया।

अवसर: यह परीक्षण रूस के रणनीतिक परमाणु अभ्यास और पुतिन के यूक्रेन में सैन्य अभियानों के संयुक्त स्टाफ के दौरे के साथ हुआ।

'बुरेवेस्टनिक' मिसाइल के बारे में

- अर्थ: "बुरेवेस्टनिक" का रूसी में अनुवाद "स्टॉर्म पेट्रेल" होता है।
- तकनीक: प्रणोदन के लिए एक लघु परमाणु रिएक्टर का उपयोग करता है, जिससे इसे लगभग अनंत सीमा और लंबे समय तक हवा में रहने की क्षमता मिलती है।
- उद्देश्य: कम ऊँचाई और अप्रत्याशित प्रक्षेप पथ पर उड़ान भरकर मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- विकास एजेंसी: रूसी रक्षा मंत्रालय और रोसाटॉम (राज्य परमाणु ऊर्जा निगम)।
- पहली घोषणा: 2018 में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा, रूस के रणनीतिक हथियारों की नई पीढ़ी के हिस्से के रूप में।

क्षेत्रीय तनाव के बीच कोलंबिया की पेट्रो ने 17 लड़ाकू विमानों के लिए 4.3 अरब डॉलर का सौदा किया

- प्रमुख हथियार समझौते पर हस्ताक्षर: कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने स्वीडन की साब कंपनी के साथ 17 ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 4.3 अरब डॉलर का अनुबंध किया, जो पहले की रिपोर्टों की पुष्टि करता है।
- एक "निवारक हथियार": पेट्रो ने इस खरीद का बचाव "शांति स्थापित करने के लिए एक निवारक हथियार" के रूप में किया, और कहा कि ये विमान तेजी से अस्थिर होते भू-राजनीतिक माहौल में कोलंबिया के खिलाफ आक्रामकता को हतोत्साहित करने के लिए हैं।
- अमेरिका-कोलंबिया तनाव के बीच समझौता: यह समझौता बोगोटा और वाशिंगटन के बीच उच्च तनाव के समय हुआ है, क्योंकि कोलंबिया ने अमेरिका से हथियारों की खरीद रोक दी है और क्षेत्र में उसकी बढ़ती सैन्य उपस्थिति की आलोचना की है।
- अन्य प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में स्वीडन के ग्रिपेन को चुना गया: कोलंबिया ने अमेरिकी (F-16) और फ्रांसीसी (राफेल) विमान निर्माताओं के प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए स्वीडन निर्मित JAS 39 ग्रिपेन E/F को चुना।
- लैटिन अमेरिका में रणनीतिक बदलाव: यह कदम कोलंबिया द्वारा सैन्य सहायता के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने के प्रयास का संकेत देता है, साथ ही स्वीडन के साथ संबंधों को मज़बूत करने और आधुनिक, कुशल विमानों के साथ राष्ट्रीय रक्षा को मज़बूत करने का भी।

कोलंबिया

- राजधानी: बोगोटा
- मुद्रा: कोलंबियाई पेसो
- राष्ट्रपति: गुस्तावो पेट्रो
- महाद्वीप: दक्षिण अमेरिका

साब एबी

- उद्योग: एयरोस्पेस और रक्षा
- स्थापना: 1937
- मुख्यालय: स्टॉकहोम, स्वीडन
- अध्यक्ष: मार्कस वॉलेनबर्ग
- सीईओ और अध्यक्ष: माइकल जोहानसन

अमेरिका और सऊदी अरब ने असैन्य परमाणु ऊर्जा और अत्याधुनिक अमेरिकी F-35 युद्धक विमानों की बिक्री पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए

असैन्य परमाणु ऊर्जा साझेदारी की घोषणा

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने असैन्य परमाणु ऊर्जा पर एक संयुक्त घोषणापत्र की पुष्टि की। यह समझौता एक दीर्घकालिक, अरबों डॉलर की परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए एक कानूनी ढाँचा स्थापित करता है जो मज़बूत अप्रसार मानकों के अनुरूप है।

प्रमुख रक्षा सौदे को मंज़ूरी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सऊदी अरब के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा बिक्री पैकेज को मंज़ूरी दी। इस पैकेज में भविष्य में उन्नत अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति शामिल है, जिससे सऊदी अरब की सैन्य क्षमताएँ मज़बूत होंगी।

रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना

ये समझौते ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करते हैं।

असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता क्या है?

एक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता एक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता है जो देशों को निम्नलिखित की अनुमति देता है:

1. परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित करना: आपूर्ति करने वाला देश बिजली उत्पादन के लिए तकनीक, रिएक्टर, ईंधन या विशेषज्ञता प्रदान करता है।
2. केवल शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें: ऐसे समझौतों में सख्त अप्रसार शर्तें शामिल होती हैं, जिसका अर्थ है कि प्राप्तकर्ता देश परमाणु हथियार विकसित करने के लिए तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता।
3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता साझा करें: इनमें प्रशिक्षण, सुरक्षा मानक, रिएक्टर डिज़ाइन, अपशिष्ट प्रबंधन और परमाणु विनियमन सहयोग शामिल हैं।
4. दीर्घकालिक औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग को सक्षम बनाएँ: ये समझौते आमतौर पर दशकों तक चलते हैं और इनमें अरबों डॉलर का निवेश शामिल होता है, जिससे ऊर्जा अवसंरचना और औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा मिलता है।
5. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों का पालन करें

सभी गतिविधियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) नियम
- वैश्विक परमाणु सुरक्षा प्रोटोकॉल
- निगरानी और निरीक्षण

साउथ कोरिया-US ने $350 बिलियन के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट MoU पर साइन किए

साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने U.S. के अंदर कई प्रायोरिटी सेक्टर्स में $350 बिलियन के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को मुमकिन बनाने के लिए एक बड़े मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए हैं। यह अनाउंसमेंट साउथ कोरिया के इंडस्ट्री मिनिस्टर किम जंग-क्वान ने की। दोनों देशों का टारगेट जनवरी 2029 तक खास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनल और सिलेक्ट करना है। इन इन्वेस्टमेंट्स के इन पर ज़्यादा फोकस होने की उम्मीद है:

- सेमीकंडक्टर
- इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और बैटरी
- क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन
- एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सिक्योरिटी

स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस

यह एग्रीमेंट इकोनॉमिक रिश्तों को मज़बूत करता है और इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सपोर्ट करता है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चीन पर सप्लाई चेन डिपेंडेंस को कम करने के U.S. के गोल्स के साथ अलाइन है। साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और EV बैटरी में एक मेन ग्लोबल प्लेयर बना हुआ है।

मुख्य तथ्य:

- U.S. में इन्वेस्ट करने वाली साउथ कोरिया की बड़ी कंपनियाँ: सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, SK हाइनिक्स, हुंडई मोटर्स, LG एनर्जी सॉल्यूशन
- U.S. घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए CHIPS & साइंस एक्ट जैसी पहलों के तहत ऐसे इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है।
- साउथ कोरिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है (IMF का अनुमान)।
- दोनों देशों के बीच संबंधों का फ्रेमवर्क: साउथ कोरिया-US अलायंस (1953)
- खास डिफेंस कोऑपरेशन पहल: वाशिंगटन डिक्लेरेशन 2023

MoD ने T-90 टैंकों के लिए INVAR एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए BDL के साथ ₹2,095 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने T-90 मेन बैटल टैंकों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए INVAR एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (ATGMs) की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ ₹2,095 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह एग्रीमेंट 'बाय (इंडियन)' कैटेगरी में आता है, जो स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन और आत्मनिर्भर भारत विजन पर सरकार के फोकस को मजबूत करता है। INVAR एक लेज़र-गाइडेड, सटीक एंटी-टैंक मिसाइल है जिसके हिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और इससे भारत की मैकेनाइज्ड युद्ध क्षमताओं को काफी मज़बूती मिलने की उम्मीद है। यह कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साइन किया गया। इस खरीद का मकसद DPSUs की एक्सपर्टीज़ का फायदा उठाना और कटिंग-एज घरेलू डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है।

INVAR ATGM के बारे में

- INVAR एक लेज़र-गाइडेड एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) है।
- रेंज: लगभग 5 km (वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग)।
- वॉरहेड: टैंडम हाई-एक्सप्लोसिव एंटी-टैंक (HEAT), एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर (ERA) के खिलाफ असरदार।
- लॉन्च किया गया: T-90 टैंक गन बैरल (गन-लॉन्च मिसाइल) से।

T-90 टैंकों के बारे में (भारत में भीष्म)

- भारत T-90S "भीष्म" टैंक चलाता है (रूसी मूल के, कुछ हद तक स्थानीय रूप से बनाए गए)।
- भारतीय सेना की आर्मर्ड कोर का मुख्य आधार।
- भारत अवाडी में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री (HVF) में लाइसेंस के तहत T-90 टैंक बनाता है।

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के बारे में

- स्थापित: 1970
- हेडक्वार्टर: हैदराबाद

- मुख्य प्रोडक्ट: ATGMs (नाग, मिलान, कोंकुर्स), आकाश SAM, एस्ट्रा मिसाइलें। BDL, रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की मुख्य मिसाइल बनाने वाली कंपनियों में से एक है।

भारत-वियतनाम ने आपसी सबमरीन सर्च और रेस्क्यू सपोर्ट पर MoA साइन किया

हनोई में हुई 15वीं भारत-वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी सबमरीन सर्च और रेस्क्यू (SAR) सपोर्ट और कोऑपरेशन पर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MoA) पर साइन किए, जिससे दोनों देशों के बीच नेवल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को मजबूत करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर भी साइन किए गए, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस प्रोडक्शन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस किया गया।

अतिरिक्त प्रमुख तथ्य:

इंडिया-वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (CSP): 2016 में डिफेंस, इकोनॉमिक और कल्चरल रिश्तों को गहरा करने के लिए शुरू की गई। इंडिया की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी": इस पॉलिसी के तहत वियतनाम एक अहम पार्टनर है, जो मज़बूत इंडो-पैसिफिक सहयोग पर ज़ोर देता है।

पिछला डिफेंस सहयोग:

इंडिया वियतनामी सबमरीन के लिए ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स देता रहा है। इंडिया ने डिफेंस खरीद के लिए वियतनाम को $500 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ़ क्रेडिट (LoC) दिया।

सबमरीन SAR सहयोग का महत्व:

इसका मकसद नेवल सेफ्टी, आपसी जवाब देने की क्षमता और समुद्री डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाना है।

स्ट्रेटेजिक महत्व:

साउथ चाइना सी में इंडिया की मौजूदगी को मज़बूत करता है, जहाँ वियतनाम को चीन की विस्तारवादी गतिविधियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

15वीं डायलॉग लोकेशन: हनोई, वियतनाम।

- इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी (2025 तक): राजेश कुमार सिंह। वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर: जनरल फान वान गियांग, जबकि सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होआंग ज़ुआन चिएन डिप्टी मिनिस्टर के तौर पर काम करते हैं।
- भारत का नेवल डॉक्ट्रिन: SAGAR — इस क्षेत्र में सभी के लिए सिक्योरिटी और ग्रोथ — के विज़न के तहत रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन पर ज़ोर देता है।
- पिछला माइलस्टोन: भारत ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए 2023 में वियतनाम को एक इनशोर पेट्रोल वेसल (INS किरपान) सौंपा।

वियतनाम:

- राजधानी: हनोई
- राष्ट्रपति: लुओंग कुओंग
- प्रधानमंत्री: फाम मिन्ह चिन
- करेंसी: वियतनामी डोंग

भारत, इज़राइल ने डिफेंस कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को मज़बूत करने के लिए MoU साइन किया

भारत और इज़राइल ने अपने बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को और बढ़ाने और गहरा करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है। यह MoU तेल अवीव में हुई डिफेंस कोऑपरेशन पर 17वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) मीटिंग के दौरान एक्सचेंज किया गया। मीटिंग की को-चेयर डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह (भारत) और मेजर जनरल आमिर बारम (डायरेक्टर जनरल, इज़राइली मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस) ने की। यह एग्रीमेंट डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तय करता है, जिसमें दोनों देशों के बीच को-डेवलपमेंट, को-प्रोडक्शन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शेयरिंग शामिल है। दोनों देशों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में जॉइंट रिसर्च, काउंटर-टेररिज्म कोऑपरेशन और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर चर्चा की। डिफेंस सेक्रेटरी सिंह ने इज़राइली डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल काट्ज़ से भी मुलाकात की, जहाँ दोनों पक्षों ने टेररिज्म जैसे आम खतरों से निपटने के लिए मज़बूत डिफेंस और सिक्योरिटी संबंधों के महत्व पर ज़ोर दिया। भारत और इज़राइल ने 1990 के दशक से एक मज़बूत डिफेंस पार्टनरशिप शेयर की है, खासकर मिसाइल सिस्टम (बराक-8), ड्रोन, रडार टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में। इज़राइल भारत के टॉप डिफेंस सप्लायर में से एक बना हुआ है।

इज़राइल:

- राजधानी: येरुशलम
- प्रधानमंत्री: बेंजामिन नेतन्याहू

DRDO, फ्रांस के DGA ने डिफेंस चुनौतियों के सॉल्यूशन बनाने के लिए समझौता किया

भारत के DRDO और फ्रांस के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ आर्मामेंट्स (DGA) ने एक टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किए। उद्देश्य: भविष्य की डिफेंस चुनौतियों से निपटने के लिए मिली-जुली एक्सपर्टीज़ और रिसोर्स का फ़ायदा उठाना।

इसके लिए एक फॉर्मल फ्रेमवर्क बनाता है:

- जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम
- ट्रेनिंग प्रोग्राम
- टेस्टिंग और इवैल्यूएशन एक्टिविटी
- जानकारी का लेन-देन

डिफेंस R&D स्किल्स को बढ़ाने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार यह एग्रीमेंट दोनों देशों को इक्विपमेंट, जानकारी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की इजाज़त देता है।

दूसरे एक-दूसरे के लिए फायदेमंद डिफेंस डोमेन

यह पार्टनरशिप भारत-फ्रांस स्ट्रेटेजिक डिफेंस संबंधों को मजबूत करती है। दोनों पक्षों ने भरोसा जताया कि यह सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी में तरक्की को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

US ने भारत को $93 मिलियन के हथियार बेचने की मंज़ूरी दी, क्योंकि डिफेंस रिश्ते मज़बूत हुए

US ने भारत को $93 मिलियन के डिफेंस सौदे को मंज़ूरी दी

U.S. स्टेट डिपार्टमेंट ने लगभग USD 93 मिलियन के एक बड़े हथियार सौदे को मंज़ूरी दी, जिसमें जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रिसिजन आर्टिलरी एम्युनिशन शामिल हैं।

सौदे का ब्रेकडाउन

- 100 FGM-148 जैवलिन मिसाइलें, साथ ही 25 कमांड लॉन्च यूनिट और दूसरे संबंधित सपोर्ट इक्विपमेंट।
- 216 M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी राउंड, साथ ही फायर-कंट्रोल सिस्टम, टेक्निकल डेटा और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट।

रणनीतिक वजह

इस बिक्री का मकसद U.S.-भारत के रणनीतिक रिश्तों को मज़बूत करना और क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है।

भारत की मिलिट्री पर असर

जैवलिन सिस्टम भारत की एंटी-आर्मर युद्ध क्षमताओं को मज़बूत करता है।

एक्सकैलिबर राउंड हाई-एक्यूरेसी, GPS-गाइडेड आर्टिलरी फायर देते हैं, जिससे पहले हमले की सटीकता बेहतर होती है।

कोई स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस नहीं

U.S. अधिकारियों का कहना है कि इस सेल से इलाके में बेसिक मिलिट्री बैलेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा।

मुख्य कॉन्ट्रैक्टर

- RTX कॉर्पोरेशन एक्सकैलिबर शेल सप्लाई करेगा।
- लॉकहीड मार्टिन और RTX का जॉइंट वेंचर जेवलिन मिसाइल देगा।

FGM-148 जेवलिन मिसाइल

- टाइप: एंटी-टैंक मिसाइल, सरफेस-टू-सरफेस मिसाइल, सरफेस-टू-एयर मिसाइल
- ओरिजिन की जगह: यूनाइटेड स्टेट्स
- मैन्युफैक्चरर: रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन

L&T ने इंडियन आर्मी के लिए BvS10 सिंधु गाड़ियां बनाने की डील पक्की की

लार्सन एंड टूब्रो (L&T) और UK की BAE सिस्टम्स ने इंडियन आर्मी के साथ BvS10 सिंधु ऑल-टेरेन आर्मर्ड गाड़ियां सप्लाई करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। L&T हजीरा में अपने आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स में ये गाड़ियां बनाएगी। BAE सिस्टम्स हैग्लंड्स टेक्निकल, डिज़ाइन और इंटीग्रेशन सपोर्ट देगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस और लाइफसाइकल सस्टेनेंस के लिए इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शामिल है।

BvS10 सिंधु के बारे में

BvS10 सिंधु, BAE सिस्टम्स की BvS10 गाड़ी का इंडिया-स्पेसिफिक वेरिएंट है। इसे बहुत मुश्किल हालातों के लिए डिज़ाइन किया गया है: ज़्यादा ऊंचाई, रेगिस्तान, दलदली ज़मीन और पानी और ज़मीन पर चलने वाले इलाके। इसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत इंडियन आर्मी की ज़रूरतों के हिसाब से अपग्रेड शामिल हैं।

इंडियन डिफेंस के लिए अहमियत

यह मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ा कदम है, जिससे घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। बड़े पैमाने पर मुश्किल डिफेंस सिस्टम देने में L&T की भूमिका को मज़बूत करता है। BAE सिस्टम्स के लाइसेंसिंग प्रोग्राम के ज़रिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है।

L&T के हाल के दूसरे डिफेंस ऑर्डर

L&T ने हाल ही में भारत की सेना के लिए एडवांस्ड MALE (मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस) UAV बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है।

L&T

- इंडस्ट्री: ग्रुप
- स्थापना: 7 फरवरी 1946
- हेडक्वार्टर: मुंबई, महाराष्ट्र
- चेयरमैन एमेरिटस: ए. एम. नाइक
- चेयरमैन और MD: एस. एन. सुब्रह्मण्यन

दक्षिण कोरिया और मिस्र शांति प्रयासों और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए

रीजनल और ग्लोबल शांति के लिए कमिटमेंट

साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्युंग ने काहिरा में मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह अल-सिसी से मुलाकात की।

दोनों देश इन जगहों पर "शांति के फ़ैसिलिटेटर" के तौर पर सहयोग करने पर सहमत हुए:

कोरियाई पेनिनसुला

- मिडिल ईस्ट
- बड़े इंटरनेशनल फ़ोरम

ली 26 नवंबर को खत्म होने वाले चार देशों के दौरे पर हैं।

डिफेंस कोऑपरेशन का मज़बूत विस्तार

दोनों पक्ष आपसी फ़ायदे वाले डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने पर सहमत हुए।

K9 हॉवित्ज़र से आगे इन जगहों पर विस्तार:

- FA-50 एयरक्राफ्ट
- चेओनजियोम एयर-लॉन्च्ड एंटी-टैंक मिसाइलें
- ग्राउंड वेपन सिस्टम

मिस्र ने पहले साउथ कोरिया के हनवा डिफेंस के साथ $1.7 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट (Feb 2022) साइन किया था:

- K9 सेल्फ़-प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र
- सपोर्टिंग इक्विपमेंट
- डिलीवरी 2026 में होने की उम्मीद

सिसी ने जॉइंट वेपन प्रोडक्शन में भी दिलचस्पी दिखाई।

CEPA ट्रेड पैक्ट की तरफ़ तरक्की:

- साउथ कोरिया और मिस्र ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन किए।
- ली ने कहा कि CEPA मज़बूत इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशनल बेस होगा।
- सियोल को उम्मीद है कि बातचीत जल्द से जल्द शुरू होगी।

ह्यूमनिटेरियन कोऑपरेशन:

साउथ कोरिया ने गाज़ा रिफ्यूजी ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस से निपटने में मिस्र की मदद करने के लिए कोऑपरेशन का वादा किया।

कल्चरल और एजुकेशनल रिश्ते मज़बूत हुए:

कई MoU पर साइन किए गए:

1. कल्चर
2. एजुकेशन
3. लोगों के बीच लेन-देन

साउथ कोरिया के न्यू मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव का लॉन्च:

प्रेसिडेंट ली ने काहिरा यूनिवर्सिटी में "SHINE" इनिशिएटिव लॉन्च किया।

SHINE का मतलब है:

- स्टेबिलिटी
- हारमनी
- इनोवेशन
- नेटवर्क
- एजुकेशन

मकसद: मिडिल ईस्ट के साथ शांति, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कल्चर और कनेक्टिविटी को मज़बूत करना।

यह इलाका एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है।

पेनिनसुला के लिए कोरिया का विज़न:

ली ने नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच दुश्मनी खत्म करने का अपना वादा दोहराया।

प्लान में शामिल हैं:

- कोरियाई देशों के बीच धीरे-धीरे लेन-देन बढ़ाना
- नॉर्थ कोरिया-US नॉर्मलाइज़ेशन के लिए सपोर्ट
- डीन्यूक्लियराइज़ेशन के लिए एक प्रैक्टिकल, फेज़्ड तरीका

माह के रक्षा/सैन्य अभ्यास

अजेय वॉरियर 2025

इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर का आठवां एडिशन राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया है। यह हर दो साल में होने वाली एक्सरसाइज 30 नवंबर, 2025 तक चलेगी, जिसमें दोनों देशों के कुल 240 सैनिक हिस्सा लेंगे।

हिस्सा लेने वाली यूनिट्स

इंडियन आर्मी की तरफ से, मशहूर सिख रेजिमेंट के सैनिक इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेज़ के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन बनाना है।

ट्रेनिंग फोकस

अजेय वॉरियर 2025 का मेन फोकस शहरी माहौल में काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन्स पर है। यह एक्सरसाइज यूनाइटेड नेशंस मैंडेट के तहत की जा रही है और इसमें मुश्किल, हाई-थ्रेट सिचुएशन्स में मिलकर काम करने की ट्रेनिंग शामिल है।

एक्सरसाइज के मकसद

इस जॉइंट इनिशिएटिव का मकसद इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, बेस्ट मिलिट्री प्रैक्टिसेज़ के एक्सचेंज को आसान बनाना और ऑपरेशनल और टैक्टिकल वॉरफेयर में आपसी कोऑपरेशन को मजबूत करना है। इसका मकसद दोनों सेनाओं को UN पीसकीपिंग मिशन में असरदार तरीके से हिस्सा लेने के लिए तैयार करना भी है।

नोट:

- अजेय वॉरियर भारत और UK में बारी-बारी से होता है; पिछला एडिशन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था।
- भारत और UK दूसरी डिफेंस एक्सरसाइज भी करते हैं जैसे कोंकण (नेवी) और इंद्रधनुष (एयर फोर्स)।
- भारत UN पीसकीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा योगदान देने वालों में से एक है, जिससे यह ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है।

ऑपरेशन अखंड प्रहार

इंडियन आर्मी ने बड़े ट्राई-सर्विसेज़ एक्सरसाइज 'त्रिशूल' के हिस्से के तौर पर डेज़र्ट सेक्टर (जैसलमेर, राजस्थान) में ऑपरेशन 'अखंड प्रहार' किया। कोणार्क कॉर्प्स की ऑपरेशनल तैयारियों का अंदाज़ा लगाने के लिए दक्षिणी कमांड के GOC-in-C लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने ऑपरेशन का रिव्यू किया। इस एक्सरसाइज़ ने कॉर्प्स की पूरी तरह से लड़ने की तैयारी को वैलिडेट किया, जिसमें इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड फोर्सेज़, आर्टिलरी, आर्मी एविएशन, स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशन्स और इंडियन एयर फ़ोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट सपोर्ट की इंटीग्रेटेड तैनाती दिखाई गई। एक खास बात नई बनी इंटीग्रेटेड ऑल-आर्म्स रुद्र ब्रिगेड का ऑपरेशनल वैलिडेट था, जो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एयर डिफेंस आर्टिलरी और अटैक हेलीकॉप्टर सपोर्ट सहित मल्टी-डोमेन वॉरफेयर के लिए तैयार और डिज़ाइन की गई है। स्वदेशी ड्रोन, काउंटर-ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) ग्रिड ने युद्ध के मैदान की ट्रांसपेरेंसी और सटीकता को बढ़ाया, जो आत्मनिर्भरता और मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम के लिए भारत के प्रयास को दिखाता है। इस एक्सरसाइज ने सदर्न कमांड के एक नेटवर्क वाली, फुर्तीली, टेक्नोलॉजी वाली फोर्स में बदलाव को पक्का किया, जो भविष्य के हाई-टेम्पो, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन के लिए तैयार है।

ऑपरेशन अखंड प्रहार के बारे में

- आयोजित किया गया: जैसलमेर, राजस्थान (डेज़र्ट सेक्टर)

- इसका हिस्सा: ट्राई-सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल
- मकसद: कई आर्म्स और सर्विसेज़ से जुड़े इंटीग्रेटेड कॉम्बैट ऑपरेशन को वैलिडेट करना।

गरुड़-2025

इंडियन एयर फोर्स (IAF) की एक टुकड़ी 16-27 नवंबर तक होने वाली बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़-2025 में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के मोंट-डी-मार्सन एयर बेस पहुंच गई है। यह एक्सरसाइज भारत-फ्रांस की लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाती है, जिसमें डिफेंस, सिक्योरिटी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन शामिल हैं।

IAF ने घोषणा की कि Su-30 MKI फाइटर जेट फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट के साथ एक सिम्युलेटेड कॉम्बैट माहौल में ट्रेनिंग लेंगे। इस एक्सरसाइज का मकसद इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना और दोनों एयर फोर्स के बीच बेस्ट प्रैक्टिस के एक्सचेंज को आसान बनाना है।

गरुड़ एक्सरसाइज के बारे में

गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच एक बाइलेटरल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज है।

पहला एडिशन: 2003 (ग्वालियर, भारत)।

भारत और फ्रांस में बारी-बारी से आयोजित किया गया।

मकसद:

- हवाई लड़ाई की टैक्टिक्स को बेहतर बनाना,
- मिली-जुली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना,
- स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिश्तों को मज़बूत करना।

इंडिया-फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप

फ्रांस इंडिया के सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। खास प्रोजेक्ट्स:

- IAF के लिए राफेल फाइटर जेट्स (36 जेट्स डिलीवर किए गए)।
- फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बनी स्कॉर्पीन-क्लास सबमरीन (कलवरी क्लास)।
- स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग।
- फ्रांस इंडो-पैसिफिक और UNSC जैसे ग्लोबल फोरम पर इंडिया के रुख का सपोर्ट करता है।

मालाबार 2025

एक्सरसाइज मालाबार 2025 एक बड़ी मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें क्वाड देश — भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। एक्सरसाइज का 2025 एडिशन ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है और इसका मकसद हिस्सा लेने वाले देशों के बीच नेवल कोऑर्डिनेशन, मैरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। इस ड्रिल में एंटी-सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस और समुद्र में सप्लाई बढ़ाने वाली एक्सरसाइज जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन शामिल हैं, जिन्हें आपसी भरोसा, ऑपरेशनल तैयारी और क्वाड पार्टनर्स की इंडो-पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम चुनौतियों का असरदार तरीके से जवाब देने की क्षमता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एक्सरसाइज मालाबार के बारे में:

- शुरू हुआ: 1992 में भारत और U.S. नेवी के बीच एक बाइलेटरल ड्रिल के तौर पर।
- बढ़ाया गया: जापान (2015) और ऑस्ट्रेलिया (2020) को शामिल करते हुए, यह एक क्वाड-लेवल एक्सरसाइज बन गई।
- नेचर: नॉन-मिलिट्री-अलायंस एक्सरसाइज; जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेविगेशन की आज़ादी पर फोकस करता है।
- पिछली बार होस्ट किया था: ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में।
- 2025 एडिशन: इसका मकसद चारों नेवी के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक भरोसे को बेहतर बनाना है।

स्ट्रेटेजिक महत्व

- क्वाड के फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो-पैसिफिक के विज़न को मज़बूत करता है।
- क्षेत्रीय मैरीटाइम खतरों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ाता है।
- नियम-आधारित व्यवस्था और सामूहिक आपदा-प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ावा देता है।
- फॉर्मल मिलिट्री अलायंस बनाए बिना बढ़ते नेवी सहयोग को दिखाता है।

VINBAX 2025

इंडिया-वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज VINBAX 2025 का 6वां एडिशन हनोई, वियतनाम में शुरू हुआ, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और वियतनाम पीपल्स आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल फुंग सी टैन ने ओपनिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की।

मकसद

एक्सरसाइज VINBAX इंडिया और वियतनाम के बीच एक बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका मकसद है:

- दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना।
- यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग ऑपरेशंस (UNPKO) में बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करना।
- दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और आपसी भरोसे को मजबूत करना।

बैकग्राउंड

- पहली VINBAX एक्सरसाइज 2018 में इंडिया के जबलपुर में हुई थी।
- VINBAX हर साल होती है, जिसमें दोनों देश बारी-बारी से होस्ट करते हैं।
- यह एक्सरसाइज इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन को दिखाती है। इंडियन आर्मी की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं, जबकि

वियतनामी साइड में उसके पीसकीपिंग ट्रेनिंग सेंटर के लोग शामिल हैं।

इंडिया-वियतनाम डिफेंस रिलेशन

- वियतनाम साउथईस्ट एशिया में इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है।
- दोनों देश साउथ चाइना सी में एक मजबूत मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन शेयर करते हैं।
- डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स में ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज और डिफेंस इंडस्ट्री कोलेबोरेशन शामिल हैं।

अतिरिक्त प्रमुख तथ्य:

- इंडिया-वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2016 में शुरू हुई थी।
- VINBAX 2023 एडिशन चंडीगढ़, इंडिया में होस्ट किया गया था।
- वियतनाम इंडिया के इंडो-पैसिफिक आउटरीच का एक अहम पिलर रहा है।
- इंडिया और वियतनाम बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज "सहयोग HOP TAC" और डिप्टी मिनिस्टर लेवल पर डिफेंस डायलॉग भी करते हैं।

MITRA SHAKTI-2025

इंडिया-श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 'MITRA SHAKTI-2025' का 11वां एडिशन 10 नवंबर 2025 को फॉरेन ट्रेनिंग नोड, बेलगावी (कर्नाटक) में शुरू हुआ।

- यह एक्सरसाइज 23 नवंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें UN चार्टर के चैप्टर VII के तहत काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन पर फोकस किया जाएगा, जो पीसकीपिंग और कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन से जुड़ा है।
- इंडियन टुकड़ी (170 लोग) में मुख्य रूप से राजपूत रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं, जबकि श्रीलंकाई टुकड़ी (135 लोग) गजबा रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करती है।
- इसके अलावा, इंडियन एयर फोर्स (IAF) के 20 लोग और श्रीलंकाई एयर फोर्स के 10 लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज में रेड और सर्च मिशन, हेलीबोर्न ऑपरेशन, सर्च-एंड-डिस्ट्रॉय टास्क, कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग, आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन (AMAR), और मेंटल रेजिलिएंस के लिए योग सेशन में जॉइंट ट्रेनिंग शामिल है।
- ड्रोन ऑपरेशन, काउंटर-UAV सिस्टम, हेलीकॉप्टर डिप्लॉयमेंट, हेलीपैड सिक्योरिटी, और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन ड्रिल जैसे मॉडर्न वॉरफेयर एलिमेंट ट्रेनिंग का हिस्सा हैं।
- इस एक्सरसाइज का मकसद सब-कन्वेंशनल वॉरफेयर और UN पीसकीपिंग ऑपरेशन में दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और आपसी समझ को बढ़ाना है, जिससे बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत होगा।

एक्सरसाइज का नाम: मित्र शक्ति — संस्कृत में "दोस्ती की ताकत" :

- शुरू हुआ: 2013 — भारत और श्रीलंका में बारी-बारी से किया गया।
- पिछला एडिशन: मित्र शक्ति-2024 श्रीलंका में हुआ था।

भारत के दूसरे बड़े बाइलेटरल एक्सरसाइज:

- गरुड़ शक्ति – इंडोनेशिया के साथ
- मैत्री – थाईलैंड के साथ
- संप्रीति – बांग्लादेश के साथ
- हैंड-इन-हैंड – चीन के साथ
- युद्ध अभ्यास – US के साथ

त्रिशूल

भारत ने पाकिस्तान के साथ लगी अपनी पश्चिमी सीमा पर एक बड़े पैमाने पर त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसका कोड नाम "अभ्यास त्रिशूल" है। इसका उद्देश्य भारतीय थलसेना, नौसेना और वायु सेना के बीच संयुक्त युद्ध तत्परता और अंतर-संचालन क्षमता का परीक्षण करना है।

उद्देश्य और प्रयोजन

अभ्यास त्रिशूल का प्राथमिक लक्ष्य है:

- थलसेना, नौसेना और वायु सेना के बीच अंतर-सेवा समन्वय को बढ़ाना।
- संयुक्त परिचालन योजना और वास्तविक समय में निर्णय लेना।
- बहु-क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध एकीकृत प्रतिक्रिया क्षमताएँ।
- नेटवर्क-केंद्रित, ड्रोन और सटीक-हमला अभियानों सहित नए युग की युद्ध रणनीतियों का परीक्षण।
- यह भारत की एकीकृत थिएटर कमान संरचनाओं को भी मान्य करेगा, जो राष्ट्रीय रक्षा दक्षता और तालमेल में सुधार के लिए वर्तमान में विकासाधीन एक अवधारणा है।

चरणबद्ध अभ्यास संरचना

चरण I (नौसेना के नेतृत्व में):

भारतीय नौसेना प्रारंभिक चरण का नेतृत्व कर रही है, जिसमें गुजरात के निकट अरब सागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी, तटीय रक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

चरण II (सेना के नेतृत्व में):

भारतीय सेना रेगिस्तानी और अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में टी-90एस भीष्म और अर्जुन एमके-1 टैंकों के साथ-साथ पिनाका और आकाश मिसाइल प्रणालियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत युद्ध और जमीनी युद्धाभ्यास करेगी।

चरण III (वायु सेना के नेतृत्व में):

भारतीय वायु सेना हवाई कवर और हमले के समन्वय के लिए राफेल और सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमानों, हमलावर हेलीकॉप्टरों और हवाई पूर्व चेतावनी प्रणालियों (अवाक्स) का उपयोग करते हुए हवाई प्रभुत्व मिशनों को अंजाम देगी।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारतीय तटरक्षक बल जैसे सहायक बल भी इसमें भाग ले रहे हैं, जिससे एक व्यापक, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा सुनिश्चित होगा।

स्तर और संरचना

- कुल शामिल कर्मी: 20,000 से अधिक सैनिक।
- प्रमुख उपकरण: टी-90एस और अर्जुन टैंक, पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल सिस्टम, राफेल और सुखोई-30एमकेआई जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और नौसेना विध्वंसक।
- परिचालन क्षेत्र: कच्छ (गुजरात) से जैसलमेर (राजस्थान) तक फैला हुआ।
- सामरिक महत्व: वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में एक साथ एकीकृत थल, जल और वायु संचालन करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन।

हाल ही में हुए समान अभ्यास:

- पूर्वी आकाश 2025 - पूर्वी कमान में संयुक्त अभ्यास।
- भारत शक्ति 2024 - राजस्थान में तीनों सेनाओं का प्रदर्शन।
- वायु शक्ति 2024 - पोखरण में भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन।
- प्रमुख रक्षा सिद्धांत: "थियेटरीकरण" - युद्ध के समय तेज़ी से निर्णय लेने के लिए एकीकृत नेतृत्व में सभी सेनाओं की कमानों का एकीकरण।

सागर कवच-2025

इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने 19-20 नवंबर 2025 तक महाराष्ट्र और गोवा कोस्टलाइन पर दो दिन की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच-02/25 की। इस एक्सरसाइज का फोकस एंटी-नेशनल एलिमेंट्स (ANEs) से खतरों के खिलाफ कोस्टल डिफेंस की तैयारियों को टेस्ट करना और ज़रूरी कोस्टल जगहों की सुरक्षा पक्का करना था।

एक्सरसाइज की खास बातें

- इंडियन नेवी, मरीन पुलिस, CISF, कस्टम्स, फिशरीज़ डिपार्टमेंट, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स और पोर्ट अथॉरिटीज़ ने हिस्सा लिया। तैनात किए गए मुख्य एसेट्स:
- इंडियन नेवी और ICG जहाज़
- ICG डोर्नियर एयरक्राफ्ट, चेतक हेलीकॉप्टर, एयर कुशन व्हीकल (ACV)
- मरीन पुलिस बोट, कस्टम बोट, CISF क्राफ्ट
- महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) और गोवा के तटीय संसाधन

कवरेज:

महाराष्ट्र और गोवा में 1 बड़ा पोर्ट और 21 छोटे पोर्ट
ज़िला लेवल की तटीय सुरक्षा अथॉरिटी

सागर कवच-02/25 के मकसद

- समुद्री सुरक्षा की अचानक आने वाली मुश्किलों का सामना करने की क्षमता का पता लगाना।
- समुद्री तट पर ANEs द्वारा घुसपैठ को रोकना।
- 26/11 के बाद के सुधारों के लिए मल्टी-लेयर्ड तटीय सुरक्षा सिस्टम को मज़बूत करना।
- एजेंसी के बीच तालमेल, रिस्पॉन्स टाइम और कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट करना।
- केंद्र, राज्य, इंटेलिजेंस और पोर्ट एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना।

अतिरिक्त:

- ICG हेडक्वार्टर: नई दिल्ली।
- डायरेक्टर जनरल, इंडियन कोस्ट गार्ड (2025): राकेश पाल।
- भारत की कोस्टलाइन: 7,516 km।
- बड़ी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां: ICG, इंडियन नेवी, मरीन पुलिस, DG शिपिंग, CISF, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), कस्टम्स, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स।
- बड़ी तटीय एक्सरसाइज़: सागर कवच, सी विजिल, एक्सरसाइज़ प्रस्थान।

लघु लेख

निवारण से कूटनीति तक: परमाणु परीक्षणों का अतीत, वर्तमान और अनिश्चित भविष्य

परमाणु परीक्षण युग की शुरुआत

परमाणु युग की शुरुआत 16 जुलाई 1945 को हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम, जिसका कोड नाम "ट्रिनिटी" था, विस्फोट किया। तब से लेकर शीत युद्ध की समाप्ति तक, परमाणु परीक्षण प्रमुख शक्तियों के शस्त्रागार का एक अभिन्न अंग बन गया। एक अनुमान के अनुसार, 1945 और 1990 के दशक के मध्य के बीच 2,000 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण किए गए, जिनमें से लगभग 1,000 परीक्षण अमेरिका द्वारा और 715 सोवियत संघ द्वारा किए गए।

परमाणु परीक्षण क्यों बंद हो गए?

जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

समय के साथ, बढ़ते प्रमाणों ने परमाणु परीक्षणों के गंभीर मानवीय और पर्यावरणीय नुकसान को दर्शाया—विशेषकर वायुमंडलीय, पानी के भीतर या अनियंत्रित भूमिगत विस्फोटों के। अमेरिका के नेवादा परीक्षण स्थल, मार्शल द्वीप समूह और कज़ाकिस्तान व आर्कटिक में सोवियत काल के परीक्षण क्षेत्रों जैसे स्थानों में विकिरण संदूषण ने प्रतिबंधों के लिए जन अभियानों को बढ़ावा दिया।

कूटनीति, संधियाँ और स्थगन

इन चिंताओं के जवाब में, परीक्षणों पर लगाम लगाने के प्रयास गंभीरता से शुरू हुए। 1963 की आंशिक (या सीमित) परीक्षण प्रतिबंध संधि ने वायुमंडलीय, अंतरिक्ष और पानी के भीतर विस्फोटों पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में, 1996 में, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर किए गए—यह सभी वातावरणों में सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। हालाँकि CTBT अभी तक लागू नहीं हुआ है (क्योंकि प्रमुख देशों ने इसकी पुष्टि नहीं की है), इसने परीक्षणों के विरुद्ध एक वैश्विक मानदंड बनाने में मदद की।

तकनीकी विकल्प

प्रमुख देशों द्वारा पूर्ण पैमाने पर परीक्षण बंद करने के बाद, उन्होंने उन्नत "भंडार प्रबंधन" कार्यक्रमों—कंप्यूटर सिमुलेशन, उप-महत्वपूर्ण प्रयोग (जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते), और घुसपैठ निगरानी—की ओर रुख किया। इससे उन्हें हथियारों का विस्फोट किए बिना मौजूदा शस्त्रागार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका ने 1992 के बाद से किसी भी उपकरण का विस्फोट नहीं किया है।

क्या परीक्षण फिर से शुरू हो सकते हैं?

रणनीतिक और तकनीकी कारक

कुछ लोगों का तर्क है कि परीक्षणों की वापसी प्रभुत्व का संकेत दे सकती है और सहयोगियों को आश्वस्त कर सकती है। एक परीक्षण यह दर्शाता है कि कोई देश ज़रूरत पड़ने पर "बटन दबाने" को तैयार है—एक शक्तिशाली निवारक संदेश। तकनीकी रूप से, परीक्षण नए हथियार डिज़ाइनों या बड़े संशोधनों को मान्य करने का सबसे सीधा तरीका बना हुआ है।

हाल के संकेत

2025 में, अमेरिकी मीडिया ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेंटागन को परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का निर्देश दिया, जिससे 33 साल का स्वैच्छिक स्थगन समाप्त हो गया। इसका कारण बताया गया: बढ़ती चीनी और रूसी परमाणु क्षमताएँ और यह भावना कि अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहिए। हालाँकि, अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने बाद में स्पष्ट किया: नियोजित परीक्षण पूर्ण-विस्फोट नहीं होंगे, बल्कि "गैर-महत्वपूर्ण" घटक परीक्षण होंगे—कोई परमाणु क्षमता नहीं।

पुनः आरंभ के जोखिम

भूमिगत या ज़मीन के ऊपर विस्फोटों की ओर रुख मोड़ना दशकों से चले आ रहे हथियार-नियंत्रण मानदंडों को कमजोर करता है। इससे परमाणु परीक्षणों में वैश्विक स्तर पर फिर से दौड़ शुरू होने का खतरा है। यदि एक प्रमुख शक्ति परीक्षण करती है, तो अन्य शक्तियाँ भी उसका अनुसरण कर सकती हैं। परमाणु विस्फोट = युद्धक्षेत्र में वृद्धि का अंतर्राष्ट्रीय मानदंड ध्वस्त हो सकता है।

विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि नए परीक्षणों से सीमित वृद्धिशील लाभ होने के बावजूद (क्योंकि अधिकांश मॉडलिंग परिपक्व हो चुकी है), व्यापक लागत—सत्यापन व्यवस्थाओं, अप्रसार प्रयासों और भू-राजनीतिक स्थिरता पर—अनुपातहीन है।

किसके पास हथियार हैं—और कौन परीक्षण करता है?

वैश्विक शस्त्रागार

अमेरिका और रूस दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियाँ बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 5,000 से अधिक आयुध हैं। अन्य देश: स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार, चीन (~600), फ्रांस (~290), ब्रिटेन (~225), भारत (~180), पाकिस्तान (~170), इज़राइल (~90) और उत्तर कोरिया (~50)।

सीटीबीटी के बाद से परीक्षण

1990 के दशक के मध्य से, केवल कुछ ही देशों ने परीक्षण किए हैं: भारत और पाकिस्तान ने 1998 में; उत्तर कोरिया ने 2006-2017 के बीच। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे प्रमुख देशों ने 1996 तक पूर्ण-विस्फोट परीक्षण बंद कर दिए थे।

छिपे हुए परीक्षण?

रोक के बावजूद, गुप्त परीक्षणों या उन्नत वितरण प्रणालियों - हाइपरसोनिक मिसाइलों, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले टॉरपीडो आदि - को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं, जो बिना किसी बड़े विस्फोट के भी प्रतिरोध को अस्थिर कर सकती हैं।

वैश्विक हथियारों की होड़ पर प्रभाव

क्या परीक्षण फिर से तनाव बढ़ाएंगे?

यदि परीक्षण फिर से शुरू होते हैं, तो यह एक क्रम को जन्म दे सकता है: एक परीक्षण → अन्य परीक्षण → हथियार नवाचार में तेजी → हथियारों की होड़ फिर से शुरू। वैश्विक समुदाय को डर है कि परीक्षण फिर से शुरू होने से हथियार नियंत्रण में विश्वास कम हो जाएगा, पुरानी संधियाँ समाप्त हो जाएँगी और हथियारों के प्रसार में तेज़ी आएगी।

रणनीतिक स्थिरता जोखिम में

परीक्षणों की वापसी से पता चलता है कि "परमाणु उपयोग" फिर से चर्चा में है - न कि केवल निवारण। "युद्ध के लिए हथियार" और "दिखावे के लिए हथियार" के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। इससे संकटों में गलत अनुमान लगाने का जोखिम बढ़ जाता है।

सत्यापन और मानदंड कमज़ोर

सीटीबीटी और संबंधित निगरानी तंत्र आंशिक रूप से इसलिए कमज़ोर बने हुए हैं क्योंकि शक्तिशाली देशों ने उनका अनुसमर्थन नहीं किया है। परीक्षण फिर से शुरू होने से इन संधियों का नैतिक बल कमज़ोर होगा और भविष्य की संधि वार्ताएँ जटिल हो जाएँगी।

निष्कर्ष: एक अनिश्चित क्षण

परमाणु हथियारों का परीक्षण तकनीक, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के चौराहे पर खड़ा है। जब प्रमुख शक्तियों ने विस्फोट करना बंद कर दिया और इसके बजाय सिमुलेशन और घोषणाओं पर निर्भर हो गईं, तो दुनिया एक कठिन स्थिरता पर पहुँच गई। लेकिन 2025 में अमेरिका से नए संकेत मिल रहे हैं कि परीक्षण पर एक बार स्वीकृत प्रतिबंध कमज़ोर पड़ सकता है। यदि कोई देश परीक्षण के क्षेत्र में फिर से प्रवेश करता है, तो एक नई वैश्विक हथियारों की दौड़ का जोखिम—जो कम पूर्वानुमानित, अधिक अस्थिर करने वाला होगा—तेजी से बढ़ जाता है।

आने वाले वर्षों में, मुख्य प्रश्न ये होंगे: क्या विस्फोट फिर से शुरू होंगे, या घटक- और प्रणाली-परीक्षण संयम की सीमा के भीतर रहेंगे? क्या हथियार-नियंत्रण ढाँचे पुनर्जीवित होंगे, या वे सत्ता की राजनीति और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के तहत ढह जाएँगे? इस कहानी का अगला मोड़ यह तय कर सकता है कि हम परमाणु वृद्धि के एक नए युग में प्रवेश करेंगे—या दशकों से बनी नाज़ुक शांति को बनाए रखने में कामयाब होंगे।

सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ

TN भारत की पहली 'विमेंस वेलनेस ऑन व्हील्स' गाड़ियां लॉन्च करेगा

तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बनने वाला है जो 'विमेंस वेलनेस ऑन व्हील्स' लॉन्च करेगा — यह महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग और वेलनेस सर्विसेज़ के लिए एक मोबाइल हेल्थकेयर पहल है। यह घोषणा तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने की, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन अगले 10 दिनों में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे।

इस पहल के बारे में

'विमेंस वेलनेस ऑन व्हील्स' प्रोग्राम में 38 मोबाइल मेडिकल गाड़ियां शुरू की जाएंगी, तमिलनाडु के हर जिले के लिए एक। ये गाड़ियां महिलाओं की ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी, जो भारतीय महिलाओं में मौत के दो बड़े कारण हैं। इस पहल का मकसद ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं के लिए प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को आसान बनाना है।

सामाजिक कल्याण के उपायों की घोषणा

उसी इवेंट में, मंत्री ने मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजना के तहत 118 लड़कियों को सेविंग सर्टिफिकेट और मैच्योरिटी फंड बांटे। यह स्कीम 18 साल की उम्र होने पर लड़की के फ़ायदे के लिए ₹50,000 देती है। इसका मकसद लड़कियों की भ्रूण हत्या और बाल विवाह को रोकना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। कवरेज बढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी के लिए सालाना इनकम लिमिट ₹72,000 से बढ़ाकर ₹1,20,000 कर दी गई है।

फ्री HPV वैक्सीनेशन इनिशिएटिव

तमिलनाडु सरकार 14 साल और उससे कम उम्र की लड़कियों के लिए फ्री HPV (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) वैक्सीनेशन भी शुरू करेगी, जिसका मकसद सर्वाइकल कैंसर को रोकना है। ₹36 करोड़ का यह प्रोजेक्ट पूरे राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में लागू किया जाएगा।

खास बातें:

- सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के इंफ़ेक्शन से होता है।वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) ने साल 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर खत्म करने का लक्ष्य रखा है।
- तमिलनाडु, मक्कलाई थेडी मारुथुवम (घर के दरवाज़े पर हेल्थकेयर) जैसी पब्लिक हेल्थ स्कीम को लागू करने में भारत के टॉप परफॉर्मिंग राज्यों में से एक रहा है।
- दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों में से लगभग एक-चौथाई भारत में होती हैं, जो ऐसी पहलों की अहमियत को दिखाता है।
- यह स्कीम हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक की रोकथाम और कंट्रोल के लिए नेशनल प्रोग्राम (NPCDCS) के साथ जुड़ी हुई है।

तेलंगाना सरकार ने लोगों को सरकार से नागरिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप पर मीसेवा शुरू की

तेलंगाना सरकार ने व्हाट्सएप पर मीसेवा शुरू की है, जो एक एआई-संचालित संवादात्मक प्लेटफ़ॉर्म है जो नागरिकों को एक सरल चैट इंटरफ़ेस के माध्यम से लगभग 40 विभागों में 580 से अधिक सरकार-से-नागरिक (G2C) सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।

उद्देश्य: बेहतर पहुँच और सुविधा

इस पहल का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को लोगों के और करीब लाना है। व्हाट्सएप प्रणाली राज्य भर में मौजूदा 5,000 मीसेवा केंद्रों का पूरक होगी, जो एक एकीकृत और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल विकल्प प्रदान करेगी।

सेवा का उपयोग कैसे करें

नागरिक व्हाट्सएप नंबर 80969 58096 पर "Hi" भेजकर इस सेवा का उपयोग शुरू कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद, उपयोगकर्ताओं को एआई-सक्षम चैट इंटरफ़ेस के माध्यम से निर्देशित विकल्प प्राप्त होंगे।

व्हाट्सएप पर उपलब्ध सेवाएँ

इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, उपयोगकर्ता ये कर सकते हैं:

- जन्म, मृत्यु, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
- बिजली, पानी और संपत्ति कर का भुगतान करें
- पुलिस चालान का भुगतान करें
- आवेदन की स्थिति देखें
- अपडेट प्राप्त करें और जारी किए गए दस्तावेज़ डाउनलोड करें

डिजिटल शासन में एक बड़ा कदम

व्हाट्सएप-सक्षम मीसेवा सेवा, डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जो पहुँच में सुधार, प्रयास को कम करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक-सरकार संपर्क को मजबूत करती है।

तेलंगाना

- राजधानी: हैदराबाद
- राज्यपाल: जिष्णु देव वर्मा
- मुख्यमंत्री: रेवंत रेड्डी
- उपमुख्यमंत्री: मल्लू भट्टी विक्रमार्क

पंजाब पूरे राज्य में बदली हुई भारत नेट स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया

पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी ज़िलों में बदली हुई भारत नेट स्कीम को पूरी तरह से लागू किया है, जिससे पहले से पहचाने गए 43 "शैडो एरिया" सहित आसान ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकेगी। सिर्फ़ एक गाँव बचा है, जिसके नवंबर के आखिर तक कवर होने की उम्मीद है। इस कामयाबी के लिए पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा को अजय कुमार करारा, CGM, BSNL पंजाब सर्कल से अवॉर्ड मिला। भारत नेट स्कीम—भारत के सबसे बड़े रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट्स में से एक—का मकसद सभी ग्राम पंचायतों, घरों और इंस्टीट्यूशन्स को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है, जिससे ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन और ई-कॉमर्स सर्विसेज़ मिल सकेंगी। पूरी तरह से लागू होने के साथ, पंजाब के पास अब एक ऐसा सिस्टम है जो देश में कहीं से भी पूरे बॉर्डर वाले राज्य की लाइव मॉनिटरिंग कर सकता है, जिससे गवर्नेंस और सिक्योरिटी ओवरसाइट मज़बूत होगी।

भारत नेट स्कीम के बारे में

- लॉन्च: 2011 (ओरिजनली नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क – NOFN के नाम से)। नोडल मिनिस्ट्री: मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिकेशंस (डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस)।
- इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी: भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL), जो अब BSNL (2022) में मर्ज हो गया है।
- दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम।
- इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी: ग्राम पंचायत लेवल तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC)।

प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना भारत को आठ चीते सौंपेगा

बोत्सवाना रिपब्लिक, देश में चीतों की आबादी को फिर से बढ़ाने के मकसद से प्रोजेक्ट चीता को मज़बूत करने की कोशिशों के तहत भारत को आठ चीते सौंपेगा। यह घोषणा गैबोरोन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के बीच दो-तरफ़ा बातचीत के दौरान की गई। इस खास मौके के तौर पर, दोनों राष्ट्रपति गैबोरोन के पास एक क्वारंटाइन सेंटर में चीतों को छोड़ते हुए देखेंगे, जो वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन में एक बड़ा कदम होगा और पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी से जुड़ी कोशिशों में भारत-बोत्सवाना के बीच सहयोग को और मज़बूत करेगा।

प्रोजेक्ट के बारे में

- प्रोजेक्ट का नाम: प्रोजेक्ट चीता
- लॉन्च: 2022
- मकसद: 1952 में खत्म हुए चीतों को भारत में फिर से लाना
- पहला ट्रांसलोकेशन: नामीबिया से 8 चीते (सितंबर 2022)
- दूसरा ट्रांसलोकेशन: साउथ अफ्रीका से 12 चीते (2023)
- फिर से लाने की जगह: कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश
- इसे लागू किया: नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर

दूसरे दोतरफ़ा डेवलपमेंट

- भारत और बोत्सवाना के बीच हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स पर MoU साइन हुआ।
- भारत ने बोत्सवाना के HIV इलाज की कोशिशों में मदद के लिए एंटी-रेट्रोवायरल (ARV) दवाओं की सप्लाई की घोषणा की।

बोत्सवाना की राजधानी: गैबोरोन

- बोत्सवाना की करेंसी: पुला
- बोत्सवाना के प्रेसिडेंट: डूमा बोको

लघु लेख

भारत में ज़हरीली कफ सिरप त्रासदी: एक सतत दवा-सुरक्षा संकट

घातक प्रकोप

अक्टूबर 2025 में, मध्य प्रदेश में एक दुखद घटना हुई जिसमें कोल्ड्रिफ नामक एक दूषित कफ सिरप पीने से कम से कम 22 बच्चों की जान चली गई। जाँच से पता चला कि सिरप में लगभग 45% डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) था - एक ज़हरीला औद्योगिक रसायन - जो स्वीकार्य सुरक्षा सीमा से कहीं अधिक था। यह सिरप तमिलनाडु स्थित कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित किया गया था और राज्य के कई हिस्सों में वितरित किया जाता था। इस त्रासदी के बाद, अधिकारियों ने कंपनी की निर्माण इकाई को सील कर दिया, उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया और देश भर से उत्पाद को वापस मंगाने का आदेश दिया।

डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) क्या है?

DEG एक ज़हरीला कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर एंटीफ्रीज़, ब्रेक फ्लुइड और औद्योगिक सॉल्वेंट्स जैसे औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन और मीठा स्वाद वाला होता है, जिससे गलती से सेवन करने पर यह विशेष रूप से खतरनाक हो जाता है। दवा निर्माण में, डीईजी को कभी-कभी ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के स्थान पर अवैध रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है, जो सुरक्षित लेकिन अधिक महंगे तत्व हैं जिनका उपयोग सिरप में विलायक के रूप में किया जाता है। डीईजी की थोड़ी सी मात्रा भी तीव्र गुर्दे की विफलता, तंत्रिका तंत्र को नुकसान और मृत्यु का कारण बन सकती है, खासकर बच्चों में।

बार-बार होने वाली आपदाओं का एक पैटर्न

2025 का मामला इसी तरह की त्रासदियों की श्रृंखला में नवीनतम है। 2022 में, गाम्बिया में एक भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप पीने से 70 से अधिक बच्चों की मौत हो गई, और कुछ महीने बाद उज़्बेकिस्तान में 18 और मौतें हुईं। ये बार-बार होने वाली घटनाएँ भारत की दवा निर्माण और नियामक प्रणालियों में गहरी खामियों को उजागर करती हैं।

प्रत्येक मामले में जाँच से खराब गुणवत्ता नियंत्रण, कच्चे माल की आपूर्ति में लापरवाही और उत्पादों के बाजार में पहुँचने से पहले पर्याप्त परीक्षण का अभाव सामने आया। वैश्विक चिंता के बावजूद,

कई लघु-स्तरीय दवा इकाइयाँ न्यूनतम निगरानी और पुरानी सुविधाओं के साथ काम करना जारी रखती हैं।

कारखाने के अंदर: उपेक्षा का एक मामला

श्रीसन फार्मास्युटिकल्स संयंत्र का दौरा करने वाली निरीक्षण टीम ने चिंताजनक स्थिति की सूचना दी। संयंत्र में अस्वास्थ्यकर भंडारण क्षेत्र, जंग लगी मशीनें, अवरुद्ध जल निकासी और गुणवत्ता परीक्षण उपकरण गायब थे। 350 से अधिक नियामक उल्लंघनों की पहचान की गई, जिनमें कच्चे माल का परीक्षण न करना और उत्पादन बैचों के दस्तावेज़ीकरण का अभाव शामिल है। ऐसी स्थितियाँ एक बार की गलती के बजाय एक प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा करती हैं - एक ऐसा उद्योग जो सुरक्षा और नैतिकता के बजाय लागत में कटौती और कमज़ोर प्रवर्तन पर चल रहा है।

कमज़ोर निगरानी और खंडित विनियमन

भारत का औषधि विनियमन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और विभिन्न राज्य औषधि नियंत्रण विभागों के बीच विभाजित है। सीडीएससीओ नई दवाओं और निर्यात के लिए अनुमोदन का प्रबंधन करता है, जबकि राज्य नियामक विनिर्माण और खुदरा बिक्री की देखरेख करते हैं। हालाँकि, यह विभाजित संरचना अक्सर भ्रम, ओवरलैप और खामियों का कारण बनती है।

कई राज्य प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी और अपर्याप्त धन है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद परीक्षण में देरी या पूर्ण अनुपस्थिति होती है। छोटी कंपनियाँ अक्सर निरीक्षणों को दरकिनार कर देती हैं या रिकॉर्ड में हेराफेरी करती हैं। 2024 में एक राष्ट्रव्यापी ऑडिट में पाया गया कि निरीक्षण की गई एक तिहाई से अधिक दवा इकाइयां बुनियादी सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रही थीं - यह एक ऐसे देश के लिए एक चौंका देने वाला आंकड़ा है जो मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है।

वैश्विक प्रतिष्ठा खतरे में

भारत लंबे समय से विकासशील देशों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने वाले "वैश्विक दक्षिण की फार्मेसी" के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन बार-बार होने वाले संदूषण घोटाले इस प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कई देश अब वितरण से पहले भारतीय दवा आयातों की स्वतंत्र जाँच पर ज़ोर दे रहे हैं।

घरेलू स्तर पर, ये त्रासदियाँ जनता के विश्वास को कम करती हैं। पीड़ितों के परिवारों को अक्सर बहुत कम या बिल्कुल भी मुआवज़ा नहीं मिलता है, और दवा और नियामक प्रणालियों में जवाबदेही कमज़ोर बनी हुई है। कानूनी कार्रवाई धीमी है, और कई कंपनियाँ थोड़े समय के लिए उत्पादन बंद करने के बाद फिर से उत्पादन शुरू कर देती हैं।

मानवीय लागत

ऐसी घटनाओं के शिकार लगभग हमेशा बच्चे होते हैं - समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग। डीईजी विषाक्तता से उल्टी, पेट दर्द, दौरे और तेज़ी से गुर्दे खराब होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जब तक इसका पता चलता है, तब तक नुकसान आमतौर पर अपरिवर्तनीय हो चुका होता है। इस तरह के विषाक्तता के बार-बार होने से यह उजागर होता है कि कैसे लाभ की भावना अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं पर भारी पड़ती है।

आगे का रास्ता: व्यवस्था को मज़बूत करना

विशेषज्ञ और स्वास्थ्य अधिवक्ता कई ज़रूरी सुधारों पर ज़ोर दे रहे हैं:

एकीकृत औषधि-सुरक्षा प्राधिकरण: बेहतर समन्वय के लिए केंद्र और राज्य की निगरानी को एकीकृत करते हुए एक केंद्रीकृत नियामक निकाय की स्थापना।

कठोर गुणवत्ता नियंत्रण: डीईजी या ईजी संदूषण को रोकने के लिए सभी कच्चे माल, विशेष रूप से ग्लिसरीन जैसे विलायकों का परीक्षण अनिवार्य करें।

आधुनिक परीक्षण अवसंरचना: प्रशिक्षित पेशेवरों और वास्तविक समय डेटा निगरानी के साथ राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन और विस्तार करें।

कठोर दंड: मिलावट या लापरवाही के दोषी पाए जाने वाली कंपनियों के लिए कड़ी आपराधिक कार्रवाई और आजीवन प्रतिबंध लागू करें।

सार्वजनिक पारदर्शिता: लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं और गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएँ जो उपभोक्ताओं और आयातकों के लिए सुलभ हों।

निष्कर्ष

हाल ही में हुई ज़हरीली कफ सिरप त्रासदी एक गंभीर सच्चाई को रेखांकित करती है - वैश्विक दवा क्षेत्र में अपने प्रभुत्व के बावजूद भारत का औषधि सुरक्षा ढांचा खतरनाक रूप से कमज़ोर बना हुआ है। जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही और कठोर गुणवत्ता प्रवर्तन प्रणाली का अभिन्न अंग नहीं बन जाते, तब तक इसी तरह की घटनाएँ निर्दोष लोगों की जान लेती रहेंगी। दुनिया भारत की दवाओं पर निर्भर है - लेकिन अब उस विश्वास को सुरक्षा, अखंडता और सुधार के माध्यम से फिर से स्थापित करना होगा।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

सुनापुर और पुरी के समुद्र तटों को फिर से ब्लू फ्लैग प्रमाणन

पुरी (ओडिशा) स्थित सुनापुर और गोल्डन बीच ने वर्ष 2025-26 के लिए एक बार फिर प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और सुरक्षा के उनके उच्च मानकों को दर्शाता है।

वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया

यह प्रमाणन फाउंडेशन फॉर एनवायर्नमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा प्रदान किया जाता है, जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो समुद्र तटों का मूल्यांकन जल गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा जैसे कड़े मानदंडों के आधार पर करती है।

बार-बार सफलता

सुनापुर: लगातार तीन वर्षों तक ब्लू फ्लैग का दर्जा प्राप्त किया।
पुरी (गोल्डन बीच): लगातार सातवें वर्ष प्रमाणन प्राप्त किया।

सख्त स्थिरता मानदंड

इन समुद्र तटों का मूल्यांकन 33 कठोर मानकों के आधार पर किया गया, जिनमें शामिल हैं:

- जल गुणवत्ता
- अपशिष्ट प्रबंधन
- सुरक्षा सेवाएँ
- पर्यावरण शिक्षा और बुनियादी ढाँचा

पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए आदर्श

ब्लू फ्लैग प्रमाणन इन समुद्र तटों को स्थायी तटीय पर्यटन के लिए आदर्श बनाता है, जो पर्यटकों के अनुकूल सुविधाओं को दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण के साथ जोड़ता है।

सामुदायिक भागीदारी

यह प्रमाणन स्थानीय समुदायों, पर्यावरण प्रबंधकों और स्वच्छता, सुरक्षा और बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने वाली सरकारी समितियों के सक्रिय सहयोग से संभव हुआ है।

ओडिशा

- राजधानी: भुवनेश्वर
- ज़िले: 30 (3 संभाग)
- राज्यपाल: कंभमपति हरि बाबू
- मुख्यमंत्री: मोहन चरण माझी
- उपमुख्यमंत्री: कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN द्वारा "अच्छा" दर्जा दिया गया, सकारात्मक दर्जा प्राप्त एकमात्र भारतीय स्थल

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN द्वारा "अच्छा" दर्जा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अपनी नवीनतम वैश्विक समीक्षा में सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को "अच्छा" दर्जा दिया है। यह यह दर्जा प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय स्थल है, जबकि पश्चिमी घाट और सुंदरबन जैसे अन्य स्थलों को गंभीर चिंताओं के लिए चिह्नित किया गया था।

भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल

2016 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, कंचनजंगा भारत का पहला "मिश्रित" धरोहर स्थल है, जिसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्वों के लिए मान्यता प्राप्त है। 1,784 वर्ग किमी में फैला यह स्थल उपोष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी, कंचनजंगा पर्वत (8,586 मीटर) के बर्फीले शिखर तक फैला हुआ है।

समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र

यह पार्क 280 ग्लेशियरों, 70 से अधिक हिमनद झीलों और विविध प्रजातियों का घर है, जिनमें हिम तेंदुए, लाल पांडा, हिमालयी ताहर और इम्पेयन तीतर तथा सैटायर ट्रैगोपैन जैसी 550 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व

लेप्चा समुदाय के लिए, यह पार्क पवित्र मायेल ल्यांग है, जबकि तिब्बती बौद्ध इसे एक पवित्र घाटी या बेयुल मानते हैं। थोलुंग जैसे प्राचीन मठ आधुनिक संरक्षण प्रथाओं के साथ-साथ इस क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को भी बनाए रखते हैं।

स्थायी सह-अस्तित्व का मॉडल

2018 में विस्तारित कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, मुख्य संरक्षित क्षेत्रों को बफर क्षेत्रों के साथ एकीकृत करता है जहाँ समुदाय स्थायी खेती में संलग्न होते हैं। यह सहभागी दृष्टिकोण पार्क के संरक्षण की सफलता का केंद्र रहा है।

प्रभावी प्रबंधन और वैश्विक सहयोग

पार्क की दूरस्थता, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और नेपाल के कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र के साथ सहयोग ने मानव दबाव को कम किया है और अवैध शिकार पर अंकुश लगाया है। यहाँ तक कि 2024 में हिमनद झील के फटने से आई बाढ़ का भी प्रभावी ख़तरा मानचित्रण के ज़रिए तेज़ी से प्रबंधन किया गया।

संरक्षण का एक मॉडल

कंगचेंदज़ोंगा की सफलता दर्शाती है कि कैसे सांस्कृतिक सम्मान, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक प्रबंधन जैव विविधता को बनाए रख सकते हैं और विरासत की रक्षा कर सकते हैं - जो दुनिया भर के संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है।

आईयूसीएन

- मुख्यालय: ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड
- स्थापना: 5 अक्टूबर 1948, फॉनटेनब्लियू, फ़्रांस
- सीईओ: ब्रूनो ओबेरले
- पूर्व नाम: अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ

प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में भारत के पहले डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नामक इस संग्रहालय का निर्माण 10 एकड़ भूमि पर ₹50 करोड़ की लागत से किया गया है। यह संग्रहालय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी नायकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देता है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को उजागर करता है और आदिवासी विरासत और पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

- प्रयुक्त तकनीक: वीएफएक्स, डिजिटल प्रोजेक्शन, इंटरैक्टिव टच स्क्रीन और क्यूआर कोड-सक्षम कहानी कहने की सुविधा

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह को समर्पित है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसमें प्रमुख आदिवासी विद्रोहों का भी विवरण है, जैसे:

- हल्बा विद्रोह (1774-1779)
- सरगुजा विद्रोह (1820 का दशक)
- परलकोट और भोपालपटनम आंदोलन
- तारापुर, लिंगागिरी, कोइ, मेरिया, मुरिया, रानी चौरी, भूमकाल (1910)
- झंडा और जंगल सत्याग्रह

ये आंदोलन औपनिवेशिक शोषण का विरोध करने और भूमि एवं वनों पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

UIDAI ने बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट को बढ़ावा देने के लिए बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड के साथ MoU साइन किया

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों के बीच मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च कंसल्टेंसी, बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड (BIL) के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। मकसद: 5 से 15 साल के बच्चों के लिए समय पर आधार बायोमेट्रिक अपडेट को बढ़ावा देना, बिहेवियरल, लॉजिस्टिकल और अवेयरनेस से जुड़ी चुनौतियों को दूर करना।

- शामिल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MeitY)
- लागू करना: MBU को बढ़ावा देने के लिए खास बिहेवियरल इंटरवेंशन डिज़ाइन, टेस्ट और लागू किए जाएँगे।
- फायदा: आधार से जुड़ी सरकारी स्कीम और सर्विस तक आसान पहुँच पक्का करता है।

ज़रूरी प्रोविज़न:

5 से 15 साल के बच्चों के लिए MBU चार्ज माफ़ कर दिए गए हैं। यह माफ़ी 1 अक्टूबर 2025 से लागू है और एक साल के लिए वैलिड है।

अतिरिक्त प्रमुख तथ्य:

- UIDAI हेडक्वार्टर: नई दिल्ली
- शुरू हुआ: 28 जनवरी, 2009
- पैरेंट मिनिस्ट्री: मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY)
- अभी के UIDAI CEO: भुवनेश कुमार
- आधार एक्ट लागू हुआ: 2016

MBU का मकसद:

- बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो) को अपडेट करना, क्योंकि उम्र के साथ उनके बायोमेट्रिक्स बदलते हैं।
- बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड (BIL):
- UK की रिसर्च कंसल्टेंसी जो पब्लिक पॉलिसी में बिहेवियरल साइंस को लागू करने में स्पेशलाइज़ करती है।
- भारत का आधार कवरेज: 1.3 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने एनरोल किया है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ID सिस्टम बन गया है।
- आधार का इस्तेमाल: सब्सिडी पाना, डिजिटल KYC, बैंकिंग, स्कूल एडमिशन, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, वगैरह।
- UIDAI का मोटो: "यूनिक आइडेंटिटी के ज़रिए लोगों को मज़बूत बनाना।"

ब्राज़ील में COP30 क्लाइमेट एग्रीमेंट को मंज़ूरी, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में तेज़ी लाने की अपील

ब्राज़ील के बेलेम में हुए यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस (COP30) में, दुनिया के नेताओं ने लंबी बातचीत के बाद एक क्लाइमेट एग्रीमेंट को मंज़ूरी दी। हालाँकि इस डील का मकसद ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को मज़बूत करना है, लेकिन इसमें फॉसिल फ्यूल को धीरे-धीरे खत्म करने का वादा शामिल नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारणों में से एक है।

COP30 एग्रीमेंट के मुख्य नतीजे

- रात भर की बातचीत के बाद एग्रीमेंट को फ़ाइनल किया गया, जिसमें फॉसिल फ्यूल के मुद्दों पर तीखे मतभेद दिखे।
- तेल बनाने वाले देशों के कड़े विरोध के कारण फॉसिल फ्यूल को धीरे-धीरे खत्म करने का कोई ज़िक्र नहीं है।
- डेवलप्ड देशों से अपील की गई कि वे खराब मौसम की घटनाओं का सामना कर रहे डेवलपिंग देशों की मदद के लिए क्लाइमेट फाइनेंस को कम से कम तीन गुना करें।
- एग्रीमेंट में क्लाइमेट से जुड़ी ट्रेड रुकावटों का रिव्यू करने का वादा शामिल है।
- देशों से अपील की गई है कि वे पेरिस एग्रीमेंट के तहत 1.5°C वार्मिंग लिमिट को हासिल करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में तेज़ी लाएँ।

ग्लोबल रिएक्शन

क्लाइमेट कैंपेनर्स ने एग्रीमेंट की आलोचना करते हुए इसे काफ़ी नहीं बताया। दुनिया के नेताओं ने इस डील का स्वागत किया, लेकिन और बड़े कामों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। देशों को बांटने

वाले मुख्य मुद्दों में फॉसिल फ्यूल को धीरे-धीरे खत्म करना, फाइनेंशियल कमिटमेंट और क्लाइमेट की ज़िम्मेदारियों में बराबरी शामिल थी। अमेरिका ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डेलीगेशन नहीं भेजने का फैसला किया था।

COP (कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़) के बारे में

- COP, UNFCCC (यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) की सबसे बड़ी फ़ैसले लेने वाली बॉडी है।
- पहला COP 1995 में बर्लिन में हुआ था।
- COP21 (पेरिस, 2015) का नतीजा पेरिस एग्रीमेंट के तौर पर हुआ, जिसका मकसद ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करना था।

क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े ज़रूरी फैक्ट्स

डेवलप्ड देशों ने 2020 से हर साल USD 100 बिलियन जुटाने का वादा किया था (जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है)।

क्लाइमेट फाइनेंस में इनके लिए फंडिंग शामिल है:

- मिटिगेशन (एमिशन कम करना)
- अडैप्टेशन (क्लाइमेट चेंज के असर से निपटना)
- लॉस एंड डैमेज (क्लाइमेट के ऐसे असर के लिए मुआवजा जिन्हें टाला नहीं जा सकता)

मुख्य ग्लोबल क्लाइमेट मैकेनिज्म

- NDCs (नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन): एमिशन कम करने के लिए देशों के कमिटमेंट।
- ग्लोबल स्टॉकटेक: पेरिस एग्रीमेंट के तहत समय-समय पर रिव्यू; अगला बड़ा रिव्यू चल रहा है।
- लॉस एंड डैमेज फंड: COP27 में कमजोर देशों की मदद के लिए बनाया गया।

क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट

- फॉसिल फ्यूल (कोयला, तेल, गैस) ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस एमिशन में 75% से ज़्यादा का योगदान करते हैं।
- दुनिया अभी लगभग 2.4°C–2.8°C वार्मिंग की ओर बढ़ रही है, जो पेरिस लिमिट से बहुत ज़्यादा है।
- बड़े एमिटर में चीन, USA, EU, भारत और रूस शामिल हैं।

क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पर: क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026

ब्राज़ील के बेलेम में COP30 के दौरान जर्मनवॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026 ने भारत को दुनिया के सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से प्रभावित देशों (1995–2024 के समय) में 9वां स्थान दिया है। रिपोर्ट में तीन दशकों के क्लाइमेट डेटा (1995–2024) का एनालिसिस किया गया है, जिसमें खराब मौसम की घटनाओं के कारण 832,000 मौतें और USD 4.5 ट्रिलियन का ग्लोबल आर्थिक नुकसान दर्ज किया गया है।

क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) के बारे में

- जर्मनवॉच, जो 1991 में जर्मनी में बना एक एनवायरनमेंटल थिंक टैंक है, हर साल इसे पब्लिश करता है।
- यह इंडेक्स छह इंडिकेटर्स के आधार पर लंबे समय तक क्लाइमेट की कमज़ोरी का अंदाज़ा लगाता है, जिनमें शामिल हैं:
- मौतें (पूरी और हर 1 लाख आबादी पर)
- आर्थिक नुकसान (पूरी और GDP के % के तौर पर)
- बहुत ज़्यादा मौसम की घटनाओं से प्रभावित लोगों की संख्या
- डेटा सोर्स: EM-DAT (इंटरनेशनल डिज़ास्टर डेटाबेस), वर्ल्ड बैंक, और IMF.
- पहली बार 2006 में पब्लिश हुआ, यह बताता है कि कौन से देश बहुत ज़्यादा मौसम के असर से सबसे ज़्यादा परेशान हैं।

CRI 2026 के ग्लोबल नतीजे

1995–2024 के बीच 9,700 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मौसम की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं।

टॉप 3 सबसे ज़्यादा प्रभावित देश (लंबे समय तक):

- डोमिनिका
- म्यांमार
- होंडुरास
- 2024 में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश: सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, ग्रेनेडा, और चाड। छोटे आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स (SIDS) ग्लोबल एमिशन में बहुत कम योगदान के बावजूद सबसे ज़्यादा असर डालते हैं।

भारत की रैंकिंग और असर

- लंबे समय की रैंकिंग (1995–2024): 9वीं (पिछले CRI में 8वीं से बेहतर)।
- 2024 के लिए रैंकिंग: सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में 15वीं।
- 2024 में प्रभावित लोग: बांग्लादेश और फिलीपींस के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा।

पिछले 30 सालों में, भारत ने 430+ बहुत खराब मौसम की घटनाओं का सामना किया है, जिससे ये हुआ:

- 80,000 मौतें
- 1.3 बिलियन लोग प्रभावित
- USD 170 बिलियन का आर्थिक नुकसान (≈ ₹14.1 लाख करोड़)
- सालाना औसत नुकसान: USD 5.6 बिलियन (≈ ₹46,000 करोड़)।
- सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर: खेती, घर और गांव की रोज़ी-रोटी।

लघु लेख

भारत-बोत्सवाना सहयोग: प्रोजेक्ट चीता को बढ़ावा

भारत से बोत्सवाना के पहले राष्ट्रपति दौरे के दौरान, भारत के राष्ट्रपति ने आठ चीतों को भारत में ट्रांसलोकेशन करने की घोषणा की, जो प्रोजेक्ट चीता में एक बड़ा कदम है। बोत्सवाना ने आधिकारिक तौर पर ये चीते सौंप दिए, और उनमें से पांच अभी बोत्सवाना के मोकोलोडी नेचर रिज़र्व में क्वारंटाइन में हैं। यह पहल भारत और अफ्रीकी देशों के बीच बढ़ते संरक्षण सहयोग को

दिखाती है और चीतों को उनके पुराने ठिकानों पर वापस लाने की भारत की कोशिशों को मज़बूत करती है।

प्रोजेक्ट चीता

प्रोजेक्ट चीता को 2022 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद 1952 में भारत में खत्म हो चुके चीतों को वापस लाना था। यह दुनिया का पहला एक बड़े जंगली मांसाहारी जानवर का इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत में चीतों की आबादी को फिर से बढ़ाना, खराब हो चुके सवाना घास के मैदानों को फिर से ठीक करना, वाइल्डलाइफ़ पर आधारित इकोटूरिज़्म और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना, और स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाकर इंसान-वाइल्डलाइफ़ टकराव को कम करना है।

इस प्रोजेक्ट को नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी (NTCA) मध्य प्रदेश फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (WII) के साथ मिलकर लागू कर रही है। 2023 में, प्रोग्राम के टेक्निकल और इकोलॉजिकल पहलुओं को गाइड करने के लिए एक खास स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी।

अभी, भारत में 27 चीते हैं, जिनमें 16 बच्चे भारतीय ज़मीन पर पैदा हुए हैं। उनके मौजूदा हैबिटैट में कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी शामिल हैं, जबकि नौरादेही वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी को एक और जगह के तौर पर देखा जा रहा है। 350 से ज़्यादा "चीता मित्र" स्थानीय स्तर पर मिलकर रहने और हैबिटैट को सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं।

बोत्सवाना: मुख्य ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक प्रोफ़ाइल

बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में बसा एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसके बॉर्डर दक्षिण और पूर्व में साउथ अफ्रीका, पश्चिम में नामीबिया और उत्तर-पूर्व में ज़िम्बाब्वे से लगते हैं। देश की एक खास फिजिकल खासियत कालाहारी रेगिस्तान है, जो इसके लगभग 70% एरिया में फैला हुआ है। रेगिस्तान कहे जाने के बावजूद, कालाहारी में ठीक-ठाक पेड़-पौधे और जंगली जानवर हैं, यहाँ सवाना घास के मैदान और पुराने बाओबाब के पेड़ आम तौर पर पाए जाते हैं। यह देश अपनी नेचुरल कंज़र्वेशन साइट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है, खासकर ओकावांगो डेल्टा, जो UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपने अनोखे इनलैंड वॉटर सिस्टम के लिए जाना जाता है, और चोबे नेशनल पार्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी हाथियों की आबादी में से एक है, जिनकी अनुमानित संख्या 50,000 से ज़्यादा है। बोत्सवाना की एनवायरनमेंटल पॉलिसीज़ मज़बूत हैं, इसके लगभग 17% ज़मीनी एरिया को प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क और गेम रिज़र्व के तौर पर बनाया गया है।

इकोनॉमिक तौर पर, बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर में से एक है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन में लगभग 20% का हिस्सा देता है। सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ने देश के विकास और स्थिरता में अहम भूमिका निभाई है।

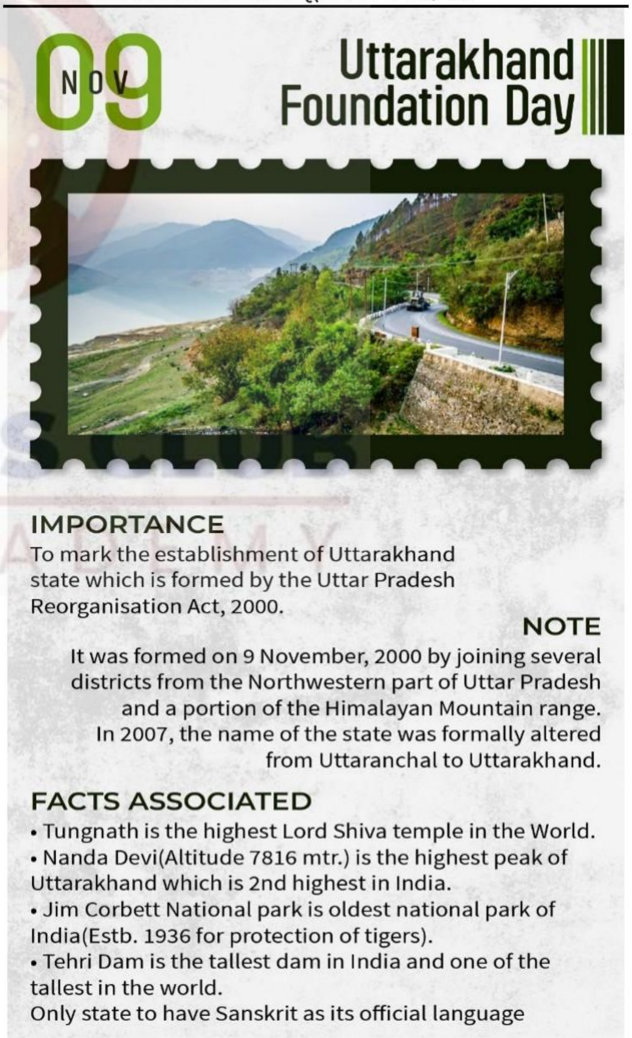

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत ने सिकल सेल बीमारी के लिए पहली देसी CRISPR-बेस्ड जीन थेरेपी लॉन्च की

भारत ने सिकल सेल बीमारी के लिए पहली देसी CRISPR जीन थेरेपी लॉन्च की

साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली CRISPR-बेस्ड जीन थेरेपी, BIRSA 101 को लॉन्च किया, जिसका मकसद सिकल सेल बीमारी का इलाज करना है, जो आदिवासी आबादी पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। इस थेरेपी का नाम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह पर उनके सम्मान में रखा गया है।

सिकल सेल बीमारी से मुक्त भारत की ओर एक बड़ा कदम

यह लॉन्च भारत की पब्लिक हेल्थ और जीनोमिक मेडिसिन की यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जो सिकल सेल बीमारी को खत्म करने के लिए देश भर में कोशिशों की शुरुआत का संकेत देता है।

जीनोमिक मेडिसिन में सस्ती सफलता

डॉ. सिंह ने बताया कि यह देसी थेरेपी दुनिया की कीमतों के बहुत कम दाम पर लेटेस्ट इलाज बनाने की भारत की क्षमता दिखाती है, जो विदेशी थेरेपी की जगह लेती है जिनकी कीमत ₹20-25 करोड़ होती है।

आदिवासी समुदायों पर फोकस

यह इनोवेशन देश भर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिकल सेल बीमारी सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के आदिवासी इलाकों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है।

लोगों में जागरूकता और साफ़ बातचीत की अपील

मंत्री ने साइंटिफिक संस्थानों से अपील की कि वे इन्फोग्राफिक्स और सोशल मीडिया के ज़रिए मुश्किल खोजों को आसान बनाएं ताकि लोगों को समझ में आए।

स्वदेशी CRISPR प्लेटफॉर्म बनाया गया

CSIR-IGIB ने सिकल सेल डिज़ीज़ (SCD) के लिए एक भारतीय CRISPR-बेस्ड जीन-एडिटिंग थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (SII) के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है। यह थेरेपी IGIB के हाई-फिडेलिटी enFnCas9 प्लेटफॉर्म पर बनी है।

लक्ष्य: सस्ता सिकल सेल इलाज

SII SCD का एक सस्ता इलाज बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल करेगा, जिससे भारत में हर साल 15,000-20,000 बच्चे प्रभावित होते हैं। BIRSA 101 नाम की इस स्वदेशी थेरेपी से इलाज का खर्च ₹20-25 करोड़ से घटकर लगभग ₹50 लाख होने की उम्मीद है।

INS सह्याद्री ने एक्सरसाइज मालाबार के समुद्री फेज़ में हिस्सा लिया

INS सह्याद्री ने एक्सरसाइज मालाबार 2025 में हिस्सा लिया

भारत के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट, INS सह्याद्री ने गुआम के पास एक्सरसाइज मालाबार 2025 के समुद्री फेज़ में हिस्सा लिया।

इंडो-पैसिफिक में इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना

INS सह्याद्री का हिस्सा लेना पार्टनर देशों के साथ जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाने के भारत के कमिटमेंट को दिखाता है।

स्वदेशी कैपेबिलिटी शोकेस

भारत में डिज़ाइन और बनाया गया, INS सह्याद्री 'आत्मनिर्भर भारत' विज़न को दिखाता है और इसने कई मल्टीनेशनल ऑपरेशन और एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है।

मालाबार एक्सरसाइज के बारे में

- मालाबार एक हाई-एंड नेवल एक्सरसाइज है जिसमें क्वाड देश — भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- यह 1992 में एक बाइलेटरल इंडिया-US ड्रिल के तौर पर शुरू हुआ था और बाद में इसमें जापान (2015) और ऑस्ट्रेलिया (2020) को शामिल किया गया।
- इस एक्सरसाइज का मकसद इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करना और एक आज़ाद और खुले इंडो-पैसिफिक को बनाए रखना है।

विकास

शुरू में एक बाइलेटरल इंडिया-US ड्रिल, मालाबार को जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है, जिससे यह एक अहम क्वाड नेवल एक्सरसाइज बन गई है जो इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की आज़ादी को सपोर्ट करती है।

स्पेसएक्स ने समुद्र तल परिवर्तन की निगरानी के लिए नासा के सेंटिनल-6B उपग्रह का प्रक्षेपण किया

स्पेसएक्स ने वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से नासा के सेंटिनल-6B उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह मिशन बढ़ते समुद्र तल की निगरानी के वैश्विक प्रयासों को मज़बूत करता है।

सेंटिनल-6B मिशन का उद्देश्य

सेंटिनल-6B को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है:

- वैश्विक समुद्र तल में वृद्धि की निगरानी
- समुद्र की स्थिति का अवलोकन
- मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार
- तटीय योजना और सुरक्षा में सहायता
- यह 30 वर्षों से अधिक समय से समुद्र तल के अवलोकन के कार्य को जारी रखता है, और महासागर-निगरानी उपग्रहों की लंबी परंपरा पर आधारित है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- यह उपग्रह संयुक्त रूप से विकसित किया गया है:

- नासा (अमेरिका)
- यूरोपीय साझेदार, जिनमें ESA और EUMETSAT शामिल हैं

यह सहयोग वैश्विक जलवायु और महासागर अनुसंधान को आगे बढ़ाता है।

सेंटिनल-6 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह

सेंटिनल-6B, नवंबर 2020 में फाल्कन 9 द्वारा प्रक्षेपित सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच का अनुसरण करता है।

दोनों उपग्रह मिलकर निम्नलिखित के उच्च-सटीक माप प्रदान करेंगे:

- समुद्र तल में वृद्धि
- महासागरीय धाराएँ
- हवा और लहरों के पैटर्न

कवरेज और डेटा गुणवत्ता

सेंटिनल-6B पृथ्वी के 90% महासागरों का डेटा एकत्र करेगा, जो वैज्ञानिक और सार्वजनिक अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत सटीक माप प्रदान करेगा।

सार्वजनिक सुरक्षा और तटीय नियोजन के लिए लाभ

यह मिशन निम्नलिखित में मदद करेगा:

- तटीय बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा
- शहर नियोजन और आपदा प्रबंधन का मार्गदर्शन
- ऊर्जा सुविधाओं और अचल संपत्ति के लिए निर्णय लेने में सहायता
- जलवायु अनुकूलन में स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता

मौसम पूर्वानुमान के लिए सहायता

उपग्रह से प्राप्त डेटा में सुधार होगा:

- दैनिक मौसम पूर्वानुमान
- महासागरीय धाराओं का पूर्वानुमान
- तूफान/टाइफून ट्रैकिंग
- तूफान की तीव्रता का पूर्वानुमान
- यह समुद्री नौवहन और आपदा तैयारियों में सहायता करता है।

भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में भूमिका

सेंटिनल-6B डेटा नासा को अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित पुनःप्रवेश पथों की योजना बनाने में मदद करेगा, जिसमें चंद्रमा से लौटने वाले भविष्य के आर्टेमिस मिशन भी शामिल हैं।

रक्षा और सुरक्षा महत्व

उपग्रह निम्नलिखित में मदद करेगा:

- तटीय सैन्य प्रतिष्ठानों को बाढ़ से बचाना
- सटीक मौसम और महासागरीय स्थिति डेटा के साथ राष्ट्रीय रक्षा अभियानों का समर्थन करना

भारत ने नेवल माइन वॉरफेयर के लिए नेक्स्ट-जेन ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल बनाए

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRdo) ने मैन-पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (MP-AUVs) को सफलतापूर्वक डेवलप किया है, जिन्हें माइन काउंटरमेजर (MCM) मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि पानी के अंदर की माइन का पता लगाया जा सके और उन्हें बेअसर किया जा सके। इस एडवांस्ड सिस्टम को नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL), विशाखापत्तनम ने डेवलप किया है, जिसमें रियल-टाइम सर्विलांस के लिए साइड-स्कैन सोनार और अंडरवाटर कैमरे जैसे पेलोड हैं। डीप-लर्निंग-बेस्ड टारगेट रिकग्निशन और अंडरवाटर अकूस्टिक कम्युनिकेशन से लैस, ये कॉम्पैक्ट AUVs नेवी के लिए ऑपरेशनल रिस्क को कम करेंगे और अंडरवाटर मिशन के दौरान माइन का तेज़ और ज़्यादा सटीक पता लगाना पक्का करेंगे।

इस्तेमाल की गई खास टेक्नोलॉजी:

- रियल-टाइम माइन डिटेक्शन के लिए साइड स्कैन सोनार और अंडरवाटर कैमरे
- ऑटोमैटिक माइन क्लासिफिकेशन के लिए डीप लर्निंग-बेस्ड AI एल्गोरिदम
- कोऑर्डिनेटेड मल्टी-AUV ऑपरेशन के लिए अंडरवाटर अकूस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम

MP-AUV के फायदे

- पोर्टेबल → मैन-पोर्टेबल और लाइटवेट
- फास्ट डिप्लॉयमेंट → रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी
- नेवी डाइवर्स और माइनस्वीपर्स के लिए कम रिस्क
- नेटवर्क-इनेबल्ड ऑपरेशन (मल्टीपल AUV कोलेबोरेशन)
- कम मिशन टाइम और लॉजिस्टिक एफर्ट

स्टेटस

- NSTL हार्बर पर सफल फील्ड ट्रायल किए गए
- कई इंडियन इंडस्ट्रीज़ शामिल → प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होगा
- साइंटिस्ट्स ने एक ज़िंदा पौधे के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स खोजे — दुनिया में पहली बार
- चीन के साइंटिस्ट्स की एक टीम ने, दुनिया में पहली बार, एक ज़िंदा फ़र्न के अंदर कुदरती तौर पर बने रेयर-अर्थ मिनरल्स (मोनाज़ाइट) खोजे हैं।
- यह नई खोज फाइटोमाइनिंग के ज़रिए इको-फ्रेंडली माइनिंग में क्रांति ला सकती है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे मिट्टी से मेटल निकालते हैं।

स्टडी की डिटेल्स

पब्लिश हुआ: एनवायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (2025)

इसमें शामिल इंस्टीट्यूशन्स:

- गुआंगज़ौ इंस्टीट्यूट ऑफ़ जियोकेमिस्ट्री, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़
- वर्जीनिया टेक, यूनाइटेड स्टेट्स
- खोज की जगह: ग्वांगज़ौ के पास, दक्षिणी चीन
- पौधा जिस पर स्टडी की गई: ब्लेचनम ओरिएंटेल (एक सदाबहार फ़र्न जिसे रेयर-अर्थ हाइपरएक्यूमुलेटर के नाम से जाना जाता है)
- रिसर्चर्स ने फ़र्न के टिशूज़ के अंदर नैनोस्केल मोनाज़ाइट खोजा, जिससे यह साबित होता है कि पौधे नॉर्मल अर्थ-सरफेस

कंडीशन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कुदरती तौर पर क्रिस्टलाइज़ कर सकते हैं — एक ऐसी चीज़ जिसे पहले सिर्फ़ बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर में ही मुमकिन माना जाता था।

मोनाज़ाइट क्या है?

- टाइप: फॉस्फेट मिनरल जिसमें सेरियम, लैंथेनम और नियोडिमियम (मुख्य रेयर-अर्थ एलिमेंट) भरपूर होते हैं।
- गुण: हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्टिकल एमिसिविटी, करोज़न और रेडिएशन रेजिस्टेंस।
- इस्तेमाल: लेज़र, कोटिंग, लाइट एमिटर, आयनिक कंडक्टर और रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट।

फाइटोमाइनिंग क्या है?

- फाइटोमाइनिंग एक ग्रीन एक्सट्रैक्शन तकनीक है जिसमें मिट्टी से मेटल या मिनरल निकालने के लिए हाइपरएक्यूमुलेटर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है।
- ये प्लांट अपने आस-पास की तुलना में सैकड़ों से हज़ारों गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन में हेवी मेटल जमा करते हैं।
- बाद में काटे गए प्लांट बायोमास से मेटल निकाले जाते हैं, जिससे पारंपरिक माइनिंग पर निर्भरता कम हो जाती है।
- यह खोज "ग्रीन सर्कुलर मॉडल" को सपोर्ट करती है — यह ज़रूरी मिनरल को निकालने का एक सस्टेनेबल, कम असर वाला तरीका है।

यह क्यों ज़रूरी है

- पारंपरिक माइनिंग से होने वाले एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को कम कर सकता है।
- रेयर-अर्थ एक्सट्रैक्शन के लिए एक सस्टेनेबल और कम लागत वाला विकल्प देता है।
- रेयर-अर्थ सप्लाई चेन में जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम करने में मदद करता है, जिस पर अभी चीन का दबदबा है।

यूनिक साइंटिफिक इनसाइट

- रिसर्चर्स ने पौधों में मोनाज़ाइट बनने की तुलना एक "केमिकल गार्डन" से की — जहाँ पानी में मेटल सॉल्ट पौधे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं।
- यह घटना जीवित जीवों के अंदर मिनरल बनने के लिए एक नए बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को दिखाती है।

NASA का मंगल ग्रह के लिए ESCAPADE मिशन लॉन्च हुआ

NASA ने 12 नवंबर, 2025 को ESCAPADE मिशन (एस्केप और प्लाज़्मा एक्सेलेरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स) के तहत दो छोटे स्पेसक्राफ्ट—ब्लू और गोल्ड—सफलतापूर्वक लॉन्च किए। मिशन का मकसद यह स्टडी करना है कि सोलर विंड मंगल ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फियर के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, जिससे साइंटिस्ट्स को यह समझने में मदद मिलेगी कि समय के साथ लाल ग्रह ने अपना ज़्यादातर एटमॉस्फियर कैसे खो दिया।

मिशन टाइमलाइन

- लॉन्च की तारीख: 12 नवंबर, 2025
- शुरुआती ऑर्बिट: ये दोनों स्पेसक्राफ्ट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के लिए लगभग एक साल तक पृथ्वी के ऑर्बिट में रहेंगे।
- मंगल ग्रह के लिए निकलना: नवंबर 2026
- मंगल ग्रह पर पहुंचने की उम्मीद: 2027

मिशन के मकसद

- सोलर विंड और मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के बीच इंटरेक्शन की स्टडी करना।
- यह एनालाइज़ करना कि ये इंटरेक्शन एटमॉस्फियरिक एस्केप का कारण कैसे बनते हैं, जिससे ग्रह के क्लाइमेट इवोल्यूशन को शेप मिलता है। ऐसा डेटा इकट्ठा करना जो MAVEN (मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन) जैसे दूसरे मार्स मिशन के नतीजों को सपोर्ट करेगा।

शामिल मुख्य संस्थाएँ

- लीड एजेंसी: NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन)
- प्रोजेक्ट लीड: UC बर्कले की स्पेस साइंसेज़ लेबोरेटरी (SSL)

मिशन पार्टनर:

- रॉकेट लैब – NASA के स्मॉल इनोवेटिव मिशन्स फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन (SIMPLEx) प्रोग्राम के तहत लॉन्च प्रोवाइडर।
- NASA का गोडार्ड स्पेस फ़्लाइट सेंटर – मिशन मैनेजमेंट सपोर्ट देता है।

साइंटिफिक महत्व

- ESCAPADE मार्स के चारों ओर प्लाज़्मा और मैग्नेटिक फ़ील्ड्स का एक साथ दो-पॉइंट मेज़रमेंट देगा—ऐसा पहले किसी मिशन ने नहीं किया है।
- यह डेटा साइंटिस्ट्स को मार्स के एटमोस्फियरिक नुकसान और पहले रहने लायक होने की इसकी क्षमता को समझने में मदद करेगा।
- इनसाइट्स मार्स पर स्पेस वेदर के असर का अनुमान लगाकर भविष्य में इंसानों की खोज में भी मदद कर सकती हैं।

बैकग्राउंड और रेलिवेंस

- ESCAPADE, NASA के स्मॉल इनोवेटिव मिशन्स फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन (SIMPLEx) इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसे छोटे स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके कम लागत वाले प्लैनेटरी साइंस मिशन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह मिशन NASA के MAVEN मिशन (2014) से मिली जानकारी पर बना है, जिसने मंगल ग्रह के ऊपरी एटमॉस्फियर की स्टडी की थी।
- मंगल ग्रह के मैग्नेटिक और एटमॉस्फियरिक प्रोसेस को समझना क्लाइमेट इवोल्यूशन स्टडीज़ और लॉन्ग-टर्म स्पेस कॉलोनाइज़ेशन प्लानिंग के लिए ज़रूरी है।

भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप (QDM) पेश किया

भारत ने देश के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप (QDM) के डेवलपमेंट के साथ क्वांटम सेंसिंग और इमेजिंग

टेक्नोलॉजी में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस माइक्रोस्कोप को IIT बॉम्बे के P-Quest ग्रुप ने डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) के नेशनल क्वांटम मिशन (NQM) के तहत डेवलप किया है। यह कामयाबी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोपी के फील्ड में भारत का पहला पेटेंट है, जिससे क्वांटम रिसर्च और इनोवेशन में देश की स्थिति मज़बूत हुई है।

ESTIC 2025 में लॉन्च

क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप (QDM) को इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC 2025) के दौरान ऑफिशियली लॉन्च किया गया। इस मौके पर ये लोग मौजूद थे:

- डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री
- प्रो. अजय के. सूद, भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर
- प्रो. अभय करंदीकर, सेक्रेटरी, DST
- IIT बॉम्बे और DST के सीनियर साइंटिस्ट और अधिकारी।
- P-Quest Group, IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है।
- इस प्रोजेक्ट को IIT बॉम्बे में प्रो. कस्तूरी साहा और उनकी टीम लीड कर रही है।
- QDM डायमंड में नाइट्रोजन-वैकेंसी (NV) सेंटर्स पर आधारित है, जो क्वांटम कोहेरेंस और फ्लोरेसेंस डिटेक्शन के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड्स की नैनोस्केल इमेजिंग की इजाज़त देता है।
- यह माइक्रोस्कोप थ्री-डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड विज़ुअलाइज़ेशन को इनेबल करता है — जो सेमीकंडक्टर डायग्नोस्टिक्स, न्यूरोसाइंस और मटीरियल्स रिसर्च के लिए एक अहम एडवांसमेंट है।

काम करने का तरीका

NV सेंटर हीरे में एटॉमिक-स्केल डिफेक्ट होते हैं, जहाँ एक नाइट्रोजन एटम, खाली जगह के पास कार्बन एटम की जगह ले लेता है।

ये सेंटर कमरे के तापमान पर भी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और थर्मल फील्ड में होने वाले बदलावों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं।

QDM ऑप्टिकली डिटेक्टेड मैग्नेटिक रेजोनेंस (ODMR) का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड डेटा कैप्चर करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लाइट की इंटेंसिटी को देखता है।

एप्लीकेशन और महत्व

सेमीकंडक्टर चिप डायग्नोस्टिक्स: मल्टीलेयर चिप्स में दबे हुए करंट पाथ की नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और 3D मैपिंग को इनेबल करता है।

न्यूरोसाइंस रिसर्च: माइक्रोस्कोपिक लेवल पर न्यूरल मैग्नेटिक एक्टिविटी की स्टडी करने में मदद करता है।

मटीरियल साइंस: एडवांस्ड मटेरियल में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की इमेजिंग की इजाज़त देता है।

भविष्य की संभावनाएँ: बेहतर इमेजिंग और डेटा एनालिसिस के लिए AI और मशीन लर्निंग के साथ इंटीग्रेशन।

महाराष्ट्र सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना

अभूतपूर्व सैटेलाइट इंटरनेट साझेदारी

महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यह एलन मस्क की ब्रॉडबैंड-फ्रॉम-स्पेस फर्म के साथ आधिकारिक रूप से सहयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह कदम राज्य के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक नई मिसाल कायम करता है।

दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी

इस साझेदारी का उद्देश्य गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव (पूर्व में उस्मानाबाद) और वाशिम जैसे आकांक्षी जिलों में सरकारी संस्थानों, गांवों, आदिवासी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक सैटेलाइट-आधारित हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाना है।

डिजिटल महाराष्ट्र मिशन के साथ रणनीतिक तालमेल

यह सहयोग महाराष्ट्र की प्रमुख डिजिटल महाराष्ट्र पहल के साथ संरेखित है और इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे, तटीय विकास और आपदा प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों के साथ एकीकृत है। स्टारलिंक का भारत में प्रवेश भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) द्वारा निम्न-पृथ्वी-कक्षा (LEO) उपग्रह संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए अधिकृत किए जाने के बाद हुआ है, जिससे वाणिज्यिक संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

आईसीटी और डिजिटल परिदृश्य पर प्रभाव

स्टारलिंक 6,000 से अधिक संचार उपग्रहों का संचालन करता है और पारंपरिक भूस्थिर प्रणालियों की तुलना में कम विलंबता वाला इंटरनेट प्रदान करता है। यह साझेदारी भारत में "अंतिम-मील" डिजिटल विभाजन को पाटने के एक नए दृष्टिकोण को दर्शाती है। जहाँ भू-आधारित दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार जारी है, वहीं उपग्रह ब्रॉडबैंड उन क्षेत्रों में एक पूरक समाधान प्रदान करता है जहाँ फाइबर या मोबाइल नेटवर्क किफायती नहीं हैं।

महाराष्ट्र

- राजधानी: मुंबई और नागपुर (शीतकालीन)
- राज्यपाल: आचार्य देवव्रत (अतिरिक्त प्रभार)
- मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस (भाजपा)
- उपमुख्यमंत्री: अजीत पवार (राकांपा) और एकनाथ शिंदे (एसएचएस)

भारत ने श्रीहरिकोटा से सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से LVM3-M5 रॉकेट के ज़रिए भारत के सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM3) — जिसे GSLV Mk-III के नाम से भी जाना जाता है, की पाँचवीं परिचालन उड़ान है, जो भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह मिशन सामरिक संचार और अंतरिक्ष रक्षा में भारत की बढ़ती क्षमताओं की पुष्टि करता है।

CMS-03 उपग्रह की मुख्य विशेषताएँ

- प्रकार: सैन्य-नागरिक दोहरे उपयोग वाला संचार उपग्रह
- भार: लगभग 4,400 किलोग्राम, जो इसे अब तक प्रक्षेपित भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह बनाता है।
- कक्षा: भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO)
- उद्देश्य: भारत और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षित, बहु-बैंड संचार सेवाएँ प्रदान करना।

अनुप्रयोग:

- रणनीतिक सैन्य संचार को मज़बूत बनाना।
- रक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए सुरक्षित डेटा, ध्वनि और वीडियो लिंक सक्षम करना।
- डिजिटल कनेक्टिविटी, टेलीमेडिसिन और टेली-शिक्षा को बढ़ावा देना।
- सरकारी कार्यों के लिए नेटवर्क सुरक्षा को बढ़ाना।

LVM3 प्रक्षेपण यान के बारे में

- पूर्ण रूप: प्रक्षेपण यान मार्क-3
- इसे GSLV Mk-III (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) के नाम से भी जाना जाता है।
- प्रकार: तीन-चरणीय भारी-उठाने वाला प्रक्षेपण यान
- पहला चरण: ठोस बूस्टर (S200)
- दूसरा चरण: द्रव कोर (L110)
- तीसरा चरण: क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (C25)

पेलोड क्षमता:

- निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में 8,000 किलोग्राम तक
- जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में 4,000-4,500 किलोग्राम तक
- पिछले मिशन: चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और वनवेब उपग्रह मिशन।

इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के बारे में

- स्थापना: 1969
- मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
- अध्यक्ष: डॉ. वी. नारायणन (2025 से)
- मुख्य विभाग: अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार

उल्लेखनीय मिशन:

- चंद्रयान-3 (2023): भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना।
- आदित्य-एल1 (2023): भारत का पहला सौर मिशन, जो वर्तमान में कार्यरत है।
- गगनयान मिशन (2025-26): भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन (आगामी)।

हांगकांग का स्टार्टअप 3D पवन डेटा के लिए दुनिया का पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च करेगा

जलवायु निगरानी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में, हांगकांग स्थित स्टार्टअप स्टेलेरस टेक्नोलॉजी ने फीलियन तारामंडल के लॉन्च की घोषणा की है—यह दुनिया का पहला उपग्रह नेटवर्क है जो त्रि-आयामी (3D) पवन डेटा एकत्र करने के लिए समर्पित है। प्राचीन चीनी पवन देवता "फीलियन" के नाम पर रखा गया यह तारामंडल, वायुमंडलीय अवलोकन और मौसम संबंधी पूर्वानुमान में क्रांति लाने का लक्ष्य रखता है। यह परियोजना पवन गति, दिशा और ऊर्ध्वाधर गति—ऐसे मापदंडों, जिन्हें वर्तमान में वैश्विक मौसम विज्ञान में कम मापा जाता है—के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन, विमानन सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और जलवायु जोखिम मॉडलिंग में सुधार की अपार संभावनाएँ रखती है।

मौसम संबंधी डेटा की कमी को पाटना

वर्तमान में, 3D पवन डेटा मुख्य रूप से मौसम गुब्बारों और विमान सेंसरों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो विशेष रूप से महासागरों और दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित और असंगत कवरेज प्रदान करते हैं। फीलियन नक्षत्र का लक्ष्य छह उपग्रहों को तैनात करके इस कमी को पूरा करना है जो प्रति घंटे, किलोमीटर-पैमाने पर वैश्विक 3D पवन मानचित्र तैयार करने में सक्षम हैं।

- पहला प्रक्षेपण: 18 महीनों के भीतर अपेक्षित
- पूर्ण नक्षत्र की तैनाती: प्रारंभिक प्रक्षेपणों के तुरंत बाद योजना बनाई जाएगी

इसरो ने CMS-03 संचार उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए LVM3 रॉकेट तैयार किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने CMS-03 मिशन के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) के लिए अपना LVM3 (प्रक्षेपण यान मार्क-3) रॉकेट रवाना कर दिया है। यह मिशन भारत के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान, LVM3 की पाँचवीं परिचालन उड़ान है। यह रॉकेट लगभग 4,400 किलोग्राम भार वाले CMS-03 संचार उपग्रह को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित करेगा। इसरो द्वारा विकसित CMS-03 उपग्रह, भारतीय मुख्य भूमि और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में संचार सेवाओं को बेहतर बनाने, विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। LVM3, जिसने पहले चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था, भारी-भरकम प्रक्षेपण तकनीक और उपग्रह-आधारित संचार प्रणालियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- LVM3 का पूर्ण रूप: प्रक्षेपण यान मार्क-3
- पूर्व नाम: GSLV Mk-III (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क-III)
- पेलोड क्षमता: निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) तक 8,000 किलोग्राम तक; 4,000-4,500 किलोग्राम भार को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में पहुँचाया जाएगा
- प्रक्षेपण स्थल: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC), श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश
- CMS-03 उपग्रह उद्देश्य: बहु-बैंड संचार, इंटरनेट विस्तार और डिजिटल पहुँच
- कक्षा प्रकार: भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO)

LVM3 के पिछले मिशन:

- चंद्रयान-2 (2019)
- चंद्रयान-3 (2023)
- वनवेब उपग्रह प्रक्षेपण (2022-23)

इसरो अध्यक्ष: डॉ. एस. सोमनाथ

- इसरो मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
- स्थापना: 1969
- मूल विभाग: अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार

NASA ने 2026 तक गिरती स्विफ्ट ऑब्ज़र्वेटरी को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन के लिए स्टार्टअप को हायर किया

NASA का अर्जेंट मिशन: NASA अपनी स्विफ्ट ऑब्ज़र्वेटरी को बचाने के लिए एक स्टार्टअप को पेमेंट कर रहा है, जिसके 2026 के आखिर तक बिना कंट्रोल के वापस आने का बहुत ज़्यादा खतरा है।

स्टार्टअप और उसका प्लान: कैटालिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज़, स्विफ्ट से मिलने और उसके ऑर्बिट को बढ़ाने के लिए LINK नाम का एक स्पेसक्राफ्ट बना रही है।

स्विफ्ट को मदद की ज़रूरत क्यों है: एटमोस्फेरिक ड्रैग की वजह से स्विफ्ट धीरे-धीरे ऊंचाई खो रहा है, जिससे उसके वापस आने की संभावना बढ़ रही है।

लॉन्च स्ट्रैटेजी: LINK को एक पेगासस XL रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया जाएगा, जिसे उड़ान के बीच में प्लेन से गिराया जाएगा।

रेस्क्यू कैसे काम करेगा: क्योंकि स्विफ्ट में डॉकिंग पोर्ट नहीं हैं, LINK इसके बाहरी स्ट्रक्चर को पकड़ने और धीरे-धीरे इसके ऑर्बिट को ऊपर उठाने के लिए एक रोबोटिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा।

महत्व: अगर यह मिशन सफल रहा, तो यह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा: एक प्राइवेट क्राफ्ट जो सर्विसिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए सैटेलाइट की लाइफ बढ़ाएगा।

NASA

- निर्माण: 29 जुलाई, 1958
- पिछली एजेंसी: नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स (1915–1958)
- हेडक्वार्टर: वाशिंगटन, D.C.
- एडमिनिस्ट्रेटर: शॉन डफी (एक्टिंग)

स्पेसटेक स्टार्टअप ग्रहा को ब्राज़ील से नैनोसैटेलाइट लॉन्च करने की मंज़ूरी मिली

IN-SPACe ने ग्रहा के नैनो-सैटेलाइट मिशन को मंज़ूरी दी: ग्रहा स्पेस को अपने पहले नैनो-सैटेलाइट मिशन, सोलारास S2 के लिए IN-SPACe से मंज़ूरी मिल गई है, जिसे नवंबर के आखिर तक लॉन्च किया जाना है।

लॉन्च प्लान और वाहन: सैटेलाइट को ब्राज़ील के अल्केन्टारा स्पेस सेंटर से कोरिया के इनोस्पेस के बनाए हनबिट-नैनो रॉकेट का इस्तेमाल करके लॉन्च किया जाएगा।

ग्रहा स्पेस के पीछे कौन है: ग्रहा स्पेस, जिसे ISRO के एक पुराने साइंटिस्ट और IBM के पुराने कर्मचारी ने मिलकर शुरू किया था, लगभग रियल-टाइम अर्थ-ऑब्ज़र्वेशन डेटा देने के लिए नैनो-सैट का एक ग्रुप बना रहा है।

सोलारास S2 क्या करेगा: यह मिशन ग्रहा के सैटेलाइट बस और सबसिस्टम को "क्वालिफ़ाई" करेगा — यह स्केल अप करने से पहले एक टेक्निकल डेमोंस्ट्रेशन स्टेप है।

बड़ा विज़न: ग्रहा का मकसद ऑप्टिकल पेलोड, इंटर-सैटेलाइट लिंक और लाइव जियोस्पेशियल डेटा के साथ एक भरोसेमंद नैनो-सैटेलाइट नेटवर्क बनाने के लिए (2026 और उसके बाद) और सैटेलाइट लॉन्च करना है।

ग्रहा स्पेस

- हेडक्वार्टर: बेंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया
- CEO: रमेश कुमार वी
- फाउंडेशन: 29 सितंबर 2021
- इंडस्ट्री: स्पेस टेक्नोलॉजी / न्यूस्पेस
- प्रोडक्ट्स: नैनोसैटेलाइट्स, ग्राउंड स्टेशन्स, सैटेलाइट डिप्लॉयर्स

लघु लेख

गुजरात ने ट्राइबल जीनोम-सीक्वेंसिंग पहल शुरू की

गुजरात अपनी ट्राइबल आबादी के लिए एक खास जीनोम-सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस अहम पहल की घोषणा ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने की, जो साइंटिफिक इनोवेशन को सोशल वेलफेयर के साथ जोड़ने के लिए एक मज़बूत कमिटमेंट का संकेत देता है। इसका मकसद पूरे राज्य में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए खास तौर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक रेफरेंस रजिस्ट्री बनाना है।

प्रोजेक्ट के मकसद और स्कोप

"गुजरात में ट्राइबल आबादी के लिए रेफरेंस जीनोम डेटाबेस बनाना" नाम के इस प्रोजेक्ट में 17 जिलों में फैले ट्राइबल कम्युनिटी के लगभग 2,000 लोग शामिल होंगे। इसका मकसद 20 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप को कवर करना है, जिसमें पुराने समय से पिछड़े कम्युनिटी भी शामिल हैं। होल-जीनोम सीक्वेंसिंग करके, राज्य को उम्मीद है कि वह ट्राइबल कम्युनिटी से उनके खास जेनेटिक आर्किटेक्चर की स्टडी करने के लिए डिटेल्ड जेनेटिक डेटा इकट्ठा कर सकेगा।

हेल्थ बेनिफिट्स और जेनेटिक इनसाइट्स

इस प्रोजेक्ट के पीछे एक मुख्य मकसद सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी इनहेरिटेड और हेरेडिटरी बीमारियों से जुड़े जेनेटिक मार्कर की पहचान करना है, जो ट्राइबल आबादी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। डेटा से इम्यून-रेज़िस्टेंस के ऐसे लक्षण भी पता चल सकते हैं जो कुछ खास आदिवासी ग्रुप के लिए खास हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल पब्लिक-हेल्थ दखल को बेहतर बनाने, ज़्यादा असरदार इलाज डिज़ाइन करने और आदिवासी

इलाकों में शुरुआती डायग्नोस्टिक तरीकों को शुरू करने के लिए किया जा सकता है।

लागू करने की स्ट्रैटेजी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क

गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सीक्वेंसिंग करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस स्ट्रैटेजी में, जहाँ मुमकिन हो, जेनेटिक ट्रायोस (माता-पिता दोनों और एक बच्चा) में लोगों की सैंपलिंग करना और महिलाओं की 50% भागीदारी के टारगेट के साथ जेंडर रिप्रेजेंटेशन पक्का करना शामिल है। इस प्रोजेक्ट को नैतिक स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए साइंटिफिक रूप से सख्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जेनेटिक टेस्टिंग को सस्ता बनाना

पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग के अलावा, रिसर्चर कम लागत वाले जेनेटिक टेस्टिंग पैनल बनाने की योजना बना रहे हैं, जिनका मकसद आदिवासी आबादी में आम जेनेटिक बीमारियों की स्क्रीनिंग करना है। इन टेस्टिंग पैनल की कीमत ₹1,000–₹1,500 प्रति टेस्ट के बीच होने की उम्मीद है, जिससे वे बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए आसानी से मिल सकें। इस तरह के इनोवेशन में जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स को डेमोक्रेटाइज़ करने और बड़े पैमाने पर बचाव के हेल्थ उपाय करने की क्षमता है।

पॉलिसी का महत्व: साइंस और सोशल इक्विटी को जोड़ना

यह पहल सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। आदिवासी समुदायों की भलाई के लिए लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, गुजरात हेल्थ में भेदभाव को कम कर रहा है और बराबरी को बढ़ावा दे रहा है। इससे बनने वाला जीनोमिक डेटाबेस पब्लिक पॉलिसी के फैसले लेने में मदद कर सकता है, जल्दी डायग्नोसिस और बचाव के केयर प्रोग्राम को मज़बूत कर सकता है, और यह पक्का कर सकता है कि आदिवासी समुदायों को उनके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से हेल्थ इंटरवेंशन मिलें।

भारत का सबसे भारी उपग्रह प्रक्षेपण: अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ी छलांग

ऐतिहासिक प्रक्षेपण कार्यक्रम

2 नवंबर 2025 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने LVM3-M5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से अब तक के अपने सबसे भारी संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। 4,410 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह को लगभग 29,970 किलोमीटर की अपभू वाली भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित किया गया - यह उपलब्धि हासिल करने के लिए आदर्श 36,000 किलोमीटर की कक्षा से थोड़ा कम है।

वाहन: भारत का सबसे बड़ा प्रक्षेपण रॉकेट

LVM3 (पूर्व में GSLV Mk III) भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। M5 विन्यास के साथ, यह 8,000 किलोग्राम तक का भार निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में और लगभग 4,000 किलोग्राम तक का भार GTO में ले जाने में सक्षम है। यह विशेष प्रक्षेपण GTO में 4,000 किलोग्राम से अधिक भार ले जाने की इसकी क्षमता को बढ़ाता है, जो इसरो के लिए पहली बार है। रॉकेट में ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक प्रणोदन वाला एक कोर चरण शामिल है, जो इसके उन्नत इंजीनियरिंग डिज़ाइन को दर्शाता है।

यह प्रक्षेपण क्यों महत्वपूर्ण है

अब तक, भारत भारी उपग्रहों को ऊँची कक्षाओं में स्थापित करने के लिए अक्सर विदेशी प्रक्षेपण प्रदाताओं (जैसे एरियनस्पेस या स्पेसएक्स) पर निर्भर रहता था। अब यह निर्भरता कम हो रही है। यह मिशन भारत के एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष-यात्रा राष्ट्र बनने की दिशा में प्रगति का संकेत देता है - जो स्वदेशी रूप से बड़े उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण करने में सक्षम है। यह भारत के नियोजित मानव-आधारित मिशनों, जैसे कि गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, के लिए भी सीधा आधार तैयार करता है।

तकनीकी विवरण और उन्नयन

इस उपग्रह का वजन 4,410 किलोग्राम है, जो GTO के लिए 4 टन की सीमा को पार करने वाला पहला भारत निर्मित दूरसंचार उपग्रह है।

इसरो ने मानक GTO की तुलना में स्थानांतरण कक्षा को थोड़ा कम करके यह उपलब्धि हासिल की, जिससे यान का पेलोड भार कम हो गया।

भविष्य के उन्नयन पर पहले से ही काम चल रहा है: बढ़े हुए प्रणोदक भार और थ्रस्ट के साथ एक नए क्रायोजेनिक चरण (C32) की योजना बनाई गई है जो लॉन्चर की क्षमता को LEO में लगभग 10,000 किलोग्राम तक बढ़ा देगा। द्रव-ईंधन वाले दूसरे चरण की जगह एक अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन की भी खोज चल रही है।

LVM3 का उड़ान सफलता रिकॉर्ड मज़बूत है: अब तक के सभी सात मिशनों ने कक्षीय लक्ष्यों को प्राप्त किया है, जिससे यह इसरो के सबसे विश्वसनीय वाहनों में से एक बन गया है।

रणनीतिक उपयोग-मामले और दृष्टिकोण

उपग्रह संचार को आगे बढ़ाने के अलावा, यह क्षमता उच्च सामरिक और व्यावसायिक मूल्य को भी उजागर करती है:

भारत के अगली पीढ़ी के दूरसंचार और प्रसारण उपग्रहों की तैनाती, भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना।

अंतरिक्ष अवसंरचना में अधिक स्वायत्तता, विदेशी प्रक्षेपण सेवाओं पर निर्भरता को कम करना।

मानव अंतरिक्ष उड़ान और भारी गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए भविष्य की तैयारी।

आगे की राह: आज के प्रक्षेपण से आगे

हालाँकि LVM3-M5 प्रक्षेपण एक मील का पत्थर है, अंतरिक्ष एजेंसी की नज़रें दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं पर टिकी हैं:

चंद्रमा मिशनों के लिए लक्षित, LEO में 80 टन तक भार ले जाने में सक्षम, अगली पीढ़ी के वाहन, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV) का विकास।

वैश्विक बाज़ार में उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण गति और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करना।

प्रक्षेपण विकल्पों को व्यापक बनाने और लागत कम करने के लिए सेमी-क्रायोजेनिक इंजन जैसे उन्नयन का लाभ उठाना।

वैश्विक तुलना: भारत का सबसे भारी उपग्रह कैसा है

इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह (4,410 किलोग्राम) भारत को ब्रॉडबैंड, दूरस्थ संपर्क और रणनीतिक

अनुप्रयोगों के लिए उच्च क्षमता वाले, बहु-बीम संचार उपग्रहों को तैनात करने में सक्षम देशों की एक विशिष्ट श्रेणी में रखता है। वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना इस प्रकार है:

देश/एजेंसी उपग्रह का नाम प्रक्षेपण द्रव्यमान उद्देश्य/क्षमताएँ प्रक्षेपण यान

भारत (इसरो) GSAT-N2 / LVM3-M5 पेलोड (2025) 4,410 किग्रा मल्टी-बैंड (C, Ku, Ka) संचार; डिजिटल कनेक्टिविटी, दूरस्थ शिक्षा, आपदा प्रतिक्रिया LVM3-M5

संयुक्त राज्य अमेरिका (NASA / SpaceX / बोइंग) ViaSat-3 अमेरिका 6,400 किग्रा वैश्विक ब्रॉडबैंड और डेटा ट्रांसमिशन (1 Tbps क्षमता) Falcon Heavy

यूरोप (ESA / Airbus) Eutelsat Konnect VHTS 6,400 किग्रा उच्च गति वाला यूरोपीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क, डिजिटल अवसंरचना Ariane 5

चीन (CASC) ChinaSat-16 (Shijian-13) 4,600 किग्रा Ka-बैंड उच्च-थ्रूपुट उपग्रह; इंटरनेट और 4K टीवी लॉन्ग मार्च 3B

जापान (JAXA) किज़ुना (WINDS) 4,850 किलोग्राम हाई-स्पीड इंटरनेट और आपदा संचार H-IIA रॉकेट

रूस (रोस्कोस्मोस) एक्सप्रेस AMU3 / AMU7 4,100–4,400 किलोग्राम प्रसारण, ब्रॉडबैंड और मोबाइल संचार प्रोटॉन-एम

भारत की स्थिति

4.4 टन के उपग्रह के साथ, भारत अब मध्यम-भारी उपग्रह खंड में जापान और रूस के बराबर प्रतिस्पर्धा कर रहा है, हालाँकि अभी भी अमेरिका और यूरोप के प्रभुत्व वाले अति-भारी श्रेणी (6-7 टन) से नीचे है।

LVM3 लॉन्चर, जो 4 टन वजन को GTO में ले जाने में सक्षम है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत को अब भारी उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए एरियनस्पेस (यूरोप) पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है - अंतरिक्ष रसद में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम।

नए उपग्रह का मल्टी-बैंड पेलोड और उच्च थ्रूपुट इसे डिजिटल इंडिया पहल, ग्रामीण ब्रॉडबैंड और सुरक्षित संचार के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है।

सारांश में

सफल LVM3-M5 मिशन ने एक नया आयाम स्थापित किया है: भारत ने अब घरेलू भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह उपलब्धि केवल एक उपग्रह के प्रक्षेपण से कहीं अधिक है; यह वैश्विक प्रक्षेपण क्षेत्र में इसरो के स्थान को पुष्ट करती है और आत्मनिर्भर एवं महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रमों की ओर भारत की यात्रा को गति प्रदान करती है।

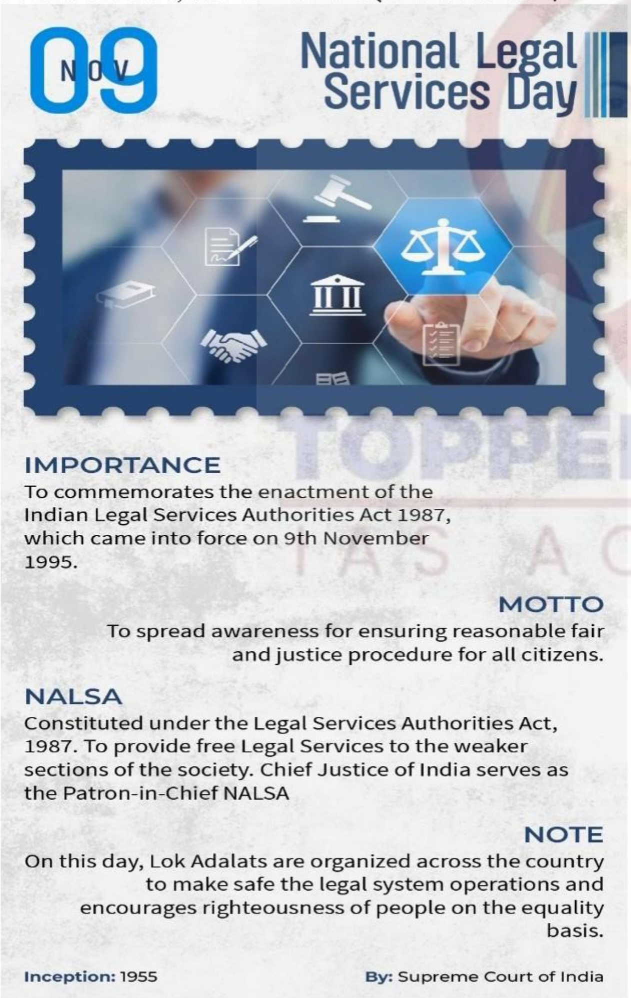

संस्कृति एवं इतिहास

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के पाँच उभरते हुए उपलब्धिकर्ताओं को 'सन्स ऑफ़ द सॉइल' पुरस्कार प्रदान किया

उभरते हुए उपलब्धिकर्ताओं को सम्मानित किया गया

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केयर लुइट द्वारा आयोजित पाँचवें द्विवार्षिक 'सन ऑफ़ द सॉइल' पुरस्कार असम 2025 में असम की पाँच युवा प्रतिभाओं को 'सन्स ऑफ़ द सॉइल' उभरते उपलब्धिकर्ता पुरस्कार' प्रदान किया। इन पुरस्कारों ने असम की उभरती हुई क्षमता को उजागर करते हुए विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता का सम्मान किया।

पुरस्कार विजेता और उनके क्षेत्र

1. सुकृता बरुआ - मीडिया और संचार
2. संघमित्रा कलिता - उद्यमिता
3. इशरानी बरुआ - खेल
4. हिमज्योति तालुकदार - कला और संस्कृति
5. डॉ. देबजानी बोरा - संरक्षण

इन उपलब्धिकर्ताओं को उनके क्षेत्रों में समर्पण, नवाचार और प्रभावशाली योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

आजीवन उपलब्धि पुरस्कार

सोनोवाल ने निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों को उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया:

1. अरुण नाथ - कला एवं संस्कृति
2. रविशंकर रवि - समाचार-मीडिया
3. मैनुद्दीन अहमद - खेल
4. लखीमी बरुआ - उद्यमिता
5. सिमंत दास - लोक सेवा

शिक्षा और सामुदायिक विकास में उनके परिवर्तनकारी कार्यों के लिए डॉ. अलका सरमा और अक्षर फाउंडेशन को सामाजिक क्षेत्र विकास पुरस्कार प्रदान किया गया।

पुरस्कारों का महत्व

2016 में स्थापित, 'सन ऑफ द सॉइल अवार्ड्स' उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जो असम के गौरव, विरासत और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सोनोवाल ने आकांक्षाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए इस पहल की सराहना की।

असम

- राजधानी: दिसपुर
- राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
- मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा (भाजपा)
- राज्यसभा: 7 सीटें
- लोकसभा: 14 सीटें

इंडियन नेवी पहला माहे-क्लास ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट कमीशन करेगी

इंडियन नेवी मुंबई में INS माहे नाम का पहला माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) कमीशन करने वाली है। इससे भारत की कोस्टल डिफेंस और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलेगा।

इंडिजिनल डिफेंस क्षमता

INS माहे को 80% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट के साथ डेवलप किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत वॉरशिप डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और सिस्टम इंटीग्रेशन में भारत की तेज़ी से हो रही तरक्की को दिखाता है। यह प्रोजेक्ट इंडियन इंडस्ट्री और नेवल टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के बीच सफल कोलेबोरेशन को हाईलाइट करता है।

ऑपरेशनल रोल

माहे-क्लास वेसल खास तौर पर लिटोरल वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और ये इन कामों में अहम भूमिका निभाएंगे:

- कम गहरे पानी में दुश्मन की सबमरीन का पता लगाना और उन्हें बेअसर करना
- कोस्टल सर्विलांस और पेट्रोल ड्यूटी
- सी लाइन्स ऑफ़ कम्युनिकेशन (SLOCs) की सुरक्षा
- स्ट्रेटेजिक नेवल बेस और पोर्ट के पास समुद्री सुरक्षा पक्का करना

इन वेसल में एडवांस्ड सोनार सिस्टम, पानी के अंदर सटीक नेविगेशन, हाई एजिलिटी और मज़बूत एंड्योरेंस शामिल हैं—ये खूबियां कोस्टल इलाकों में टैक्टिकल दबदबे के लिए आइडियल हैं।

एग्जाम के लिए खास बातें:

- इंडियन नेवी के लिए कुल 8 माहे-क्लास ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं।
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने बनाया है।
- यह नई जेनरेशन के ASW कोस्टल डिफेंस फ्लीट का हिस्सा है, जो पुराने अभय-क्लास शिप की जगह लेगा।
- अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में भारत की तैयारी को मज़बूत करता है।
- नेवी के आत्मनिर्भर और नेटवर्क-सेंट्रिक समुद्री फोर्स के विज़न को सपोर्ट करता है।

महत्व

INS माहे के चालू होने से भारत की सब-सरफेस निगरानी बढ़ेगी, जिससे इंडियन ओशन रीजन (IOR) में बढ़ती सबमरीन गतिविधियों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। यह बदलते समुद्री खतरों के समय तटीय सुरक्षा को मज़बूत करता है।

डेविड स्ज़ाले ने नॉवेल 'फ्लेश' के लिए 2025 का बुकर प्राइज़ जीता

हंगेरियन-ब्रिटिश लेखक डेविड स्ज़ाले ने अपने नॉवेल 'फ्लेश' के लिए 2025 का बुकर प्राइज़ जीता है, जिसकी घोषणा लंदन के ओल्ड बिलिंग्सगेट में हुए एक समारोह में की गई।

- बुकर प्राइज़, जिसमें £50,000 का इनाम है, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, जो इंग्लिश में लिखे गए और UK या आयरलैंड में पब्लिश हुए सबसे अच्छे ओरिजिनल नॉवेल के लिए दिया जाता है।
- स्ज़ाले को इससे पहले 2016 में उनके नॉवेल 'ऑल दैट मैन इज़' के लिए बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।
- उनका विजेता नॉवेल, फ्लेश, इमोशनल आइसोलेशन, क्लास डिवाइड और नैतिक पतन के विषयों को एक्सप्लोर करता है, जो हंगरी के एक हाउसिंग एस्टेट से लेकर लंदन के एलीट हवेलियों तक दशकों तक फैला हुआ है।
- फ्लेश स्ज़ाले का छठा फिक्शन है, जो उनके सिग्नेचर स्पेयर और मिनिमलिस्ट प्रोज़ स्टाइल में लिखा गया है।

बुकर प्राइज़ (पहले मैन बुकर प्राइज़):

1969 में शुरू हुआ।

- बुकर प्राइज़ फ़ाउंडेशन (UK) इसे चलाता है।
- UK या आयरलैंड में छपी बेहतरीन इंग्लिश-लैंग्वेज फ़िक्शन को पहचान देता है।
- प्राइज़ मनी: £50,000 (लगभग ₹53 लाख)।

डेविड स्ज़ाले – बैकग्राउंड:

- जन्म: मॉन्ट्रियल, कनाडा।
- राष्ट्रीयता: हंगेरियन-ब्रिटिश।
- दूसरी मशहूर रचनाएँ: स्प्रिंग, द इनोसेंट, और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टर्बुलेंस।
- 2024 बुकर प्राइज़ विनर: पॉल लिंच, प्रोफ़ेट सॉन्ग (आयरलैंड) के लिए।

मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवॉर्ड 2025: डॉ. साई गौतम गोपालकृष्णन को मटीरियल इंजीनियरिंग में बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस (IISc), बेंगलुरु में मटीरियल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. साई गौतम गोपालकृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवॉर्ड के 2025 एडिशन के लिए चुना गया है। इस अवॉर्ड में ₹5 लाख का कैश प्राइज़ दिया जाता है, जो इसे भारत में युवा साइंटिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले नेशनल अवॉर्ड में से एक बनाता है। डॉ. गोपालकृष्णन को अनिल काकोडकर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी द्वारा इंटरव्यू सहित कड़े मूल्यांकन के बाद एक कॉम्पिटिटिव पूल (~50 एप्लिकेंट) में से चुना गया था। उनका रिसर्च ग्रुप कम्प्यूटेशनल मटीरियल साइंस पर फोकस करता है, जिसमें एटॉमिक-लेवल सिमुलेशन और एनर्जी स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस्ड एलॉय का AI-एडेड डिज़ाइन शामिल है। फॉर्मल अवॉर्ड दिसंबर 2025 में होने वाले मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव में दिए जाएंगे।

अतिरिक्त प्रमुख तथ्य::

- मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवॉर्ड गोवा सरकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी में शानदार योगदान देने वाले युवा भारतीय साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए शुरू किया था।
- मटीरियल इंजीनियरिंग और कम्प्यूटेशनल मटीरियल साइंस ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांज़िशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस के लिए ज़रूरी होते जा रहे हैं — जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी और मेक इन इंडिया के तहत भारत के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हैं।
- IISc बेंगलुरु, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, भारत के सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन में से एक है और यह साइंटिफिक टैलेंट तैयार करने में, खासकर STEM फील्ड में, अहम भूमिका निभाता है।
- अवार्ड के इवैल्यूएशन प्रोसेस में रिसर्च के नतीजों का असेसमेंट, काम का समाज पर असर, इनोवेशन की क्षमता और नेशनल साइंस प्रायोरिटी के साथ तालमेल शामिल था।
- युवा साइंटिस्ट अवॉर्ड भारत में टैलेंट को बनाए रखने, आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को सपोर्ट करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत की ग्लोबल पहचान को मज़बूत करने के लिए एक इंसेंटिव के तौर पर काम करते हैं।

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को 2025 के लिए शांति एवं सुरक्षा हेतु विश्व नेता का पुरस्कार मिला

वैश्विक शांति प्रयासों को मान्यता

आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर को बोस्टन ग्लोबल फोरम (बीजीएफ) और एआई वर्ल्ड सोसाइटी (एआईडब्ल्यूएस) द्वारा शांति निर्माण, सुलह और मानवीय सेवा में उनके योगदान के लिए 2025 के लिए शांति एवं सुरक्षा हेतु विश्व नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख योगदानों पर प्रकाश डाला गया

- कोलंबिया, इराक, श्रीलंका, वेनेजुएला और कश्मीर सहित विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष-मध्यस्थता प्रयासों का मार्गदर्शन किया।
- अपने संगठन, द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से संवाद, अंतर-धार्मिक सद्भाव और अहिंसा को बढ़ावा दिया।
- सामाजिक और मानवीय पहलों में आध्यात्मिक प्रथाओं को लागू किया, "तनाव-मुक्त, हिंसा-मुक्त विश्व" के लिए आंतरिक लचीलेपन और नैतिक नेतृत्व पर ज़ोर दिया।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्व

- पुरस्कार का नाम: शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार 2025
- पुरस्कार देने वाली संस्थाएँ: बोस्टन ग्लोबल फ़ोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी
- प्राप्तकर्ता: श्री श्री रविशंकर
- मुख्य क्षेत्र: शांति स्थापना, वैश्विक सुलह, मानवीय सेवा

- वैश्विक प्रभाव: 180 से अधिक देशों और कई संघर्ष क्षेत्रों में सक्रिय
- यह मान्यता शांति कूटनीति में भारत की बढ़ती सॉफ्ट-पावर और वैश्विक मानवीय ढाँचों में आध्यात्मिक नेतृत्व के एकीकरण को रेखांकित करती है।

डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स III ने नाइटहुड की उपाधि दी: अब "सर डेविड बेकहम"

इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स III ने फुटबॉल, ब्रिटिश समाज और चैरिटी के काम में उनकी शानदार सेवाओं के लिए विंडसर कैसल में ऑफिशियली नाइटहुड की उपाधि दी है। 50 साल के इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने इस सम्मान को अपनी ज़िंदगी का "सबसे गर्व का पल" बताया।
इसके साथ ही इंग्लैंड के दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। विंडसर कैसल में एक आधिकारिक समारोह के दौरान राजकुमारी ऐनी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान एंडरसन को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची (अप्रैल 2024) में शामिल किए जाने के बाद दिया गया है, जिसमें उनकी असाधारण खेल उपलब्धियों और इंग्लिश क्रिकेट के प्रति दीर्घकालिक सेवा को मान्यता दी गई है।

अन्य:

बेकहम को पहले फुटबॉल में उनके योगदान के लिए 2003 में ऑर्डर ऑफ़ द ब्रिटिश एम्पायर (OBE) मिला था। "सर" का दर्जा मिलना खेल और समाज के लिए तीन दशकों की सेवा का नतीजा है।

केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2024 घोषित

केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2024 की घोषणा त्रिशूर में राज्य के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर साजी चेरियन ने की। इन अवॉर्ड्स ने साल 2024 के लिए मलयालम सिनेमा में बेहतरीन काम को पहचान दी।

मुख्य विनर्स

- बेस्ट फ़िल्म: मंजुम्मेल बॉयज़ – डायरेक्टर चिदंबरम
- दूसरी बेस्ट फ़िल्म: फेमिनिची फातिमा – डायरेक्टर फाज़िल मुहम्मद
- बेस्ट डायरेक्टर: चिदंबरम (मंजुम्मेल बॉयज़)
- बेस्ट एक्टर: ममूटी (ब्रमायुगम) – कोडुमन पोट्टी का रोल निभाने के लिए
- बेस्ट एक्ट्रेस: शामला हमज़ा (फेमिनिची फातिमा)
- बेस्ट कैरेक्टर रोल (मेल): सौबिन शाहिर (मंजुम्मेल बॉयज़) और सिद्धार्थ भारतन (ब्रमायुगम)
- बेस्ट कैरेक्टर रोल (फीमेल): लिजोमोल जोस (नादन्ना संभवम)
- बेस्ट स्टोरीराइटर: प्रसन्ना विथानगे (पैराडाइज़)
- बेस्ट स्क्रिप्टराइटर (ओरिजिनल): चिदंबरम (मंजुम्मेल बॉयज़)
- बेस्ट स्क्रिप्ट (एडेप्टेशन): लाजो जोस और अमल नीरद (बोगेनविला)
- बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र: सुशीन श्याम (बोगेनविला)
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफर: शैजू खालिद (मंजुम्मेल बॉयज़)

स्पेशल जूरी अवार्ड्स

- बेस्ट फ़िल्म: पैराडाइज़ (प्रसन्ना विथानागे द्वारा डायरेक्टेड)
- बेस्ट एक्टर: टोविनो थॉमस (ARM), आसिफ अली (किष्किंधकंदम)
- बेस्ट एक्ट्रेस: ज्योतिर्मयी (बोगेनविला), दर्शना राजेंद्रन (पैराडाइज़)

लखनऊ को यूनेस्को द्वारा 'रचनात्मक पाककला का शहर' घोषित किया गया - अवधी विरासत को वैश्विक मान्यता

विश्व नगर दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर अपनी जगह बनाई है। इसे उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महाधिवेशन के 43वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा पाककला का रचनात्मक शहर घोषित किया गया। यह मान्यता लखनऊ के सदियों पुराने अवधी व्यंजनों, इसकी गंगा-जमुनी तहजीब (साझा संस्कृति) और शहर की निरंतर पाककला परंपराओं का सम्मान करती है जो शाही रसोई और स्ट्रीट फूड संस्कृति को जोड़ती हैं।

यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क (यूसीसीएन) के बारे में

- स्थापना: 2004
- उद्देश्य: सतत शहरी विकास के रणनीतिक चालकों के रूप में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना।
- श्रेणियाँ: शिल्प और लोक कला, डिज़ाइन, फिल्म, पाककला, साहित्य, मीडिया कला और संगीत।
- रचनात्मक शहरों की संख्या (2025): दुनिया भर में 350+ शहर।
- यूसीसीएन में शामिल अन्य भारतीय शहर: हैदराबाद (पाक कला), वाराणसी (संगीत), जयपुर (शिल्प और लोक कला), चेन्नई (संगीत), मुंबई (फ़िल्म), श्रीनगर (शिल्प और लोक कला), और ग्वालियर (संगीत)।
- इस उपलब्धि के साथ, लखनऊ, हैदराबाद (2019) के बाद पाक कला के रचनात्मक शहर का दर्जा पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है।

पुरातत्वविद् प्रो. रवींद्र कोरीसेट्टार को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया

कर्नाटक के धारवाड़ के प्रसिद्ध पुरातत्वविद् प्रो. रवींद्र (रवि) कोरीसेट्टार को राज्य के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पुरातत्व, प्रागैतिहासिक अनुसंधान और शैक्षणिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।

शेफ संजीव कपूर को वर्ल्ड फ़ूड प्राइज़ फ़ाउंडेशन द्वारा "शीर्ष कृषि-खाद्य अग्रणी" के रूप में सम्मानित किया गया

प्रसिद्ध भारतीय शेफ, लेखक और पद्म श्री पुरस्कार विजेता संजीव कपूर को वर्ल्ड फ़ूड प्राइज़ फ़ाउंडेशन द्वारा डेस मोइनेस, आयोवा (अमेरिका) में बोरलॉग डायलॉग वीक 2025 के दौरान आयोजित एक समारोह में "शीर्ष कृषि-खाद्य अग्रणी" के रूप में सम्मानित किया गया। बोरलॉग डायलॉग वीक 2025 एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत पोषण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ एकत्रित होते हैं।

विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के बारे में:

- स्थापना: 1986 में "हरित क्रांति के जनक" नॉर्मन बोरलॉग द्वारा।
- मुख्यालय: डेस मोइनेस, आयोवा, अमेरिका।
- उद्देश्य: दुनिया भर में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार लाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करना।
- बोरलॉग संवाद सप्ताह फाउंडेशन का प्रमुख कार्यक्रम है, जो नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाता है।

अतिरिक्त:

संजीव कपूर को पाक कला में उनके योगदान के लिए 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वह फ़ूड फ़ूड चैनल पर शो होस्ट करने वाले पहले भारतीय शेफ थे और उन्होंने 200 से अधिक कुकबुक प्रकाशित की हैं। भारत शीर्ष 10 वैश्विक कृषि निर्यातकों में शामिल है, जो कुल वैश्विक कृषि उत्पादन में 11% से अधिक का योगदान देता है (एफएओ डेटा)। विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 वैश्विक खाद्य सुरक्षा (अमेरिका) के विशेष दूत डॉ. कैरी फाउलर को प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा

भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा की है।

पुरस्कार श्रेणियाँ और विजेता

- विज्ञान रत्न पुरस्कार: यह पुरस्कार प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर को मरणोपरांत प्रदान किया गया। वे एक प्रतिष्ठित खगोल भौतिक विज्ञानी थे और ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए जाने जाते थे।
- विज्ञान श्री पुरस्कार: विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 8 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों का चयन किया गया है।
- विज्ञान युवा - शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार: विभिन्न विषयों में उनके नवोन्मेषी अनुसंधान के लिए 14 युवा वैज्ञानिकों का चयन किया गया।
- विज्ञान टीम पुरस्कार: कृषि विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य, विशेष रूप से सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए टीम अरोमा मिशन (सीएसआईआर) को प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में

इन पुरस्कारों का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करना है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने और व्यक्तिगत एवं सहयोगात्मक वैज्ञानिक योगदान को मान्यता देने के लिए बनाए गए हैं।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर: सर फ्रेड हॉयल के साथ अपने सहयोग और ब्रह्मांड विज्ञान में योगदान के लिए जाने जाते हैं।
- सीएसआईआर अरोमा मिशन: "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत लैवेंडर और रोज़मेरी जैसी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया।
- ये पुरस्कार वैज्ञानिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
- 2024 में पहली बार शुरू किए गए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ने एक एकीकृत राष्ट्रीय सम्मान प्रणाली बनाने के लिए कई पूर्व राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का स्थान लिया है।

मिस यूनिवर्स 2025: मेक्सिको की फातिमा बॉश बनीं विनर, भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में

फातिमा बॉश (मेक्सिको) को ऑफिशियली मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया है। वह 25 साल की हैं, फैंस की पसंदीदा हैं, और उन्होंने पूरे पेजेंट में शानदार परफॉर्मेंस दी। फातिमा को डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थीलविग, मिस यूनिवर्स 2024 ने ताज पहनाया।

रनर-अप (ऑफिशियल रैंकिंग):

1st रनर-अप: प्रवीणर सिंह (थाईलैंड)
2nd रनर-अप: स्टेफनी अबासली (वेनेजुएला)
3rd रनर-अप: अहतिसा मनालो (फिलीपींस)
4th रनर-अप: ओलिविया यासे (आइवरी कोस्ट)

फिनाले सवाल और फातिमा का विनिंग जवाब:

कंटेस्टेंट से पूछा गया:
UN में वे किन ग्लोबल मुद्दों पर बात करेंगी
युवा लड़कियों को एम्पावर करने के लिए वे मिस यूनिवर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगी

फातिमा बॉश का विनिंग जवाब:
"अपनी असलियत की ताकत पर विश्वास करें। आपके सपने मायने रखते हैं, आपका दिल मायने रखता है। कभी किसी को अपनी काबिलियत पर शक करने न दें।" उनका जवाब पेजेंट की थीम: "प्यार की ताकत" से मेल खाता था, जो एकता और एम्पावरमेंट पर फोकस थी।

फातिमा बॉश से जुड़ा विवाद:
थाई पेजेंट डायरेक्टर नवात इत्सराग्रिसिल से डांट खाने के बाद फातिमा ने पहले वॉकआउट कर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने प्रमोशनल पोस्ट मिस करने पर एक लाइवस्ट्रीम के दौरान उन्हें "बेवकूफ" कहा था। नवात ने इस शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार किया लेकिन सिक्योरिटी को बुलाने की बात मानी।

मिस यूनिवर्स 2025 में भारत:
मनिका विश्वकर्मा ने भारत को रिप्रेजेंट किया। वह टॉप 15 में पहुंचीं, लेकिन स्विमसूट राउंड के बाद टॉप 12 के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाईं। भारत ने पिछली बार 2021 (हरनाज़ संधू) में मिस यूनिवर्स जीता था, इससे पहले 1994 (सुष्मिता सेन) और 2000 (लारा दत्ता) में।

लियोनार्डो डिकैप्रियो को पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में डेज़र्ट पाम अचीवमेंट अवॉर्ड मिलेगा

लियोनार्डो डिकैप्रियो को पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में डेज़र्ट पाम अचीवमेंट अवॉर्ड मिलेगा। यह सम्मान पॉल थॉमस एंडरसन की ड्रामा 'वन बैटल आफ्टर अनदर' में उनके परफॉर्मेंस के लिए है।

फिल्म के बारे में – वन बैटल आफ्टर अनदर
यह फिल्म थॉमस पिंचन के 1990 के नॉवेल 'वाइनलैंड' से काफी हद तक प्रेरित है। कहानी एक पुराने क्रांतिकारी (डिकैप्रियो) के बारे में है जो अपनी लापता बेटी को बचाने के लिए अपने साथियों से मिलता है। फिल्म में उनकी बेटी का रोल चेस इनफिनिटी ने किया है। सपोर्टिंग कास्ट में शॉन पेन, रेजिना हॉल, बेनिसियो डेल टोरो, तेयाना टेलर, अलाना हैम, शायना मैकहेल और वुड हैरिस शामिल हैं। पॉल थॉमस एंडरसन ने फिल्म को डायरेक्ट, लिखा और प्रोड्यूस किया। सितंबर 2025 के आखिर में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने क्रिटिक्स और कमर्शियल सक्सेस हासिल की, और दुनिया भर में $200 मिलियन से ज़्यादा कमाए।

डिकैप्रियो के करियर की खास बातें:
डिकैप्रियो ने 1990 के दशक की शुरुआत में दिस बॉयज़ लाइफ़ और व्हाट्स ईटिंग गिल्बर्ट ग्रेप से अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक (1997) के बाद वे ग्लोबल स्टार बन गए। मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ उनके कोलेबोरेशन ने हॉलीवुड आइकन के तौर पर उनकी पहचान को मज़बूत किया।
स्कॉर्सेसी की बड़ी फ़िल्मों में एविएटर, द डिपार्टेड, शटर आइलैंड, गैंग्स ऑफ़ न्यूयॉर्क, द वुल्फ़ ऑफ़ वॉल स्ट्रीट, और किलर्स ऑफ़ द फ़्लावर मून शामिल हैं। दूसरी बड़ी हिट फ़िल्मों में इनसेप्शन, जैंगो अनचेन्ड, द ग्रेट गैट्सबी, वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड शामिल हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में हीट 2 (माइकल मान) और स्कॉर्सेसी द्वारा डायरेक्टेड जेनिफर लॉरेंस के साथ व्हाट हैपन्स एट नाइट शामिल हैं।

रबीह अलमेडीन और पैट्रिशिया स्मिथ को नेशनल बुक अवार्ड्स 2025 में ताज पहनाया गया

76वां नेशनल बुक अवार्ड्स समारोह सिप्रियानी वॉल स्ट्रीट, मैनहट्टन में हुआ। लेबनानी नॉवेलिस्ट रबीह अलमेडीन ने 'द ट्रू ट्रू स्टोरी ऑफ़ राजा द गुलिबल (एंड हिज़ मदर)' के लिए फिक्शन प्राइज़ जीता। शिकागो में जन्मी पोएट पैट्रिशिया स्मिथ ने 'द इंटेंशन्स ऑफ़ थंडर' के लिए पोएट्री प्राइज़ जीता। नॉनफिक्शन प्राइज़ कनाडाई-ईरानी राइटर उमर एल अक्कड़ को 'वन डे, एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस' के लिए मिला। ईरानी अमेरिकन डेनियल नायेरी ने 'द टीचर ऑफ़ नोमैड लैंड: ए वर्ल्ड वॉर II स्टोरी' के लिए यंग पीपल्स लिटरेचर अवार्ड जीता। अर्जेंटीना की राइटर गैब्रिएला कैबेज़ोन कैमारा ने 'वी आर ग्रीन एंड ट्रेम्बलिंग' के लिए ट्रांसलेटेड लिटरेचर प्राइज़ जीता, जिसका ट्रांसलेशन रॉबिन मायर्स ने किया था। हर विनर को $10,000 का कैश प्राइज़ मिला।

रात की थीम और मैसेज
- लेखकों ने ग्लोबल संकटों के लिए आभार, चिंता और राजनीतिक/सामाजिक मुद्दों की आलोचना ज़ाहिर की।
- बताए गए टॉपिक में U.S. में इमिग्रेशन रेड और मिडिल ईस्ट में हिंसा शामिल थे।
- एल अक्कड़ ने कहा कि उनकी किताब गाज़ा में हुए नरसंहार के जवाब में लिखी गई थी, जिससे जश्न मनाना मुश्किल हो गया।

अवॉर्ड प्रोसेस:
अवॉर्ड नेशनल बुक फ़ाउंडेशन द्वारा मैनेज किए जाते हैं। विनर्स को राइटर्स, क्रिटिक्स और बुकसेलर्स के पैनल चुनते हैं। पब्लिशर्स द्वारा सबमिट की गई सैकड़ों किताबों को फ़ाइनल सिलेक्शन से पहले रिव्यू किया जाता है।

भारत और क्यूबा ने लीगल कोऑपरेशन और कल्चरल एक्सचेंज पर एक अहम समझौते पर साइन किए

दोतरफा रिश्तों को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भारत और क्यूबा ने हवाना में एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए, जिसमें क्रिमिनल मामलों में आपसी लीगल असिस्टेंस पर एक ट्रीटी और कल्चरल एक्सचेंज और कोऑपरेशन (2025–2030) पर एक प्रोटोकॉल शामिल है। यह एग्रीमेंट भारत की विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और क्यूबा के एक्टिंग विदेश मंत्री गेरार्डो पेनाल्वर पोर्टल के बीच एक मीटिंग के दौरान साइन किया गया। क्यूबा ने हेल्थ, एजुकेशन, साइंस और कल्चर में भारत के साथ पॉलिटिकल बातचीत को गहरा करने और कोऑपरेशन बढ़ाने के अपने कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया।

अतिरिक्त प्रमुख तथ्य:

- डिप्लोमैटिक रिश्ते: भारत ने क्यूबा की क्रांति के तुरंत बाद क्यूबा को मान्यता दी; 12 जनवरी 1960 को फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिश्ते बने।
- म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस (MLAT): ये ट्रीटी बॉर्डर पार क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए सबूत, डॉक्यूमेंट और गवाहों के बयानों के एक्सचेंज की इजाज़त देती हैं। भारत का MLAT नेटवर्क: भारत ने बॉर्डर पार कानूनी सहयोग को मज़बूत करने के लिए 40 से ज़्यादा देशों के साथ MLAT पर साइन किए हैं।
- कल्चरल एक्सचेंज प्रोटोकॉल (2025–30): यह आर्ट्स, कल्चर, स्कॉलरशिप और लोगों के बीच लेन-देन में सहयोग पर फोकस करता है।
- इंसानी सहयोग: भारत ने पहले भी तूफ़ान के बाद क्यूबा को मदद दी है, जिसमें राहत का सामान और मोबाइल फ़ील्ड हॉस्पिटल शामिल हैं।
- एजुकेशन और टेक्नोलॉजी लिंक: भारत और क्यूबा ने पहले भी बायोटेक्नोलॉजी, पारंपरिक दवा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग किया है।

लघु लेख

वंदे मातरम के 150 साल: भारत ने साल भर चलने वाला जश्न शुरू किया

प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का उद्घाटन किया। माना जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का बनाया यह गीत अक्षय नवमी, 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था, और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक शक्तिशाली सांस्कृतिक ताकत के रूप में उभरा।

ऐतिहासिक विकास और राष्ट्रीय पहचान

मूल रूप से 1875 में साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित, वंदे मातरम को बाद में बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया था। इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीत दिया था, जिन्होंने इसकी भावनात्मक और देशभक्ति वाली अपील को और बढ़ाया। पहले दो छंदों को 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऑफिशियली भारत के नेशनल सॉन्ग के तौर पर अपनाया।

24 जनवरी 1950 को, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया कि हालांकि जन गण मन भारत का नेशनल एंथम होगा, लेकिन वंदे मातरम को आज़ादी की लड़ाई में अपनी बेमिसाल भूमिका की वजह से बराबर सम्मान दिया जाएगा। हालांकि भारत के संविधान में साफ तौर पर किसी नेशनल सॉन्ग का ज़िक्र नहीं है, आर्टिकल 51A(a) नेशनल सिंबल का सम्मान करना एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाता है।

नेशनल रेजिस्टेंस के सिंबल के तौर पर वंदे मातरम

कॉलोनियल राज के दौरान, वंदे मातरम देश भर में आज़ादी के लिए लड़ने वालों को प्रेरित करने वाला, देश को जगाने और कुर्बानी का एक साथ लाने वाला नारा बन गया। इसकी ताकत को पहचानते हुए, अंग्रेजों ने अक्सर इसे पब्लिक में गाने पर रोक लगा दी या बैन लगा दिया।

इस गाने को पॉलिटिकल पहचान तब मिली जब रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया। यह जल्द ही बड़ी पॉलिटिकल सभाओं में रेगुलर तौर पर गाया जाने लगा और आज़ाद हिंद की प्रोविजनल सरकार की घोषणा के दौरान इसे गाया गया। वाराणसी कांग्रेस सेशन (1905) में, इसे पूरे भारत में होने वाले मौकों के लिए ऑफिशियली मंज़ूरी दी गई।

मास मूवमेंट और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में भूमिका

बंगाल बंटवारे के आंदोलन (1905) में वंदे मातरम का पहली बार बड़े पैमाने पर नारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ, जिसमें कलकत्ता टाउन हॉल में लगभग 40,000 लोगों की एक बड़ी सभा शामिल थी। इसके बढ़ते असर के कारण लॉर्ड कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे पब्लिक में गाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया।

इस गाने ने एक्टिविज़्म के नए तरीकों को प्रेरित किया, जिसमें वंदे मातरम संप्रदाय भी शामिल है, जिसे 1905 में उत्तरी कलकत्ता में प्रभात फेरी और कम्युनिटी डोनेशन के ज़रिए देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अंग्रेजी डेली "वंदे मातरम" 1906 में बिपिन चंद्र पाल के अंडर शुरू किया गया था, बाद में श्री अरबिंदो भी इसमें शामिल हो गए। यह आत्मनिर्भरता और एंटी-कॉलोनियल संघर्ष के लिए एक लीडिंग आवाज़ बन गया। अरबिंदो इस गाने को स्पिरिचुअली पावरफुल मानते थे, जो एक कलेक्टिव पॉलिटिकल चेतना जगाता था।

बॉर्डर के बाहर असर और स्टूडेंट मूवमेंट

यह गाना ग्लोबल फ्रीडम एक्टिविज़्म का हिस्सा बन गया। 1907 में, मैडम भीकाजी कामा ने स्टटगार्ट में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला वर्शन फहराया, जिस पर वंदे मातरम लिखा था। मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों ने अपने आखिरी शब्द "वंदे मातरम" कहे। विदेशों में भी पब्लिकेशन ने इस गाने का मैसेज छापा, जिसमें 1909 में जिनेवा की एक मैगज़ीन भी शामिल थी।

भारत में, हैदराबाद-कर्नाटक इलाके में गुलबर्गा (1938) के मशहूर वंदे मातरम आंदोलन को स्टूडेंट्स ने लीड किया, जिसमें ब्रिटिश पाबंदियों को तोड़ा गया और उन्हें गिरफ्तारियां और देश निकाला झेलना पड़ा—जो इस गाने के लगातार क्रांतिकारी असर को दिखाता है।

बंकिम चंद्र चटर्जी: गाने के पीछे की दूर की सोचने वाली हस्ती

बंकिम चंद्र चटर्जी (1838–1894) बंगाली साहित्य और शुरुआती राष्ट्रवाद में एक आगे रहने वाले व्यक्ति थे। आनंदमठ, कपालकुंडला, दुर्गेशनंदिनी और देवी चौधुरानी जैसे अपने नॉवेल के ज़रिए उन्होंने कल्चरल गर्व, देशभक्ति की ताकत और गुलाम भारत के सामाजिक-राजनीतिक हालात को दिखाया। वंदे मातरम उनका सबसे यादगार योगदान है, जो मातृभूमि के प्रति हमेशा सम्मान की निशानी है।

खेल-कूद

कुराकाओ FIFA वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है

कुराकाओ आबादी के हिसाब से FIFA वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है।

- उन्होंने यह कैसे किया: उन्होंने जमैका के ख़िलाफ़ 0-0 के ड्रॉ के साथ क्वालिफ़िकेशन हासिल किया, और CONCACAF ग्रुप B में 12 पॉइंट्स के साथ बिना हारे टॉप पर रहे।
- रिकॉर्ड तोड़ने वाली मौजूदगी: सिर्फ़ 156,115 की आबादी के साथ, कुराकाओ ने आइसलैंड (जिसकी आबादी ~350,000 थी) को पीछे छोड़कर वर्ल्ड कप तक पहुँचने वाला सबसे छोटा देश बन गया।
- यह क्यों ज़रूरी है: उनका क्वालिफ़िकेशन छोटे देशों में फ़ुटबॉल की ग्रोथ और 2026 में 48-टीम के वर्ल्ड कप फ़ॉर्मेट के असर को दिखाता है।

FIFA वर्ल्ड कप सिलेक्शन प्रोसेस

- हर कॉन्टिनेंट को FIFA से वर्ल्ड कप स्लॉट की एक तय संख्या मिलती है।
- टीमें अपने कॉन्टिनेंट में क्वालिफ़ायर खेलती हैं (ग्रुप मैच + प्लेऑफ़)।
- टॉप टीमें सीधे क्वालिफ़ाई करती हैं; कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ़ में जाती हैं।
- मेज़बान देश अपने आप क्वालिफ़ाई कर लेता है। कुल 48 टीमें वर्ल्ड कप में पहुँचती हैं (2026 से आगे)।

कुराकाओ

- राजधानी: विलेमस्टेड
- करेंसी: कैरेबियन गिल्डर
- राजा: विलेम-अलेक्जेंडर
- गवर्नर: ल्यूसिल जॉर्ज-वाउट
- स्पीकर: फर्गिनो "गीनो" ब्राउनबिल
- प्रधानमंत्री: गिलमार पिसास
- ऑफिशियल भाषाएँ: पापियामेंटो, डच, इंग्लिश
- महाद्वीप: साउथ अमेरिका

सिनर ने ट्यूरिन में अल्काराज़ को हराकर एटीपी फ़ाइनल ख़िताब जीता

जैनिक सिनर ने ट्यूरिन में अपने निट्टो एटीपी फ़ाइनल ख़िताब का सफलतापूर्वक बचाव किया।

मुख्य तथ्य:

जैनिक सिनर ने ट्यूरिन में कार्लोस अल्काराज़ को हराकर अपने एटीपी फ़ाइनल ख़िताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। सिनर ने अपने इनडोर हार्ड-कोर्ट जीत के सिलसिले को 31 मैचों तक बढ़ाया। यह उनका सीज़न का छठा फ़ाइनल था, और सिनर ने इस दौरान अल्काराज़ पर अपनी केवल दूसरी जीत हासिल की।

ऐतिहासिक और सांख्यिकीय तथ्य:

- सिनर ने अब एक भी सेट गंवाए बिना लगातार दो एटीपी फ़ाइनल ख़िताब जीते हैं।
- 24 साल की उम्र में, वह रोजर फेडरर (2004) के बाद लगातार एटीपी फ़ाइनल ख़िताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं।
- सिनर ने इस सीज़न में ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीता है।
- अलकाराज़ ने इस साल रोलैंड गैरोस और यूएस ओपन जीता है, जिससे दोनों ही कोर्ट पर संतुलित प्रतिद्वंद्विता का संकेत मिलता है।

एटीपी फ़ाइनल

- स्थापना: 1970
- स्थान: ट्यूरिन, इटली (2021–2028)
- श्रेणी: वर्षांत चैंपियनशिप
- पुरस्कार राशि: US$15,250,000
- वर्तमान चैंपियन (2025)
- एकल: इटली जैनिक सिनर
- युगल: हैरी हेलियोवारा (फ़िनलैंड) और हेनरी पैटन (यूनाइटेड किंगडम)

धनुष श्रीकांत ने 2025 डेफलंपिक्स में गोल्ड जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

टोक्यो, जापान में हुए 2025 डेफलंपिक्स में भारत ने शानदार शुरुआत की, शूटर धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10m एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 252.2 पॉइंट्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाया, और अपने पिछले डेफलंपिक्स टाइटल को सफलतापूर्वक बचाया। भारत ने इसी इवेंट में मोहम्मद वानिया के ज़रिए सिल्वर भी जीता, जिन्होंने 250.1 पॉइंट्स स्कोर किए, जिससे राइफल शूटिंग में भारत का दबदबा पक्का हो गया।

महिला टीम ने मेडल जीतना जारी रखा

महिलाओं की 10m एयर राइफल इवेंट में:

- माहित संधू – सिल्वर मेडल
- कोमल वाघमारे – ब्रॉन्ज़ मेडल
- इससे कॉम्पिटिशन के एक ही दिन में भारत के लिए दो डबल-पोडियम फिनिश हुए।

कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और ज़रूरी बातें

डेफलंपिक्स, ओलंपिक और पैरालंपिक्स की तरह, हर चार साल में होने वाले डेफलंपिक्स के लिए IOC से मान्यता प्राप्त मल्टी-स्पोर्ट इवेंट है।

हाल के एडिशन में कई मेडल जीतने के साथ, डेफलंपिक्स में शूटिंग भारत के सबसे मज़बूत स्पोर्ट्स में से एक है। धनुष श्रीकांत

ने ब्राज़ील में 2022 डेफलंपिक्स में भी गोल्ड जीता। भारत ISSF, एशियन गेम्स और डेफलंपिक्स इवेंट्स में राइफल शूटिंग में एक टॉप-रैंकिंग देश के तौर पर उभर रहा है। टोक्यो ने पहले 1964 और 2020 समर ओलंपिक्स होस्ट किए थे और यह एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बना हुआ है।

कुशल दलाल ने लक्ज़मबर्ग में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज़ का टाइटल जीता

भारत के कुशल दलाल ने लक्ज़मबर्ग के स्ट्रैसन में हुए GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज़ 2025 का मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने एक रेयर डबल शूट-ऑफ में पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 स्टीफन हैनसेन (USA) को हराकर गोल्ड मेडल जीता, जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दिखाया। अंडर-21 मेन्स कंपाउंड इवेंट में, भारत के गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जिससे इंटरनेशनल इनडोर कॉम्पिटिशन में कंपाउंड आर्चरी में भारत की बढ़ती सफलता में मदद मिली।

मुख्य तथ्य:

- इंडोर आर्चरी वर्ल्ड सीरीज़ हर साल वर्ल्ड आर्चरी द्वारा आयोजित की जाती है। कंपाउंड आर्चरी को अभी तक ओलंपिक गेम्स में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में यह खास तौर पर शामिल है।
- ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा जैसे टॉप एथलीट के साथ, भारत को दुनिया भर में कंपाउंड आर्चरी में टॉप परफॉर्म करने वाला देश माना जाता है।
- यूरोपियन सर्किट डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लक्ज़मबर्ग इंटरनेशनल इनडोर आर्चरी इवेंट्स होस्ट कर रहा है।

वर्ल्ड आर्चरी:

- बनाना: 4 सितंबर 1931
- स्थापित: ल्वो, पोलैंड (आज ल्वीव, यूक्रेन)
- हेडक्वार्टर: लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड
- प्रेसिडेंट: ग्रेग ईस्टन

24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते

24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया, जिसमें एशिया भर के शीर्ष तीरंदाजों ने भाग लिया। इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप में रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाजी श्रेणियों में कई स्पर्धाएँ शामिल हैं, जो एथलीटों को रैंकिंग हासिल करने और प्रमुख वैश्विक प्रतियोगिताओं की तैयारी करने का अवसर प्रदान करती हैं। यह टूर्नामेंट एशियाई तीरंदाजी प्रदर्शन मानकों के मूल्यांकन और क्षेत्रीय खेल सहयोग को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, टूर्नामेंट का 24वाँ संस्करण था, जो 8 से 14 नवंबर 2025 तक ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। भारत इस टूर्नामेंट में सबसे सफल राष्ट्र रहा।

पदक तालिका

रैंक	राष्ट्र	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	भारत	6	3	1	10
2	दक्षिण कोरिया	2	4	4	10
3	चीनी ताइपे	1	1	0	2
4	कज़ाकिस्तान	1	0	0	1
5	बांग्लादेश	0	1	1	2
5	उज़्बेकिस्तान	0	1	1	2

एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के बारे में

- शुरुआत: 1980
- आवृत्ति: द्विवार्षिक (प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित)
- शासी निकाय: विश्व तीरंदाजी एशिया (WAA)
- 2025 मेजबान शहर: ढाका, बांग्लादेश
- देश: 29

ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, काहिरा — भारत ने 9 मेडल जीते

सम्राट राणा ने पुरुषों के 10m एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, और इंडिविजुअल एयर पिस्टल वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। राणा ने 243.7 पॉइंट्स बनाए, और चीन के हू काई को 0.4 पॉइंट्स से हराया। वरुण तोमर ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जिससे भारत ने दो बार पोडियम पर जगह बनाई। सम्राट राणा, वरुण तोमर और शरवन कुमार की भारतीय टीम ने पुरुषों के 10m एयर पिस्टल टीम इवेंट में भी गोल्ड जीता।

इसके साथ, काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत के मेडल की संख्या 9 मेडल हो गई — 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज़, जिससे भारत चीन (12 मेडल) के बाद दूसरे स्थान पर आ गया। मनु भाकर, ईशा सिंह और सुरुचि सिंह वाली महिलाओं की 10m एयर पिस्टल टीम ने सिल्वर मेडल जीता, हालांकि मनु भाकर इंडिविजुअल मेडल से चूक गईं। 22 साल की उम्र में, सम्राट राणा ओलंपिक शूटिंग इवेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाले सिर्फ़ पांचवें भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले अभिनव बिंद्रा, रुद्रांक पाटिल, तेजस्विनी सावंत और मिक्स्ड टीम जोड़ी शिवा नरवाल-ईशा सिंह यह खिताब जीत चुके हैं।

ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025:

- शुरूआत: 17 जुलाई 1907
- हेडक्वार्टर: म्यूनिख, जर्मनी
- प्रेसिडेंट: लुसियानो रॉसी

केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान किया

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के कप्तान केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जिससे सबसे छोटे फॉर्मेट में एक शानदार चैप्टर खत्म हो गया है। 34 साल के इस क्रिकेटर ने 93 T20 इंटरनेशनल मैचों में न्यूज़ीलैंड को रिप्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने सभी बड़े टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2,500 से ज़्यादा रन बनाए। विलियमसन, जिन्होंने 2011 में अपना T20I डेब्यू किया था, ने 75 मैचों में ब्लैक कैप्स की कप्तानी की, टीम को दो T20 वर्ल्ड कप सेमी-फ़ाइनल (2016, 2022) और एक फ़ाइनल (2021) तक पहुँचाया, जहाँ न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया से रनर-अप रहा। T20I से रिटायरमेंट के बावजूद, वह टेस्ट और ODI में न्यूज़ीलैंड को रिप्रेजेंट करते रहेंगे।

अवनि लेखरा ने दुबई में 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता

भारतीय पैरा शूटर अवनि लेखरा ने दुबई के अल ऐन में हुए 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10m एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। लेखरा ने स्वीडन की एना बेसनॉन को हराकर टॉप पोडियम हासिल किया, जबकि थाईलैंड की वान्रिपा लेउंगविलाई ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। इसके अलावा, मिक्स्ड 50m पिस्टल SH1 कैटेगरी में भारत ने अपना दबदबा दिखाया — आकाश ने 223.1 पॉइंट बनाकर गोल्ड मेडल जीता, और संदीप कुमार ने सिल्वर मेडल जीता। रुद्रांश खंडेलवाल के साथ, भारतीय तिकड़ी ने टीम सिल्वर मेडल भी जीता, जो ईरान से ठीक पीछे रहा।

अवनि लेखरा के बारे में:

- जन्म: 1999, जयपुर, राजस्थान।
- दो पैरालंपिक मेडल (टोक्यो 2020) जीतने वाली पहली भारतीय महिला — 10m एयर राइफल SH1 में गोल्ड और 50m राइफल 3 पोजीशन SH1 में ब्रॉन्ज़।
- पद्म श्री (2022) और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड (2021) की प्राप्तकर्ता।
- वर्ल्ड रिकॉर्ड: महिलाओं की 10m एयर राइफल SH1 में 250.6 का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर रखती हैं।

पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में:

इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी (IPC) द्वारा आयोजित।
मुख्य उद्देश्य: पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता।
इवेंट्स: इसमें एयर राइफल, एयर पिस्टल और मिक्स्ड टीम कैटेगरी शामिल हैं।

भारत ने 2025 में पहली बार ICC महिला ODI विश्व कप का खिताब जीता

एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला ICC महिला ODI विश्व कप जीत लिया। यह जीत भारतीय खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है, जो महिला क्रिकेट के बढ़ते वैश्विक कद का प्रतीक है। पहले गेंदबाजी करते हुए, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 298/7 पर रोक दिया, लेकिन शेफाली वर्मा (87 रन) और हरमनप्रीत कौर (65 रन) ने एक प्रतिस्पर्धी स्कोर सुनिश्चित किया। दीप्ति शर्मा की ऑलराउंड प्रतिभा (9.3 ओवर में 5/39 और बल्ले से 37 रन) ने मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी 209/5 से 246 पर ऑल आउट हो गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि दीप्ति शर्मा ने पूरी श्रृंखला में अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। भारतीय टीम को पुरस्कार राशि के रूप में ₹37.3 करोड़ मिले - पिछले संस्करण की तुलना में 239% की रिकॉर्ड वृद्धि - जो क्रिकेट पुरस्कारों में लैंगिक समानता के प्रति ICC की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- ICC महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत ने की - 2013 के बाद पहली बार।
- फाइनल का स्थान: डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई।
- भारतीय टीम की कप्तान: हरमनप्रीत कौर।
- भारतीय महिला टीम (2025) के कोच: अमोल मजूमदार।
- सर्वाधिक रन (टूर्नामेंट): स्मृति मंधाना (भारत)।
- सर्वाधिक विकेट (टूर्नामेंट): दीप्ति शर्मा (भारत)।
- भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज़ के बाद ICC महिला विश्व कप जीतने वाला पाँचवाँ देश बन गया।
- पहला महिला विश्व कप 1973 में आयोजित किया गया था - पुरुष संस्करण से दो साल पहले।
- महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2023 में शुरू होगी, जिससे भारतीय महिला क्रिकेटरों को व्यापक अवसर मिलेंगे।

पंजाब के नमितबीर सिंह वालिया ने शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीता

पंजाब के जालंधर के युवा शतरंज खिलाड़ी नमितबीर सिंह वालिया ने फ्रांस में आयोजित तीसरे एनेमासे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल कर आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर (आईएम) का खिताब हासिल किया है।

शतरंज खिताबों के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय मास्टर (IM) खिताब FIDE (फेडरेशन इंटरनेशनेल डेस एचेक्स) द्वारा प्रदान किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित वैश्विक शतरंज शासी निकाय है।
- IM के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तीन IM मानदंड प्राप्त करने होंगे और न्यूनतम 2400 की FIDE रेटिंग प्राप्त करनी होगी।

- पदक्रमानुसार, ये खिताब इस प्रकार हैं: ग्रैंडमास्टर (GM) → अंतर्राष्ट्रीय मास्टर (IM) → FIDE मास्टर (FM) → कैंडिडेट मास्टर (CM)।

भारत की शतरंज उपलब्धियाँ:

- भारत के पहले ग्रैंडमास्टर: विश्वनाथन आनंद (1988)।
- भारत की पहली महिला ग्रैंडमास्टर (WGM): सुब्बारामन विजयलक्ष्मी (2001)।
- 2025 तक, भारत में 87 ग्रैंडमास्टर और 130 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स हैं, जो इसे दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ते शतरंज देशों में से एक बनाता है।
- 1951 में स्थापित अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) देश में इस खेल का संचालन करता है।

स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज़ बनीं

भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना 828 रेटिंग अंकों के साथ आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुँच गई हैं, जिससे वह दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली बल्लेबाज़ बन गई हैं। अब वह ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर से लगभग 100 अंक आगे हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं। मंधाना की यह सफलता भारत में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद आई है, जहाँ उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैच विजयी शतक (109) और बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 34 रन बनाए थे। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए, उन्हें आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ (सितंबर 2025) भी चुना गया। उनकी सलामी जोड़ीदार प्रतीक रावल 564 अंकों के साथ 27वें स्थान पर पहुँच गईं, लेकिन चोट के कारण उन्हें बाकी टूर्नामेंट से हटना पड़ा।

रैंकिंग में अन्य शीर्ष खिलाड़ी (अक्टूबर 2025 तक):

बल्लेबाज:

1. स्मृति मंधाना (भारत) – 828 अंक
2. एश्ले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया) – 729 अंक
3. नताली साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड) – 710 अंक

गेंदबाज:

1. सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) – 747 अंक
2. अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया) – 729 अंक
3. एश्ले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया) – 718 अंक

ICC रैंकिंग प्रणाली के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा प्रबंधित।
- खिलाड़ी प्रदर्शन, विरोधी टीम की ताकत और मैच के महत्व के आधार पर अंक अर्जित करते हैं।
- रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद साप्ताहिक रूप से अपडेट की जाती है।
- टेस्ट, वनडे और टी20I में बल्लेबाजों, गेंदबाजों और ऑलराउंडरों के लिए अलग-अलग रैंकिंग।

ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के बारे में:

- मेजबान देश: भारत
- प्रारूप: 50 ओवर के मैच
- भाग लेने वाली टीमें: 8

कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप-कप्तान स्मृति मंधाना के नेतृत्व में भारत का प्रदर्शन। इस टूर्नामेंट ने महिला क्रिकेट में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया।

भारतीय शतरंज सितारे डी. गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 में दोहरा स्वर्ण पदक जीता

भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी. गुकेश और दिव्या देशमुख ने ग्रीस के रोड्स में आयोजित यूरोपीय क्लब कप 2025 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की और गोवा में होने वाले आगामी शतरंज विश्व कप 2025 से पहले देश के लिए दोहरा स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। ओपन वर्ग में, ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश ने शीर्ष बोर्ड पर स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी टीम सुपरचेस ने टीम स्वर्ण पदक जीता। यह जीत गुकेश के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है, जिन्होंने वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन होने के बावजूद एक चुनौतीपूर्ण वर्ष का सामना किया है। महिला वर्ग में, दिव्या देशमुख ने दूसरे बोर्ड पर स्वर्ण पदक जीता और उनकी टीम सर्कल डी'एचेक्स डी मोंटे कार्लो चैंपियन बनी। गौरतलब है कि दिव्या विश्व कप 2025 में भाग लेने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं, जिससे टूर्नामेंट से पहले उनकी जीत एक उत्साहजनक संकेत है।

प्रीतिस्मिता भोई ने युवा विश्व रिकॉर्ड बनाया, एशियाई युवा खेल 2025 में स्वर्ण पदक जीता

भारत की उभरती हुई भारोत्तोलन स्टार प्रीतिस्मिता भोई ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में एक नया युवा विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके और लड़कियों के 44 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

मुख्य आकर्षण

- प्रतियोगिता: लड़कियों का 44 किग्रा भारोत्तोलन वर्ग
- उपलब्धि: क्लीन एंड जर्क में 92 किग्रा भार उठाकर नया युवा विश्व रिकॉर्ड बनाया
- कुल भारोत्तोलन: 158 किग्रा (स्नैच + क्लीन एंड जर्क मिलाकर)

रोहन बोपन्ना ने दो दशक लंबे शानदार टेनिस करियर के बाद संन्यास लिया

पुरुष युगल में पूर्व विश्व नंबर 1, अनुभवी भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने आधिकारिक तौर पर पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उनके 20 साल के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत हो गया। उन्होंने आखिरी बार 2025 रोलेक्स पेरिस मास्टर्स में पेशेवर टेनिस खेला था, जहाँ उन्होंने अलेक्जेंडर बुब्लिक के साथ खेला था। 4 मार्च 1980 को कर्नाटक के कुर्ग में जन्मे बोपन्ना 2003 में पेशेवर बने और भारत के सबसे

सफल युगल विशेषज्ञों में से एक बन गए। इन वर्षों में, उन्होंने 26 एटीपी युगल खिताब जीते, जिसमें मैथ्यू एबडेन के साथ 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन भी शामिल है - इस जीत ने उन्हें एटीपी युगल रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बनने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी (43 वर्ष) बना दिया। बोपन्ना ने गैब्रिएला डाब्रोव्स्की (कनाडा) के साथ 2017 फ्रेंच ओपन (रोलैंड गैरोस) मिश्रित युगल खिताब भी जीता और दो यूएस ओपन युगल फाइनल में पहुँचे। कई वैश्विक खिलाड़ियों के साथ उनकी कोर्ट पर साझेदारी और एटीपी स्पर्धाओं में उनकी निरंतर उपस्थिति ने उन्हें अपने करियर में 539 टूर-स्तरीय जीत दिलाई।

वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में महिलाओं के फ़ाइनल में भारत ने जीत हासिल की

कुल नतीजे

- भारत ने 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते।
- भारत ने सभी 20 वेट कैटेगरी में कम से कम एक मेडल जीता।
- इवेंट ग्रेटर नोएडा में हुआ था।
- महिला बॉक्सिंग – 7 गोल्ड मेडल
- निकहत ज़रीन की लीडरशिप में भारतीय महिलाओं ने सात गोल्ड मेडल जीते।

गोल्ड मेडलिस्ट:

- निकहत ज़रीन (51kg)
- जैस्मिन लैम्बोरिया (57kg) – मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन
- मीनाक्षी हुड्डा (48kg) – मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन
- प्रीति पवार (54kg) – एशियन गेम्स ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट
- परवीन हुड्डा (60kg) – वर्ल्ड ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट
- अरुंधति चौधरी (70kg) – पूर्व यूथ वर्ल्ड चैंपियन
- नूपुर श्योराण (80kg)
- पुरुष बॉक्सिंग – 2 गोल्ड मेडल
- हितेश गुलिया (70kg) – गोल्ड जीता। सचिन सिवाच (60kg) – गोल्ड मेडल जीता।

टोक्यो डीफ्लंपिक्स में 25m पिस्टल इवेंट में भारत के अभिनव देशवाल ने गोल्ड जीता

भारत ने डीफ्लंपिक्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, शूटर अभिनव देशवाल ने टोक्यो में हुए 25m पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। यह चल रहे खेलों में शूटिंग में भारत का 15वां मेडल है।

इवेंट की खास बातें

- अभिनव देशवाल ने 44 के फाइनल स्कोर के साथ गोल्ड जीता, उन्होंने सेउंग ह्वा ली (साउथ कोरिया) को थोड़े अंतर से हराया, जिन्होंने 43 स्कोर किया।
- सेरही फॉर्मिन (यूक्रेन) ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता।
- एक और भारतीय शूटर, चेतन हनमंत सपकाल, 5वें स्थान पर रहे।
- देशवाल ने क्वालिफिकेशन राउंड में भी रिकॉर्ड प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने शानदार कंसिस्टेंसी दिखाई।

डीफ्लंपिक्स के बारे में

डीफ्लंपिक्स डेफ एथलीटों के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) से मान्यता प्राप्त एक इवेंट है। पहली बार 1924 में हुआ, यह ओलंपिक्स के बाद सबसे पुराने मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स में से एक है। इसमें हिस्सा लेने वाले एथलीट्स के बेहतर कान में कम से कम 55 dB सुनने की क्षमता कम होनी चाहिए। पैरालंपिक्स के उलट, डेफलंपिक्स में कॉम्पिटिशन के दौरान हियरिंग एड्स या कोक्लियर इम्प्लांट्स की इजाज़त नहीं होती है।

डेफलंपिक्स में भारत

भारत डेफलंपिक्स में लगातार बेहतर कर रहा है, खासकर शूटिंग, बैडमिंटन, कुश्ती और एथलेटिक्स में। भारत ने ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में 2022 डेफलंपिक्स में रिकॉर्ड 16 मेडल जीते। इस इवेंट में शूटिंग भारत का सबसे मज़बूत मेडल जीतने वाला डिसिप्लिन बना हुआ है।

इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड जीता

इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो, श्रीलंका में हुए पहले विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड को जीतकर इतिहास रच दिया। यह जीत इंडिया के ब्लाइंड स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में एक अहम मील का पत्थर है।

मैच हाइलाइट्स

- इंडिया ने फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया।
- इंडिया के पहले फील्डिंग करने के फैसले के बाद नेपाल ने 114/5 का स्कोर बनाया।
- इंडिया ने 12.1 ओवर में टारगेट को सफलतापूर्वक चेज कर लिया।
- इंडिया पूरे टूर्नामेंट में बिना हारे रहा।

टूर्नामेंट का रास्ता

इंडिया ने लीग स्टेज और सेमीफाइनल में श्रीलंका, USA, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को हराया। नेपाल एक कड़े मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा।

ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में

- ब्लाइंड क्रिकेट को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट लिमिटेड (WBCL) दुनिया भर में चलाता है।
- भारत में, इसे क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (CABI) सपोर्टनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के तहत मैनेज करता है।

खिलाड़ियों को इस तरह बांटा गया है:

1. B1 (पूरी तरह से ब्लाइंड)
2. B2 (थोड़ा ब्लाइंड)
3. B3 (कम नज़र)

टीमों में कम से कम B1 खिलाड़ियों की एक तय संख्या होनी चाहिए ताकि सब कुछ शामिल हो सके।

ब्लाइंड क्रिकेट में भारत की उपलब्धियां
भारत ने पहले ये जीते हैं:

- मेन्स ब्लाइंड क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप – 2014, 2018
- मेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप – 2012, 2017
- यह दुनिया भर में पहला विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल है।

क्रिकेट गवर्नेंस फैक्ट्स:

- BCCI भारत में मेनस्ट्रीम क्रिकेट को कंट्रोल करता है, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट BCCI के अंडर नहीं है—इसे CABI जैसी अलग बॉडी चलाती हैं।
- श्रीलंका और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट में पारंपरिक रूप से मज़बूत कॉम्पिटिटर हैं।
- ब्लाइंड क्रिकेट में साउंड-बेस्ड ट्रैकिंग के लिए एक बड़ी, शोर वाली बॉल का इस्तेमाल होता है।

लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन्स सिंगल्स टाइटल जीता

इंडियन बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने सिडनी में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 (मेन्स सिंगल्स) का टाइटल जीत लिया है, जो इस साल का उनका पहला टाइटल है और इंटरनेशनल बैडमिंटन सर्किट में उनकी फॉर्म में वापसी का एक अहम मौका है।

2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन (बैडमिंटन)

- एडिशन: 34वां
- लेवल: सुपर 500
- टोटल प्राइज़ मनी: US$475,000
- जगह: सिडनी, ऑस्ट्रेलिया

2025 चैंपियंस:

- मेन्स सिंगल्स: लक्ष्य सेन (इंडिया)
- विमेन्स सिंगल्स: एन से-यंग (साउथ कोरिया)
- मेन्स डबल्स: रेमंड इंद्रा और निकोलस जोकिन {इंडोनेशिया}
- विमेन्स डबल्स: रेचल एलेसिया रोज़ और फेबी सेटियानिंग्रम {इंडोनेशिया}
- मिक्स्ड डबल्स: चेन टैंग जी और तोह ई वेई {मलेशिया}

भारत ने चीनी ताइपे को हराकर लगातार दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता

भारत ने लगातार दो वर्ल्ड कप टाइटल जीते
भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराया। यह भारत की लगातार दूसरी महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीत है।उनका लगातार दबदबा कबड्डी में भारत की लंबे समय से चली आ रही टैक्टिकल और फिजिकल बेहतरी को दिखाता है, यह एक ऐसा खेल है जो फुर्ती, स्ट्रैटेजी और कोऑर्डिनेटेड रेडिंग-डिफेंस बैलेंस पर आधारित है।

भारत का ट्रॉफी तक का सफर
भारत ने ग्रुप-स्टेज के सभी मैच आसानी से जीते।
सेमीफाइनल में ईरान को 33-21 से हराकर टॉप क्लैश में पहुंचा।
पूरे मैच में मजबूत डिफेंसिव कोऑर्डिनेशन और तेज रेडिंग ट्रांजिशन बनाए रखा।

चीनी ताइपे का शानदार सफर
अपने ग्रुप में भी बिना हारे रहा।
सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 25-18 से हराकर भारत के साथ एक हाई-स्टेक्स फाइनल तय किया।

दुनिया भर में बढ़ रहा हिस्सा
टूर्नामेंट में कुल 11 देशों ने हिस्सा लिया।

महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025

- तारीखें: 15 – 25 नवंबर 2025
- एडमिनिस्ट्रेटर: बांग्लादेश कबड्डी फेडरेशन
- मंज़ूरी: इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन (IKF)
- होस्ट: ढाका, बांग्लादेश
- चैंपियन: इंडिया
- फर्स्ट रनर-अप: चाइनीज़ ताइपे
- सेकंड रनर-अप: बांग्लादेश

इटली ने अपना चौथा डेविस कप टाइटल जीता

इटली ने लगातार तीसरा डेविस कप टाइटल जीतकर इतिहास रचा | इटली ने बोलोग्ना में फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर अपना चौथा और लगातार तीसरा डेविस कप जीता — यह 1970 के दशक की शुरुआत के बाद से पहली बार हुआ था।

स्टार्स के बिना जीत
अद्भुत बात यह है कि टॉप खिलाड़ियों जैनिक सिनर और लोरेंजो मुसेट्टी की गैरमौजूदगी के बावजूद इटली ने टाइटल जीता, जिससे टीम की गहराई और मज़बूती का पता चलता है। इसी तरह, स्पेन अपने स्टार कार्लोस अल्काराज़ के बिना खेला।

एक ऐतिहासिक हैट-ट्रिक
इस जीत से इटली मॉडर्न डेविस कप युग (चैलेंज राउंड के बाद) में लगातार तीन टाइटल जीतने वाला पहला देश बन गया है — यह सिलसिला 1968-72 में U.S. के बाद से नहीं देखा गया था।

होम ग्लोरी
बोलोग्ना में घरेलू ज़मीन पर जीत ने इस पल को और भी खास बना दिया, जब इटली की भीड़ ने सपोर्ट में ज़ोरदार तालियां बजाईं।

डेविस कप

- खेल: टेनिस
- स्थापना: 1900
- संस्थापक: ड्वाइट एफ. डेविस
- देश: ITF सदस्य देश
- सबसे हाल के चैंपियन: इटली (चौथा टाइटल)
- सबसे ज़्यादा टाइटल: यूनाइटेड स्टेट्स (32 टाइटल)

निधन

मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन

हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया।

- करियर: 7 दशकों तक फिल्मों में एक्टिव, इंडियन सिनेमा की शुरुआती और सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं।
- डेब्यू: नीचा नगर (1946) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की — यह कान्स फिल्म फेस्टिवल (ग्रांड प्रिक्स / पाल्मे डी'ओर) में टॉप अवॉर्ड जीतने वाली पहली इंडियन फिल्म थी।
- गोल्डन एरा में योगदान: दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया।
- रोल्स में बदलाव: 1960 के दशक के आसपास कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट हुईं लेकिन पहचान मिलती रही।
- आखिरी फिल्म: लाल सिंह चड्ढा (2022) — 95 साल की उम्र में एक्टिंग की, जिससे इस काम के प्रति डेडिकेशन दिखा।
- जन्म: 24 फरवरी 1927 को लाहौर में जन्मीं; किन्नेयर्ड कॉलेज की एल्युम्ना।

अवार्ड्स:

- बिराज बहू (1954) के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड
- फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (2015)

जानी-मानी एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। सुलक्षणा एक मशहूर म्यूजिकल फैमिली से थीं, वह मशहूर म्यूजिक कंपोजर जोड़ी जतिन-ललित की बहन थीं। वह 1970 और 1980 के दशक की कई हिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग और कई हिंदी फिल्मी गानों में अपनी मधुर आवाज देने के लिए जानी जाती थीं।

एक्टिंग करियर

- डेब्यू फिल्म: उलझन (1975), संजीव कुमार के साथ। उन्होंने हेरा फेरी (1976), अपनापन (1977), खानदान (1979), चेहरे पे चेहरा (1981), धर्म कांटा (1982), वक़्त की दीवार (1981) जैसी बड़ी हिंदी फ़िल्मों में काम किया।
- उनकी आखिरी बड़ी फ़िल्म दो वक़्त की रोटी (1988) थी जिसमें उनके साथ फिरोज़ खान, रीना रॉय और संजीव कुमार थे।
- अपनी शानदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और इमोशनल गहराई के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने अपने समय के बड़े एक्टर्स — जीतेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया।

अवार्ड रिकग्निशन:

- फ़िल्म संकल्प के गाने "तू ही सागर है तू ही किनारा" के लिए बेस्ट फ़ीमेल प्लेबैक सिंगर (1975) का फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड जीता।

DNA डबल हेलिक्स के को-डिस्कवर, नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 साल की उम्र में निधन हो गया

जेम्स वॉटसन, मशहूर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्होंने 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर DNA के डबल-हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी, का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। इस खोज ने जेनेटिक्स और हेरेडिटी की समझ को बदल दिया, जिसके लिए वॉटसन, क्रिक और मौरिस विल्किंस को 1962 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला। वॉटसन का जन्म शिकागो (1928) में हुआ था, उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम किया, जहाँ यह ऐतिहासिक खोज की गई थी। टीम के नतीजों को रोज़लिंड फ्रैंकलिन की एक्स-रे डिफ्रैक्शन इमेज से सपोर्ट मिला, जिससे डबल-हेलिक्स मॉडल के लिए ज़रूरी सबूत मिले। वॉटसन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर और बाद में कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी

(CSHL) के डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जिससे इसे जेनेटिक रिसर्च के लिए एक प्रमुख सेंटर बनाने में मदद मिली।

अतिरिक्त तथ्य:

- DNA का स्ट्रक्चर 1953 में नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ था।
- इस खोज ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट (HGP) की नींव रखी — जिसे 1990 में लॉन्च किया गया और 2003 में पूरा किया गया, जिसमें सभी ह्यूमन जीन की पहचान की गई।
- रोज़लिंड फ्रैंकलिन के योगदान को मरणोपरांत पहचान मिली; उन्हें नोबेल प्राइज़ शेयर नहीं किया गया क्योंकि यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है।
- कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी (CSHL), जहाँ वॉटसन ने डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस और क्वांटिटेटिव बायोलॉजी में एक लीडिंग रिसर्च सेंटर है।

वॉटसन के कोलेबोरेटर, फ्रांसिस क्रिक ने बाद में न्यूरोसाइंस और कॉन्शसनेस स्टडीज़ पर काम किया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ हर साल स्वीडन का कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है।

प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ और फिल्म निर्माता एम. नाइट श्यामलन के पिता, नेल्लियट सी. श्यामलन का अमेरिका में निधन

डॉ. श्यामलन का 88 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया।

पेशेवर पृष्ठभूमि

वे एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अमेरिका में अभ्यास किया और मूल रूप से केरल के नेल्लियट परिवार से थे।

वे फिल्म निर्माता एम. नाइट श्यामलन के पिता हैं।

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी. हिंदुजा का 85 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन और चार हिंदुजा भाइयों में से एक, गोपीचंद पी. हिंदुजा का 85 साल की उम्र में लंदन के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। प्यार से "GP" के नाम से मशहूर, उन्होंने फैमिली बिज़नेस को एक मामूली इंडो-मिडिल ईस्ट ट्रेडिंग फर्म से एक ग्लोबल ग्रुप में बदलने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी कई सेक्टर में अलग-अलग तरह की मौजूदगी थी।

हिंदुजा ग्रुप के बारे में:

- शुरू किया: परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में मुंबई (तब बॉम्बे) में।
- हेडक्वार्टर: लंदन, यूनाइटेड किंगडम।

अवार्ड और पहचान:

कई बिज़नेस मैगज़ीन ने टॉप 100 ग्लोबल बिज़नेस लीडर्स में लिस्ट किया है। ग्लोबल इंडस्ट्री और भारत-ब्रिटिश रिश्तों में उनके योगदान के लिए कई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं। हिंदुजा भाइयों को बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट और रोज़गार पैदा करके भारत-UK बिज़नेस पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए भी पहचान मिली।

US के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी का 84 साल की उम्र में निधन

अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी का 84 साल की उम्र में निमोनिया और कार्डियक और वैस्कुलर बीमारी से हुई दिक्कतों की वजह से निधन हो गया।

पॉलिटिकल करियर:

वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर व्हाइट हाउस में आने से पहले, रिचर्ड ब्रूस "डिक" चेनी ने व्योमिंग कांग्रेसमैन (1979–1989) के तौर पर और बाद में प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के अंडर U.S. सेक्रेटरी ऑफ़ डिफेंस (1989–1993) के तौर पर काम किया। डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर, चेनी ने 1991 के गल्फ वॉर के दौरान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की देखरेख में अहम भूमिका निभाई, जिसने इराकी सेना को कुवैत से सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया।

वाइस प्रेसिडेंसी (2001–2009):

चेनी ने प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के अंडर दो टर्म (2001–2009) तक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद वे U.S. नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के एक बड़े आर्किटेक्ट थे, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी बनाना और "वॉर ऑन टेरर" स्ट्रैटेजी शामिल है। उन्होंने 2003 में इराक पर U.S. हमले का भी ज़ोरदार सपोर्ट किया था, जिसमें मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का ज़िक्र किया गया था — जो कभी नहीं मिले — इस कदम से दुनिया भर में विवाद खड़ा हो गया था।

मशहूर मराठी एक्ट्रेस दया डोंगरे का 85 साल की उम्र में निधन

मराठी फिल्म और थिएटर की मशहूर एक्ट्रेस दया डोंगरे का 85 साल की उम्र में उम्र से जुड़ी बीमारियों की वजह से निधन हो गया। उनका जन्म 11 मार्च 1940 को अमरावती, महाराष्ट्र में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ा था — उनकी माँ, यमुनाताई मोदक भी एक एक्ट्रेस थीं। दया डोंगरे का शुरू में म्यूज़िक में रुझान था, लेकिन अपनी जवानी में ऑल इंडिया रेडियो सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीतने के बाद वह मशहूर हुईं। बाद में उन्होंने एक्टिंग पर ध्यान दिया और नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) से फॉर्मल ट्रेनिंग ली। अपने दशकों लंबे करियर में, उन्होंने मराठी थिएटर, टेलीविज़न और फिल्मों में काम किया, और "तुझी माझी जोड़ी जमली रे," "नंदा सौख्या भरे," "याचसथी केला होता अट्टाहास," और "लेकुरे उदंड जाली" जैसे पॉपुलर सीरियल में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाई। उन्हें उनकी वर्सेटाइल काबिलियत और मराठी परफॉर्मिंग आर्ट्स में गहरे योगदान के लिए सराहा गया।

नॉर्थ कोरिया के पूर्व सेरेमोनियल हेड ऑफ़ स्टेट किम योंग नाम का 97 साल की उम्र में निधन

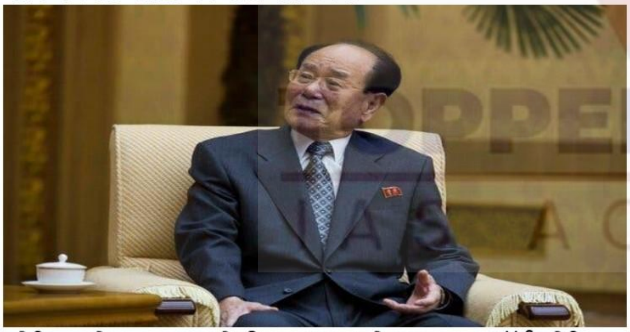

कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (KCNA) के अनुसार, नॉर्थ कोरिया के पूर्व सेरेमोनियल हेड ऑफ़ स्टेट और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पॉलिटिकल लोगों में से एक, किम योंग नाम का 97 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण निधन हो गया।

पद:

- सुप्रीम पीपल्स असेंबली (SPA) के प्रेसिडियम के प्रेसिडेंट — नॉर्थ कोरिया के सेरेमोनियल हेड ऑफ़ स्टेट
- कार्यकाल: 1998–2019
- पूर्व विदेश मंत्री और रूलिंग वर्कर्स पार्टी ऑफ़ कोरिया के सीनियर डिप्लोमैट।

फ्रेंच ओलंपियन चार्ल्स कॉस्टे, दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 101 साल की उम्र में गुज़र गए

फ्रेंच साइकिलिस्ट चार्ल्स कॉस्टे, दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 101 साल की उम्र में गुज़र गए। कॉस्टे ने 1948 के लंदन ओलंपिक्स में पुरुषों की टीम परस्यूट इवेंट में पियरे एडम, सर्ज ब्लूसन और फर्नांड डेकानाली के साथ गोल्ड मेडल जीता था। 1924 में फ्रांस के विलेफ्रेंच-सुर-मेर में जन्मे कॉस्टे ने युद्ध के बाद की पीढ़ी के एथलीटों को रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्लोबल स्पोर्ट्स को फिर से ज़िंदा किया। 2 जनवरी 2025 को हंगेरियन जिमनास्ट एग्नेस केलेटी (उम्र 103) की मौत के बाद वह दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक चैंपियन बन गए थे। कॉस्टे 2024 पेरिस ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी में टॉर्चबियरर में से एक थे, जो ओलंपिक मूवमेंट की हमेशा रहने वाली भावना का प्रतीक है। ओलंपिक में अपनी जीत के अलावा, वह एक मशहूर रोड साइक्लिस्ट भी थे, जिन्होंने 1949 का ग्रैंड प्रिक्स डेस नेशंस जीता था, जो एक मशहूर 140-km का टाइम ट्रायल था, जहाँ उन्होंने इटली के साइकिलिंग लेजेंड फॉस्टो कोप्पी को हराया था, जो टूर डी फ्रांस और गिरो डी'इटालिया चैंपियन थे।

वरिष्ठ ब्रिटिश अभिनेत्री प्रुनेला स्केल्स का 93 वर्ष की आयु में निधन

प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री प्रुनेला स्केल्स, जिन्हें बीबीसी के क्लासिक सिटकॉम "फॉल्टी टावर्स" में सिबिल फॉल्टी की अपनी प्रतिष्ठित भूमिका के लिए जाना जाता है, का 93 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। स्केल्स 2013 से संवहनी मनोभ्रंश से पीड़ित थीं, जिसके कारण उन्होंने अपने 70 साल के प्रतिष्ठित अभिनय करियर से संन्यास ले लिया।

संवहनी मनोभ्रंश के बारे में:

मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में कमी के कारण होने वाला एक सामान्य प्रकार का मनोभ्रंश, जो अक्सर स्ट्रोक या संवहनी रोग के कारण होता है। इससे स्मृति हानि, भ्रम और तर्क क्षमता में कमी आती है। अल्ज़ाइमर के विपरीत, इसके लक्षण अक्सर छोटे स्ट्रोक के बाद अचानक प्रकट होते हैं।

दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन

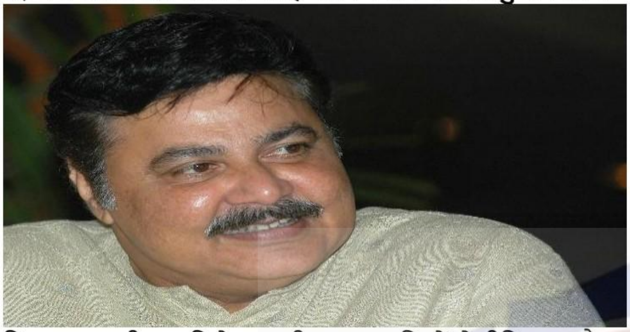

दिग्गज भारतीय अभिनेता सतीश शाह, जिन्हें टेलीविजन और फिल्मों में उनकी अविस्मरणीय हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, का 25 अक्टूबर, 2025 को 74 वर्ष की आयु में मुंबई में किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय हास्य और टेलीविजन के एक युग का अंत हो गया। शाह ने लोकप्रिय टीवी सिटकॉम "साराभाई वर्सेस साराभाई" में इंद्रवदन साराभाई की भूमिका से अपार लोकप्रियता हासिल की, जो 2000 के दशक के सबसे लोकप्रिय भारतीय हास्य कार्यक्रमों में से एक बन गया। इससे पहले, उन्होंने 1980 के दशक की हिट फिल्म "ये जो है ज़िंदगी" से प्रसिद्धि पाई, जिसमें उनकी बेजोड़ हास्य टाइमिंग और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया था।

मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का निधन

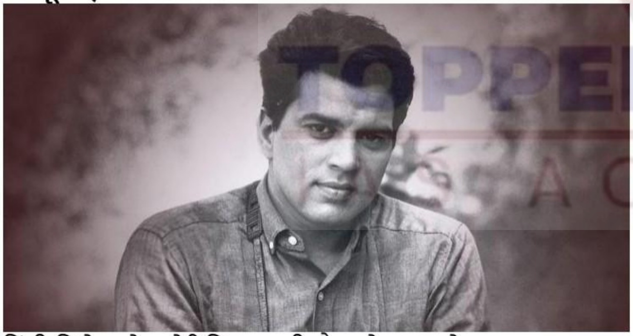

हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल "ही-मैन" के नाम से मशहूर मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया, जहाँ परिवार के सदस्यों और फिल्म इंडस्ट्री के साथियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

65 साल का शानदार करियर

धर्मेंद्र का भारतीय सिनेमा में सबसे लंबा और सबसे सफल करियर था। 300 से ज़्यादा फिल्मों के साथ, उनके नाम हिंदी फिल्म इतिहास में सबसे ज़्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड है। उन्हें बॉलीवुड के सबसे महान और सबसे हैंडसम स्टार्स में से एक माना जाता था।

स्टारडम तक का सफ़र

1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू करने के बाद, वह 1960 के दशक के बीच में आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, और आए दिन बहार के जैसी फिल्मों से मशहूर हुए। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने बाद में उन्हें "इंडिया का ही-मैन" का टाइटल दिलाया।

ब्लॉकबस्टर का दौर

1960 के दशक के आखिर से लेकर 1980 के दशक तक, धर्मेंद्र ने आँखें, शिकार, सीता और गीता, जुगनू, यादों की बारात, मेरा गाँव मेरा देश, शोले, प्रतिज्ञा, धरम वीर, गुलामी, हुकूमत और आग ही आग जैसी कई बड़ी हिट फ़िल्में दीं। उन्हें अनुपमा, बंदिनी, हकीकत, सत्यकाम, चुपके चुपके, द बर्निंग ट्रेन, दिल्लगी और दूसरी फ़िल्मों में उनके काम के लिए भी तारीफ़ मिली।

बाद के रोल और पहचान

1990 के दशक के आखिर से, उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ़ इन अ मेट्रो, अपने, जॉनी गद्दार, यमला पगला दीवाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फ़िल्मों में जाने-माने कैरेक्टर रोल किए। उन्हें 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला।

पॉलिटिकल करियर

धर्मेंद्र ने 15वीं लोकसभा में राजस्थान के बीकानेर चुनाव क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए सांसद के तौर पर भी काम किया, BJP सदस्य के तौर पर।

परिवार और विरासत

धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पत्नियां प्रकाश कौर और एक्ट्रेस हेमा मालिनी हैं। वे अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं जिसे दर्शकों, फिल्ममेकर्स और कलाकारों की पीढ़ियों ने संजोकर रखा है।

अन्य जानकारी:

- पॉलिटिकल पार्टी: भारतीय जनता पार्टी
- पति: प्रकाश कौर (शादी 1954) और हेमा मालिनी (शादी 1980)
- अवार्ड्स: पद्म भूषण (2012)
- निकनेम: ही-मैन; गरम धरम

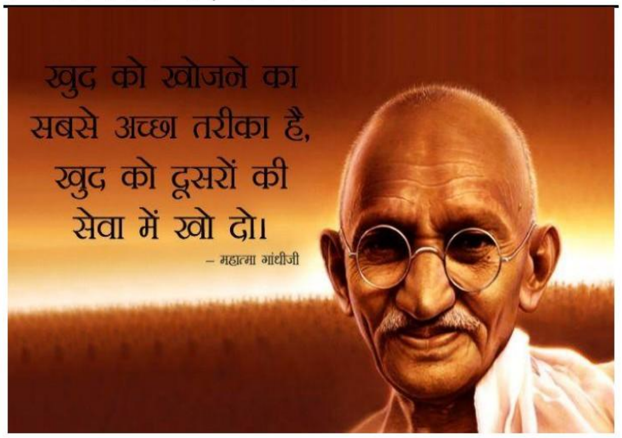

माह के महत्वपूर्ण दिन

दिवस	मनाया जाता है	थीम/उद्देश्य
1 दिसम्बर	विश्व एड्स दिवस	रुकावटों पर काबू पाना, AIDS के जवाब में बदलाव लाना
2 दिसम्बर	राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस	औद्योगिक आपदा को नियंत्रित करना तथा प्रदूषण के स्तर को कम करना।
3 दिसम्बर	विश्व विकलांग दिवस	समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना।
4 दिसम्बर	भारतीय नौसेना दिवस	देश के लिए भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को पहचानना
5 दिसम्बर	विश्व मृदा दिवस	स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी
7 दिसम्बर	सशस्त्र सेना झंडा दिवस	उन शहीदों और वर्दीधारियों का सम्मान करना जो देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर बहादुरी से लड़े।
9 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस	भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना: कल की ईमानदारी को आकार देना
10 दिसम्बर	मानव अधिकार दिवस	हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें
11 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस	ग्लेशियर पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं
14 दिसम्बर	विश्व/राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता लाना
16 दिसम्बर	विजय दिवस	पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने हेतु
18 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस	प्रवासी, आशा के मिशनरी
19 दिसम्बर	गोवा मुक्ति दिवस	यह 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने की याद दिलाता है।
20 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस	उस दिन को मनाने के लिए जिस दिन UNGA ने 20 दिसंबर 2005 को मौलिक और सार्वभौमिक मूल्यों में से एक के रूप में एकजुटता की पहचान की थी
22 दिसम्बर	राष्ट्रीय गणित दिवस	महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने हेतु
23 दिसम्बर	किसान दिवस	23 दिसंबर 1902 को चौधरीचरण सिंह की जयंती मनाने हेतु, जो भारत के 5वें प्रधान मंत्री थे।
25 दिसम्बर	सुशासन दिवस (भारत)	पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने हेतु

पुस्तकें एवं लेखक

पुस्तक: विंग्स ऑफ़ वैलोर

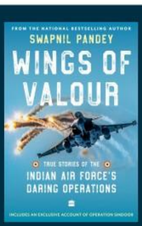

लेखक: स्वप्निल पांडे
बारे में: इस पुस्तक में लेखक स्वप्निल पांडे, वायुसेना के पायलटों, क्रू, पूर्व सैनिकों और गरुड़ कमांडो से विभिन्न एयरबेसों पर मुलाकात के बाद, विंग्स ऑफ़ वैलोर में उनकी प्रेरणादायक यात्राओं का वर्णन करते हैं।

पुस्तक: अबव एंड बियॉन्ड

लेखक: शिव कुमार मोहनका
बारे में: यह पुस्तक हवाई यात्रा के पीछे के विज्ञान पर प्रकाश डालती है, जैसे कि ऊँचाई पर भोजन का स्वाद अलग क्यों होता है, और यात्रियों के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करती है।

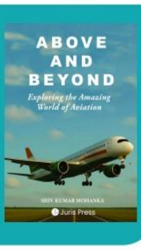

पुस्तक: मैंने कैंसर को जीत लिया

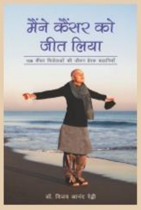

लेखक: डॉ. पी. विजय आनंद रेड्डी
बारे में: यह पुस्तक कैंसर से बचे लोगों की 108 प्रेरक कहानियाँ प्रस्तुत करती है, जिनमें से प्रत्येक असाधारण साहस, दृढ़ता और निराशा पर आशा की विजय को दर्शाती है।

पुस्तक: रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट II: शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स

लेखक: जनरल अनिल चौहान
बारे में: यह पुस्तक भारत के सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु एक व्यापक और भविष्योन्मुखी खाका प्रस्तुत करती है।

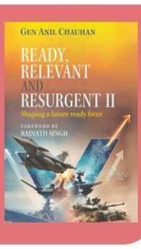

पुस्तक: शिवम शुभम: एक युगल की जीवनी

लेखक: बी.के. हरिनारायणन
बारे में: यह पुस्तक एक ऐसे युगल का उत्सव मनाती है जिनके प्रेम, अनुशासन और समर्पण ने संगीत को अमरता प्रदान की और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी एक शाश्वत राग की तरह गूंजती रहती है।

TOPPERS CLUB IAS ACADEMY

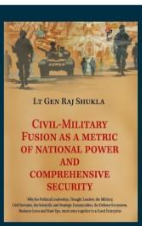

पुस्तक: राष्ट्रीय शक्ति और व्यापक सुरक्षा के एक मानक के रूप में नागरिक-सैन्य संलयन

लेखक: लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला (सेवानिवृत्त)
बारे में: यह पुस्तक चीन के सैन्य एकीकरण (MCF), अमेरिकी अनुभवों और भारत के पथ का विश्लेषण करती है, और सैन्य-सैन्य एकीकरण को भारत के सामरिक और सैन्य भविष्य के एक प्रमुख चालक के रूप में रेखांकित करती है।

पुस्तक: मोदी का मिशन

लेखक: बर्जिस देसाई
बारे में: यह पुस्तक भारत की सामूहिक चेतना को बढ़ाने और पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी शासन की शुरुआत करने के मोदी के मिशन की पड़ताल करती है।

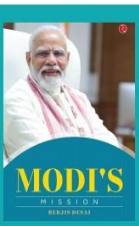

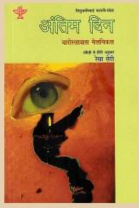

पुस्तक: अंतिम दिन

लेखक: रेखा सेठी
बारे में: यह उपन्यास पहचान, परिवर्तन और सांस्कृतिक बदलावों की पड़ताल करता है, और पाठकों को व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास और मानवीय अनुभवों की जटिलताओं पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है।

पुस्तक: ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ इन्डिआज़ डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान

लेखक: लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लों (सेवानिवृत्त)
बारे में: यह पुस्तक चार दिवसीय युद्ध का वर्णन करती है, जिसमें भारत के सैन्य कौशल, खुफिया जानकारी और कूटनीतिक रणनीति का प्रदर्शन किया गया है जिसने स्थिरता सुनिश्चित की और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया।

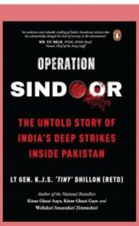

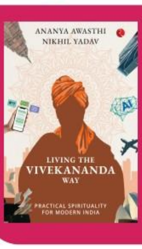

पुस्तक: लिविंग द विवेकानंद वे

लेखक: डॉ. अनन्या अवस्थी और डॉ. निखिल यादव
बारे में: यह पुस्तक दर्शाती है कि स्वामी विवेकानंद का निर्भयता, एकता और करुणा का संदेश केवल दर्शन नहीं, बल्कि आज की दुनिया की अराजकता से बचने का एक तरीका है।

TOPPERS CLUB
IAS ACADEMY

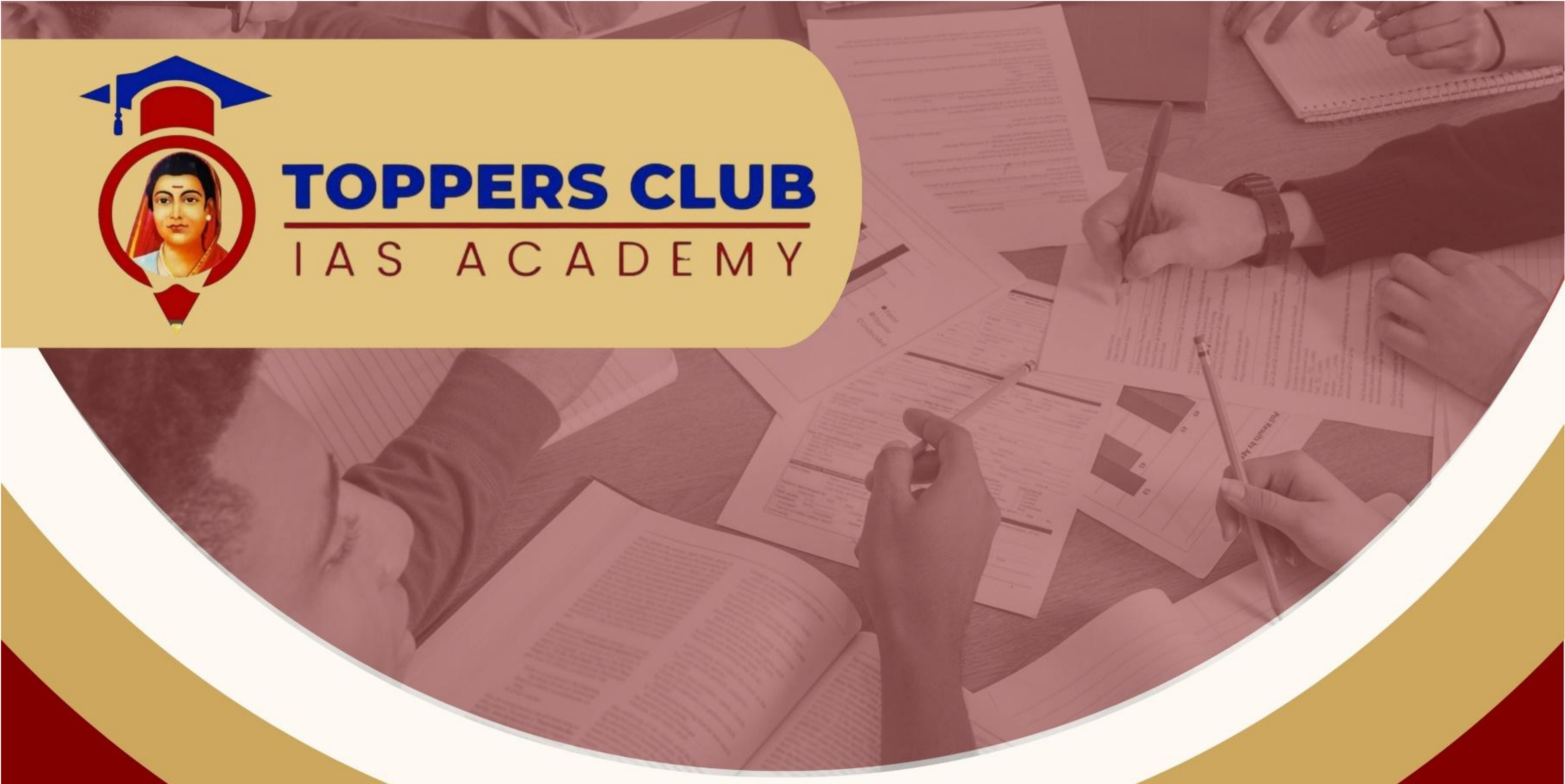

Monthly

CURRENT AFFAIRS

By - Toppers Club

Staying updated with current affairs is crucial for academic and professional growth. It enhances knowledge, sharpens critical thinking, and improves decision-making. Awareness of global issues aids in competitive exams, essays, and interviews. Beyond academics, it reflects adaptability and curiosity—key traits in today's fast-changing world. Being informed broadens perspective, builds confidence, and opens up new opportunities.

+91 6388671098
dpsctc@gmail.com
Toppers CLUB IAS
www.topperclubiasacademy.in
Sec 12 HNO 687 MUNSHI PULIYA INDIRA NAGAR LUCKNOW 226016